चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

1986 से प्रकाशित

दिल्ली, 27 दिसंबर 2010–02 जनवरी 2011

मूल्य 5 रुपये

खा गए खाद्यान्न

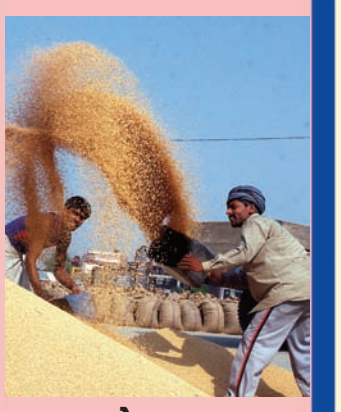

पेज-5

कब ख़त्म होगी बंधुआ मज़दूरी

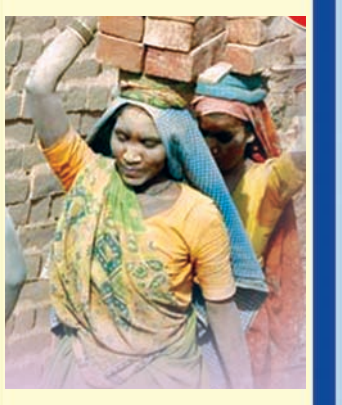

पेज-6

साई की महिमा

पेज-12

2010 का लेखा-जोखा

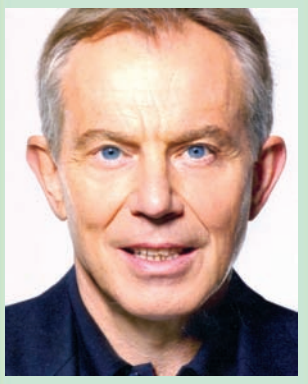

पेज-13

आरटीआई संशोधन

यह भ्रष्टाचार को बचाने की साज़िश है

सूचना का अधिकार क़ानून (आरटीआई) स्वतंत्र भारत में बना पहला ऐसा क़ानून है, जिसने आम आदमी को जानने और जीने का अधिकार दिया. उस व्यवस्था से सवाल पूछने की ताक़त दी, जिसकी नज़र में आम आदमी की कोई गरिमा नहीं है. सत्ता और व्यवस्था में बैठे लोगों को पहली बार लगा कि कोई उनसे भी सवाल पूछ सकता है. धीरे धीरे सवाल पूछने की यही ताक़त एक मूक क्रांति में परिवर्तित होने लगी. एक ऐसी क्रांति, जो लोकतांत्रिक ढंग से व्यवस्था में लगी जंग को साफ कर सकती है. ज़ाहिर है, शासकों को ऐसी बातें रास नहीं आतीं. सो, इस क़ानून की धार को कुंद करने की तैयारी चल रही है. ऐसे में कांग्रेस को अब बताना चाहिए कि उसका हाथ किसके साथ है?

शशि शेखर

बात 2006 की है. सूचना क़ानून को लागू हुए अभी कुछ ही महीने हुए थे. बिहार के झंझारपुर का एक रिक्शाचालक मजलूम इंदिरा आवास योजना के तहत आवेदन देता है. अब खंड विकास अधिकारी उसके आवेदन को पास करने के लिए 5 हज़ार रुपये की रिश्वत मांगता है. अनपढ़ और ग़रीब मजलूम तीन साल से बीडीओ कार्यालय में धक्के खा रहा था, क्योंकि 5 हज़ार रुपये घूस देना उसके लिए संभव नहीं था. इसी बीच वह एक सामाजिक कार्यकर्ता अशोक सिंह से मिला, जिन्होंने उसे सूचना के अधिकार के तहत सूचना मांगने का आवेदन बनाकर दिया. आवेदन डालने के एक सप्ताह के भीतर मजलूम को 15 हज़ार रुपये का चेक मिल गया. एक महीने बाद जब मजलूम बाक़ी राशि लेने बीडीओ दफ्तर पहुंचा तो एक बार फिर उससे रिश्वत की मांग की गई. इस बार अनपढ़ मजलूम ने बीडीओ से कहा कि अगर मेरा पैसा नहीं दोगे तो फिर से सोचना (सूचना) की अर्जी लगा दूंगा. नतीजतन, बिना एक पैसे घूस दिए मजलूम को पूरी राशि मिल गई. अनपढ़ मजलूम की अर्जी ने साबित कर दिया कि एक मौन क्रांति का आगाज़ हो चुका है. आज देश भर में मजलूम जैसे हज़ारों लोग, जो अनपढ़ या कम पढ़े-लिखे हैं, सूचना का अधिकार क़ानून के सहारे इस मौन क्रांति को आकार देने में जुटे हुए हैं. लेकिन, व्यवस्था में बैठे नेताओं और नौकरशाहों को यह बात हज़म नहीं हो रही है कि कल तक जिन लोगों के लिए वे माई-बाप हुआ करते थे, वही आज उनसे आंख मिलाकर सवाल पूछ रहे हैं. इस देश में आज भी अंग्रेजों के बनाए हुए कई क़ानून गुलामी की याद दिलाते हैं. आज़ादी के 64 साल बाद भी ऐसे क़ानूनों को हटाने, बदलने या उनमें संशोधन की ज़रूरत देश के कर्णधारों को महसूस नहीं होती, लेकिन 5 साल पुराने आरटीआई क़ानून उनकी आंखों में ऐसा चुभ रहा है कि जिसे देखो, वही इसमें संशोधन की बात कर रहा है. नेता, नौकरशाह और जज भी.

अभी केंद्र सरकार के कार्मिक विभाग में आरटीआई नियमों में संशोधन की तैयारी चल रही है. संशोधन भी ऐसे, ताकि देश के ग़रीब, अनपढ़ और कम पढ़े-लिखे लोगों के लिए यह क़ानून बेमानी हो जाए. प्रस्तावित संशोधन के मुताबिक़, एक आरटीआई आवेदन को 250 शब्दों में ही सीमित करना होगा. एक आवेदन में एक ही विषय शामिल करना होगा. इसके अलावा सूचना उपलब्ध कराने के लिए जो डाक ख़र्च होगा, वह भी आवेदक को ही देना होगा. साथ ही किसी ऐसी सूचना, जिसके लिए किसी विभाग को बाहर से कोई मशीन या उपकरण किराए पर लेना पड़ता है तो उसका ख़र्च भी आवेदक को ही उठाना पड़ेगा. मसलन, किसी सड़क की गुणवत्ता जांच के संबंध में कोई आवेदक सूचना चाहता है तो इसमें जो मशीनी ख़र्च आएगा, उसे आवेदक को ही अदा करना पड़ेगा. यही नहीं, कोई आवेदक अपील करना चाहता है तो उसे इसके लिए एक ख़ास प्रारूप का इस्तेमाल करना होगा और कई सारे दस्तावेज लगाने होंगे. ज़ाहिर है, अगर ये संशोधन स्वीकार कर लिए जाते हैं तो एक ऐसा आवेदक, जो ग़रीब या कम पढ़ा-लिखा या अशिक्षित है, उसके लिए यह क़ानून किसी काम का नहीं रह जाएगा. चाहे वह सोनीपत ज़िले के सिलारपुर मेहता गांव की साठ वर्षीय सुमित्रा देवी हों, जिन्होंने आरटीआई की मदद से गरीब स्कूली लड़कियों के लिए साइकिल वितरण की सरकारी योजना

(शेष पृष्ठ 2 पर)

“आरटीआई क़ानून में कुछ खामियां हैं, जिनका बड़े स्तर पर दुरुपयोग हो रहा है. यह आरटीआई क़ानून के अनेक प्रावधानों में अंतरावलोकन का समय है. (अक्टूबर 2010 में दिया गया बयान) (सितंबर 2009 में मुख्य न्यायाधीश ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भेजे अपने पत्र में न्यायपालिका को आरटीआई क़ानून के दायरे से बाहर रखने का आग्रह किया था. तर्क यह कि इस क़ानून की वजह से न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है.)”

के जी बालाकृष्णन
चेयरमैन, एनएचआरसी

“250 शब्दों की सीमा तय करना एक बड़ी समस्या है. इस देश की एक बड़ी आबादी अशिक्षित है, वह कैसे इतने कम शब्दों में अपनी बात रख पाएगी? सूचना शुल्क में जो बदलाव की बात हो रही है, उससे तो पीआईओ अपनी मर्जी से सूचना जुटाने में लगी मेहनत और समय का भी शुल्क वसूलना शुरू कर देंगे. पहले भी सूचना उपलब्ध कराने के नाम पर आवेदक से पीआईओ का वेतन मांगा जाता रहा है. सरकार को हमारी मांगें नहीं दिख रही हैं, उल्टे वह जानबूझ कर इस क़ानून को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है.”

अरविंद केजरीवाल,
रेमन मैगसेसे अवार्ड विजेता एवं आरटीआई कार्यकर्ता.

“मैं समझता हूं कि 250 शब्दों की सीमा सही है. कई बार लोग 15 पन्नों का आवेदन भेज देते हैं. संसद में पूछे जाने वाले प्रश्नों के लिए भी एक शब्द सीमा होती है. वे 150 शब्दों से ज़्यादा नहीं होते. हां, एक विषय तय कर देने से यह मुश्किल होगी कि फिर पीआईओ अपने हिसाब से विषय तय करने लगेंगे. जहां तक डाक शुल्क आवेदक से लिए जाने की बात है तो मैं समझता हूं कि यह जायज़ है, क्योंकि सरकार अभी जो ख़र्च कर रही है, वह भी तो जनता का ही पैसा है.”

शैलेष गांधी,
केंद्रीय सूचना आयुक्त

एनएसी और आरटीआई

अरुणा राय

राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के एक उपसमूह की बैठक 13 दिसंबर को हुई. यह उपसमूह उत्तरदायिता और पारदर्शिता के लिए बना है, जिसकी अध्यक्ष एनएसी की सदस्य एवं सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा राय हैं. बैठक का एजेंडा डीओपीटी द्वारा आरटीआई क़ानून के नियमों में प्रस्तावित संशोधन था. उपसमूह का अध्यक्ष होने के नाते अरुणा राय को यह अधिकार है कि इस बैठक में वह कुछ बाहरी लोगों को भी बुला सकती हैं. नतीजतन इस बैठक में सूचना का अधिकार आंदोलन से जुड़े कुछ प्रख्यात लोगों जैसे शेखर सिंह, निखिल डे एवं अरविंद केजरीवाल को भी बुलाया गया. इन तीनों ने एक स्वर से प्रस्तावित संशोधन की मुख़ालफ़त की और इसे आम आदमी के ख़िलाफ़ बताया. बहरहाल, इस बैठक की रिपोर्ट एनएसी की अध्यक्ष सोनिया गांधी को सौंपी जाएगी. अगली बैठक दिसंबर के आख़िरी हफ्ते में होनी है. इस बात का इंतज़ार उक्त तीनों आरटीआई कार्यकर्ताओं के अलावा देश की जनता को भी रहेगा कि सोनिया गांधी एनएसी अध्यक्ष के नाते इस मुद्दे पर क्या रुख़ अपनाती हैं.

विदेश सचिव निरुपमा राव ने हाल में राजधानी में अपने मंत्रालय के पब्लिक डिप्लोमेसी डिवीजन द्वारा आयोजित एक सेमिनार को संबोधित किया.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

बाबुओं की ट्वीटिंग

हाल में विकीलीक्स, साइबर अटैक्स और फोन टैपिंग जैसे कई ख़ुलासों की उलझन में सरकारी कामकाज ठप पड़ा है. इस साल की शुरुआत में बाबुओं द्वारा निजी ईमेल अकाउंट्स और सोशल मीडिया नेटवर्क्स का इस्तेमाल सरकारी कामकाजों में करने को लेकर भारत सरकार ने कड़ी फटकार लगाई थी. हालांकि विदेश मंत्रालय (एमईए) विदेशी सार्वजनिक नीति पर सीधे तौर पर डिबेट करना चाहता है. विदेश सचिव निरुपमा राव ने हाल में राजधानी में अपने मंत्रालय के पब्लिक डिप्लोमेसी डिवीजन द्वारा आयोजित एक सेमिनार को संबोधित किया. राव चाहती हैं कि विदेश मंत्रालय के बाबू जो अमूमन एहतियात बरतते हैं, उन्हें सार्वजनिक सूचना के क्षेत्र में आए खालीपन को सही सूचना देकर भरने के लिए जनता और मीडिया से संबंधित सोशल नेटवर्किंग टूल्स जैसे फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर साइटों पर सकारात्मक पहल करनी चाहिए. संयुक्त सचिव नवदीप सूरी की निगरानी में पब्लिक डिप्लोमेसी डिवीजन पहले से इंटरनेट का प्रयोग करने में भारत के रणनीतिक प्रयासों के बारे में गलत और रूढ़िवादी सूचना का विरोध कर रहा है. उम्मीद है, विदेश मंत्रालय की इस शुरुआती पहल से दूसरे मंत्रालयों को भी उनके कामकाज के तरीकों में सुधार के लिए एक नई सीख मिलेगी.

आ गई शामत

भ्रष्टाचार के चंगुल में फंसे बाबुओं की नियति अब उनका पीछा कर रही है. ज़मीन आवंटन घोटाला मामले पर उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्य सचिव नीरा यादव जो अब ज़मानत पर बाहर हैं, को अंततः जेल जाना पड़ गया. वहीं दूसरी ओर 2-जी घोटाला मसले पर ए राजा से संबंधित दूरसंचार विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारियों पर सीबीआई का डंडा चलना शुरू हो गया है. इनमें पूर्व दूरसंचार सचिव सिद्धार्थ बहुरिया, के श्रीधर, ए के श्रीवास्तव और आर के चंदोलिया भी शामिल हैं. इस मामले पर बाबुओं की परेशानी काफी बढ़ गई है, लेकिन यह कहना जल्दबाज़ी होगी कि सरकारी तंत्र में जवाबदेही की वापसी हो रही है. सरकारी नौकरियों और राजनीतिक क्षेत्र की मर्यादा धूमिल होती जा रही है. याद रखिए, नीरा यादव को सज़ा मिलने में सात साल लग गए. 2-जी मामले में भी दोषियों को न्यायोचित सज़ा दिलवाने में इससे अधिक नहीं तो कम वक्त भी लगने की उम्मीद नहीं है.

dilipcherian@gmail..com

साउथ ब्लॉक

75 आईपीएस बनेंगे आईजी

लंबे इंतज़ार के बाद आख़िरकार 1990 बैच के 75 आईपीएस अधिकारियों को आईजी या भारत सरकार में इसके समानांतर पद के लिए तैयार सूची में शामिल कर लिया गया है. इनमें उत्तराखंड के संजय सिंह, टी एस लूथरा, दीपेंद्र पाठक, आंध्र प्रदेश के गोविंद सिंह एवं अंजना सिंह प्रमुख रूप से शामिल हैं.

तिवारी बने एफआईयू के निदेशक

1985 बैच के आईएएस अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी को राजस्व विभाग में वित्तीय खुफिया इकाई का निदेशक बनाया गया है. इससे पहले इस पद पर 1985 बैच के उत्तराखंड के आईएएस अधिकारी अरुण गोयल काबिज थे. गोयल हाल में आर्थिक मंत्रालय की ओर से जापान में भारतीय दूतावास में नियुक्त किए गए हैं.

अजय आईटी में जेएस

1985 बैच के केरल के आईएएस अधिकारी अजय कुमार को सूचना तकनीक विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है. इससे पहले इस पद पर पंजाब के आईएएस अधिकारी राकेश सिंह कार्यरत थे, जो हाल में वित्तीय सेवाओं के विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं. यह पद जून, 2010 से खाली था.

नॉर्थ ब्लॉक मारेगा बाजी

विश्व बैंक वॉशिंगटन के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार की तलाश में यह साफ हो रहा है कि इस समय साउथ ब्लॉक नहीं, बल्कि नॉर्थ ब्लॉक से एक अधिकारी इस पद पर काबिज हो सकता है. हालांकि अभी तक सारी नियुक्तियां साउथ ब्लॉक से होती रही हैं. यह पद उत्तर प्रदेश के आईएएस अधिकारी जावेद उस्मानी की सेवानिवृत्ति के बाद से खाली है.

यह भ्रष्टाचार को बचाने की साज़िश है

पृष्ठ एक का शेष

का लाभ छात्र -छात्राओं तक पहुंचाया था या फिर इलाहाबाद के सुदूर गुलरहाई और चित्रकूट के भरथौल के आम लोग, जिनके आवेदन से प्राथमिक विद्यालय के छात्र-छात्राओं को स्कूल ड्रेस और किताबें मिलीं.

दरअसल, सूचना क़ानून के नियमों में प्रस्तावित संशोधन के पीछे एक लंबी कहानी है. सितंबर 2009 में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश के जी बालाकृष्णन ने एक पत्र प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लिखा. अपने पत्र में उन्होंने न्यायपालिका को आरटीआई क़ानून के दायरे से बाहर रखने का आग्रह किया था. तर्क यह कि इस क़ानून की वजह से न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है. हालांकि अब बालाकृष्णन एनएचआरसी के अध्यक्ष हैं और वह अब भी इस संशोधन की वकालत कर रहे हैं. अक्टूबर, 2010 में दिए एक बयान में वह कहते हैं कि इस क़ानून में कुछ खामियां हैं, जिनका बड़े स्तर पर दुरुपयोग हो रहा है. यह आरटीआई क़ानून के अनेक प्रावधानों में अंतरावलोकन का समय है. संभवतः यह विधेयक संसद में जल्दबाज़ी में पारित किया जाएगा. उनके इस बयान से पता चलता है कि सरकार काफी समय से इस संशोधन की तैयारी कर रही है. ग़ौरतलब है कि आरटीआई की वजह से ही धीरे-धीरे आम आदमी ने न्यायपालिका से भी सवाल पूछना शुरू कर दिया था. आरटीआई के इस्तेमाल से ही पता चला था कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने अपनी पत्नी के साथ विदेश यात्रा की थी, जबकि नियम के मुताबिक़ उस यात्रा के दौरान मुख्य न्यायाधीश अपनी पत्नी को साथ नहीं ले जा सकते थे. मामला सार्वजनिक होते ही सरकार ने कई दिशानिर्देश जारी किए थे, जिनमें जजों की विदेश यात्राओं में 30 प्रतिशत तक कटौती की भी बात थी.

बहरहाल, 2009 में बालाकृष्णन द्वारा प्रधानमंत्री को भेजे गए पत्र की भनक जब कुछ ग़ैर सरकारी संगठनों को लगी, तब उन्होंने सोनिया गांधी से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की. सोनिया गांधी 9 नवंबर, 2009 को अपने पत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री के सामने यह स्पष्ट करती हैं कि वह इस क़ानून में किसी भी तरह के संशोधन के ख़िलाफ़ हैं. वह लिखती हैं कि सिर्फ़ 4 सालों में ही इस क़ानून ने आम आदमी को बहुत कुछ दिया है. मेरी राय में राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे अभी भी इस क़ानून से बाहर हैं और ऐसी सूरत में इस क़ानून में किसी भी संशोधन की ज़रूरत नहीं है. वह प्रधानमंत्री को बताती हैं कि सरकार की असली समस्या कर्मचारियों में प्रशिक्षण का अभाव और सरकारी आंकड़ों का बेतरतीब रखरखाव है. बावजूद इसके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सोनिया गांधी को जवाब दिया कि वह उनके विचारों से सहमत हैं, लेकिन इसके साथ कुछ ऐसे मुद्दे भी हैं, जिनके लिए इस क़ानून में संशोधन करना ज़रूरी हो गया है. यानी पीएम भी आम आदमी को ताक़तवर बनाने वाले इस क़ानून में संशोधन के पक्ष में पहले से ही खड़े थे. और हो भी क्यों न. जब यह क़ानून इन नेताओं की असलियत का भंडाफोड़ कर रहा हो. एक उदाहरण पर ग़ौर करें. आरटीआई की बदौलत ही आम लोग यह जान सके कि चार साल में हमारे देश के मंत्रियों ने चाय-पानी पर आम आदमी की गाढ़ी कमाई में से लगभग 26 करोड़ रुपये ख़र्च कर दिए. जितनी तेज इन्हें प्यास लगती है, उतनी ही तेज प्यास इनकी गाड़ियों को भी लगती है. इसके अलावा साल 2003 से 2008 के बीच 44 मंत्रालयों एवं उनके अधीन विभिन्न विभागों के मंत्रियों एवं अधिकारियों ने केवल स्थानीय यात्राओं पर 58 करोड़ 54 लाख रुपये उड़ा दिए.

केंद्र सरकार का कार्मिक विभाग, जो इस क़ानून के लिए नोडल एजेंसी के तौर पर काम करता है, शुरू से ही इस क़ानून के कुछ नियमों में फेरबदल करना चाहता था. सूचना क़ानून बनने के पहले ही साल में कुछ ब्यूरोक्रेट्स की सलाह पर सरकार ने इसमें संशोधन कर फाइल नोटिंग जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान को ख़त्म करने की कोशिश की. हालांकि सिविल सोसायटी, वामपंथी पार्टियों और कुछ संगठनों के भारी विरोध के बाद सरकार ने यह फ़ैसला वापस ले लिया था. फिर भी बार-बार केंद्र और राज्य सरकारें इस क़ानून के नियमों में कुछ न कुछ हेरफेर के चक्कर में लगी ही रहती हैं, ताकि आम आदमी की ताक़त दिनोंदिन कमज़ोर होती जाए. कोई सवाल न पूछ सके, कोई बदलाव न हो सके, ताकि बिहार के मधुबनी ज़िले का कोई दूसरा चंद्रशेखर आरटीआई की वजह से पंचायत शिक्षक नियुक्ति में हुए फर्जीवाड़े का खुलासा न कर सके. या उड़ीसा की 70 वर्षीय कबनाकलता त्रिपाठी की 13 साल से लटकी पेंशन आरटीआई डालने के बाद एक महीने में न मिल सके. या फिर बिहार के बेगूसराय के विष्णुदेव शर्मा द्वारा एक आवेदन डालते ही उनकी बकाया पेंशन बैंक वालों को उनके खाते में डालने की जहमत न उठानी पड़े.

आरटीआई में प्रस्तावित संशोधन के मुद्दे पर जब चौथी दुनिया ने रेमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित आरटीआई कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल से बात की तो उनका कहना था कि सरकार को हमारी मांगें दिखाई नहीं देतीं. हम सालों से कहते आ रहे हैं कि सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया बनाई जाए, ताकि अच्छे लोगों को सूचना आयुक्त बनाया जा सके, लेकिन इस ओर ध्यान देने के बजाय केंद्र सरकार आम आदमी के इस क़ानून को और कमज़ोर बनाने में लगी हुई है. दरअसल, पूर्व नौकरशाहों को सरकार सूचना आयुक्त नियुक्त करती रही है. कुछ वर्तमान सूचना आयुक्त तो डीओपीटी में ही सचिव रह चुके हैं. असल में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए ज़िम्मेदार विभाग डीओपीटी के पास नियुक्ति के संबंध में कोई स्पष्ट नियम-क़ानून नहीं हैं. इसी का फ़ायदा उठाकर सरकार अपने विश्वस्त एवं वफ़ादार ब्यूरोक्रेट्स को सूचना आयुक्त बना देती है, जो किसी भी क़ीमत पर अपने आकाओं के हितों की अनदेखी नहीं कर सकते. कुछ राज्य सरकारें भी अपने यहां इस क़ानून के नियमों में संशोधन करती रही हैं. मसलन, कुछ राज्य सरकारों ने आरटीआई शुल्क दस के बजाय 100 रुपये और फोटो कॉपी शुल्क 2 के बजाय 5 रुपये कर दिया. जून, 2009 में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर 14 महत्वपूर्ण विषयों को इस क़ानून के दायरे से बाहर निकालने का तुगलकी फरमान जारी किया था. ज़ाहिर है, ऐसे फरमानों का मकसद गरीबों को उनके अधिकारों से वंचित करने और उनके सशक्तिकरण को रोकने के बराबर ही माना जाएगा. क्योंकि, आरटीआई ही वह क़ानून है, जिसने ग़रीबों को राशन तक दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. दिल्ली में तो ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं. पुरी की अनासारा गांव की 68 वर्षीय जनातुन बेगम और उनके पति को अंत्योदय योजना के तहत मिलने वाला अनाज आरटीआई की वजह से दोबारा मिलना शुरू हुआ था. जहानाबाद ज़िले के कताई बिगहा गांव में ग्रामीणों को सही मात्रा में राशन और मिट्टी का तेल मिलने लगा था. यही नहीं, सूचना के अधिकार ने पुलिस की तानाशाही को भी काफी हद तक कम किया है. उदाहरण के लिए पटना के सगुना निवासी अमित आनंद की जमीन कोइलवर थानाध्यक्ष के क़ब्ज़े से मुक्त हो गई. देवरिया ज़िले के धनेसर यादव की बेटी का जब गांव के कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, तब धनेसर यादव ने सूचना कानून के तहत पुलिस कप्तान कार्यालय को आवेदन दिया, जिसमें उन्होंने अपनी शिक़ायत पर की गई कार्रवाई के बारे में पूछा. आवेदन मिलते ही पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए धनेसर की अगवा पुत्री को बरामद कर लिया और आरोपी भी गिरफ़्तार कर लिए गए.

लेकिन इस बार केंद्र सरकार आरटीआई के नियमों में संशोधन को लेकर जिस तरह गंभीर दिख रही है, उससे लगता है कि आम आदमी के जीने और जानने के अधिकार से जुड़ा यह क़ानून पंगु बन जाएगा. फिर कोई आम आदमी सवाल नहीं पूछ सकेगा. वे सवाल, जो उसे ताक़त देते हैं, सम्मान देते हैं. लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन राहुल गांधी या सोनिया गांधी की सलाह को ही कांग्रेस पार्टी आदेश मानती रही है, क्या वे भी इस मुद्दे पर चुप रहेंगे? क्या कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ का उनका नारा महज़ नारा ही बनकर रह गया है? अब चाहे जो भी बात हो, जनता इनसे यह ज़रूर जानना चाहेगी कि अब कांग्रेस का हाथ किसके साथ है?

shashishekhar@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
देश का पहला साप्ताहिक अखबार

वर्ष 2 अंक 42
दिल्ली, 27 दिसंबर 2010-02 जनवरी 2011
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63, नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय

के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा
गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.
संपादकीय 0120-4783999/11-23418962
विज्ञापन + 91 9810017924
प्रसार + 91 9013478398
फैक्स न. 0120-4783950

पृष्ठ-16+4 (बिहार-झारखंड एवं उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुनः प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

अमन कारवां

फ़िलिस्तीनियों का दुःख-दर्द बांटने की कोशिश

भारत से अमन का पैग़ाम लेकर एक कारवां इज़रायल पहुंचने वाला है. यह फ़िलिस्तीनियों के दुःख-दर्द को बांटने और शांति का पैग़ाम लेकर वहां जा रहा है. इसमें देश की कई जानी-मानी हस्तियां शामिल हैं. यह कारवां ज़मीन के रास्ते पाकिस्तान और ईरान होते हुए इज़रायल पहुंच रहा है. डर इस बात का है कि अमन के इस कारवां का हश्र भी कहीं फ्रीडम फ्लोटिला की तरह न हो. भारत फ़िलिस्तीन का हिमायती रहा है, लेकिन अमन के इस कारवां को शुरुआत से ही कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा है.

फ़रमान चौधरी

इज़रायल की नीतियों की वजह से फ़िलिस्तीनी हिंसा का शिकार हो रहे हैं, जिन्हें शायद इज़रायल और फ़िलिस्तीन का मतलब पता नहीं है. ताज़ा स्थिति यह है कि इज़रायल के हवाई हमलों की वजह से फ़िलिस्तीन के लोगों को रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं. सबसे बड़ी समस्या दवाइयों की है. आर्थिक नाकेबंदी की वजह से लोग मर रहे हैं. मरने वालों में नवजात बच्चे हैं, बूढ़े हैं और महिलाएं हैं. इज़रायल की ओर से ग़ज़ा की आर्थिक नाकेबंदी की वजह से ग़ज़ा की स्थिति बहुत कष्टदायी है. ऑक्सफेम, एमनेस्टी इंटरनेशनल और स्योदी चिल्ड्रन जैसे 21 संगठनों की रिपोर्ट भी यही कहती है. फ़िलिस्तीन में काम कर रहे मानवाधिकार संगठन वहां की बदहाली के बारे लगातार बता रहे हैं, फिर भी अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने चुप्पी साध रखी है. यही वजह है कि फ़िलिस्तीन के लोग साफ़ पानी, बिजली और रोज़गार के लिए तरस रहे हैं. फिलिस्तीन की जनता को मदद की ज़रूरत है.

फ़िलिस्तीन के इन्हीं मजबूर और मज़लूम लोगों का दुःख-दर्द बांटने अमन का एक कारवां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि राजघाट से ग़ज़ा के लिए रवाना हुआ. ग़ज़ा रवाना होने से पहले 60 लोगों ने राजघाट पर एक बैठक की, जिसमें अखिल भारतीय कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद मणि शंकर अय्यर ने भी शिरकत की. इन दोनों नेताओं ने इस कार्यक्रम में न सिर्फ़ शिरकत की, बल्कि कारवां के प्रति सहानुभूति और समर्थन की घोषणा भी की. दिग्विजय सिंह ने कहा कि भारत हमेशा से फ़िलिस्तीन के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थक रहा है और आज भी. लेकिन पूर्व केंद्रीय मंत्री मणि शंकर अय्यर ने जो कहा, वह चौंकाने वाला है. वह शुरुआत से ही फिलिस्तीनी आंदोलन के समर्थक रहे हैं. उन्होंने कहा कि भारत हमेशा फ़िलिस्तीन का समर्थन करता आया है, लेकिन आज स्थिति काफ़ी अलग है और नीतियों में भी काफ़ी परिवर्तन आया है. ग़ौर करने वाली बात यह है कि देश के सत्तारूढ़ दल के नेता अगर यह बात कह रहे हैं तो इसमें शक़ की कोई गुंजाइश नहीं बचती है. मणि शंकर अय्यर की साफ़गोई के लिए उनकी तारीफ़ होनी चाहिए, क्योंकि सरकार की मजबूरियों के बीच उन्होंने कहा कि हम सबको लाचार फ़िलिस्तीनियों को आज़ादी और न्याय दिलाने के लिए क़दम से क़दम मिलाकर उनका समर्थन करना चाहिए.

दुनिया भर की सरकारों की अपनी मजबूरी हो सकती है, लेकिन इस कारवां को अलग-अलग देशों की जनता और संगठनों का समर्थन ज़रूर हासिल है. फ़िलिस्तीन समर्थक संगठन एशियन पीपल्ज़ सोलीडेरिटी फॉर पिल्सटाइन के इस कारवां में भारत के 60 सदस्यों के अलावा पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया, जापान, अफ़ग़ानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, ईरान, इराक, शाम, ओमान, तुर्की, लेबनान और मिस्र से लगभग 500 लोग शामिल हुए. इस अमन कारवां ने ग़ज़ा में दाख़िल होने के लिए 27 दिसंबर की तारीख निर्धारित की है, क्योंकि इसी दिन इज़रायल द्वारा ग़ज़ा की घेराबंदी के तीन साल पूरे हो जाएंगे. अमन कारवां में बुद्धिजीवी, फिल्म निर्माता, अभिनेता , पत्रकार, मानवाधिकार कार्यकर्ता और अन्य क्षेत्रों से जुड़े लोग शामिल हैं. कारवां को एशिया के सैकड़ों संगठनों और दलों का समर्थन प्राप्त है. अकेले भारत से ही लगभग 80 संगठनों ने इस कारवां के समर्थन की घोषणा की, जिनमें समाजसेवी संस्थाएं, उदारवादी संगठन, धार्मिक संगठन, विद्यार्थी, पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता आदि शामिल हैं. इनमें से कुछ संगठनों के प्रतिनिधि कारवां के साथ गए, जबकि कुछ ने अपने समर्थन की घोषणा की. नागपुर से सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश खैरनार, मैगसेसे अवार्ड से सम्मानित संदीप पांडेय, पत्रकार अजीत साही और मिली गज़ेट के प्रधान संपादक डॉक्टर ज़फ़र इल इस्लाम ख़ां जैसे लोग अमन कारवां में शरीक़ हुए. कारवां में पूरे देश के हर वर्ग के प्रतिनिधित्व की सफल कोशिश की गई. इसकी एक ख़ास बात यह भी है कि भारत समेत सभी एशियाई देशों द्वारा फ़िलिस्तीन से सहानुभूति प्रकट होने के बावजूद कोई कारवां आज तक इससे पहले नहीं गया. यूरोप से बड़े-बड़े कारवां गए और जा रहे हैं. तुर्की से इस साल फ्रीडम फ्लोटिला नामक एक कारवां ग़ज़ा के लिए गया था, जिसमें अनाज, दवाएं और अन्य आवश्यक सामग्री थी और दुनिया भर के लगभग 300 लोग शामिल थे. यह ग़ज़ा जाना चाहता था, लेकिन बीच रास्ते में समुद्र में इस पर इज़रायली कमांडोज ने हमला कर दिया था, जिससे 9 स्वयंसेवी मारे गए और 50 से अधिक घायल हो गए थे. बाक़ी लोगों को इज़रायली सिपाहियों ने गिरफ्तार कर लिया और इस जहाज़ को सामान समेत उठाकर ले गए. हालांकि बाद में वह जहाज़ इज़रायल ने आज़ाद कर दिया था. अब यह जहाज़ मरम्मत के बाद 26 दिसंबर को मिस्र की सीमा पर एक बड़े जलसे के बाद दोबारा ग़ज़ा रवाना किया जाएगा.

एशिया से ग़ज़ा रवाना होने वाले अमन कारवां को 2 दिसंबर को वाघा सीमा पैदल पार करके पाकिस्तान जाना था, जहां लाहौर पहुंच कर करांची और कोयटा होते हुए ईरान, तुर्की, सीरिया, जार्डन, लेबनान और फिर मिस्र के रास्ते ग़ज़ा में दाख़िल होने का कार्यक्रम था, लेकिन अमन कारवां को पहला झटका उस समय लगा, जब सुरक्षा को ख़तरा बताकर पाकिस्तान ने भारतीय अमन कारवां के सदस्यों को वीज़ा देने से इंकार कर दिया. बाद में पाकिस्तान ने सिर्फ़ लाहौर तक का वीज़ा जारी किया, वह भी 60 में से सिर्फ़ 29 सदस्यों को. बाक़ी सदस्यों का वीज़ा पाकिस्तान उच्चायोग ने बिना किसी ठोस कारणों के रद्द कर दिया. अब सवाल यह है कि पाकिस्तान ने ऐसा क्यों किया. क्या पाकिस्तान ने अमेरिका और इजरायल के दबाव में आकर ऐसा किया या फिर उसे सचमुच ऐसा लगता है कि कारवां में शामिल लोग उसकी सुरक्षा के लिए ख़तरा हैं. पाकिस्तान के इस रवैये की वजह वहां के अधिकारी ही बता सकते हैं. हालांकि पाकिस्तान उच्चायोग शुरू से ही अमन कारवां के सदस्यों को आश्वासन देता रहा है कि उसकी सरकार कारवां का समर्थन करती है और अगर कारवां के सदस्य रात के 12 बजे भी आएंगे तो भी उन्हें वीजा जारी कर दिए जाएंगे. इसके बावजूद एक दिसंबर की शाम को कारवां के सदस्यों को बुलाकर पाकिस्तानी उच्चायोग ने कहा कि उसकी सरकार अमन कारवां के सदस्यों को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती. पाकिस्तानी सरकार का यह रवैया संदेह पैदा करता है. ये लोग शांति का संदेश लेकर फ़िलिस्तीनियों की मदद करने ग़ज़ा जा रहे हैं, अब कोई सरकार ऐसे लोगों को सुरक्षा देने से मना कर दे तो इसे क्या माना जाए. इसके अलावा पाकिस्तानी उच्चायोग में कारवां के सदस्यों से जो सवाल किए गए, उनसे भी पाकिस्तान की नीयत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है. पाकिस्तानी उच्चायोग द्वारा पूछे गए विभिन्न सवालों में से एक सवाल यह भी था कि क्या पाकिस्तानी पत्रकार तुलाल भी इस कारवां के साथ ग़ज़ा जाएंगे. पाकिस्तान की इजरायल नवाज़ी इस सवाल के बाद पूरी तरह खुलकर सामने आ गई, क्योंकि इजरायल की सरकार ने यह पहले ही ऐलान कर दिया था कि हर व्यक्ति को ग़ज़ा जाने की अनुमति नहीं है. सवाल यह है कि तुलाल को इजरायल ग़ज़ा में दाख़िल होने की अनुमति नहीं देता है तो कोई बात नहीं, लेकिन पाकिस्तान के सामने तुलाल को रोकने की क्या मजबूरी थी.

ग़ज़ा जाने वाले कारवां को दूसरा झटका उस समय लगा, जब उसके 29 सदस्य वाघा सीमा पर पहुंचे. वहां उन्हें पता चला कि वाघा के अधिकारियों के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि किसी अमन कारवां को पैदल पाकिस्तान जाने की अनुमति दी जाए. इस मौक़े पर कारवां के भारतीय और पाकिस्तानी सदस्यों ने सीमा के दोनों ओर विरोध प्रदर्शन किया. इसके बाद कारवां के सदस्य वापस आने लगे तो पंजाब से दिल्ली आते हुए रात को लगभग 9 बजे सूचना मिली कि वे कल वाघा सीमा पार कर सकते हैं. इस घटना के बाद भारत सरकार का वह चेहरा सामने आ जाता है, जिसका ज़िक्र 2 दिसंबर को महात्मा गांधी की समाधि पर मणि शंकर अय्यर ने किया था कि भारत हमेशा फ़िलिस्तीन का समर्थन करता आया है. लेकिन आज की परिस्थितियां काफ़ी भिन्न हैं और नीतियों में काफ़ी बदलाव आ गया है. यह फ़िलिस्तीन के प्रति भारत सरकार की नीतियों की देन है, वरना अगर कारवां द्वारा डेढ़ महीने पहले दिए गए आवेदन को ख़ारिज़ किया जा चुका था तो इसकी सूचना क्यों नहीं भेजी गई. आख़िरकार ग़ज़ा जाने वाले एशियाई अमन कारवां के 29 भारतीय सदस्यों ने अगले दिन पैदल वाघा सरहद पार की, जहां पाकिस्तान के दर्जनों लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया. वाघा सीमा पर ही एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय कारवां के सदस्यों ने फ़िलिस्तीनी परचम पाकिस्तानी सदस्यों के सुपुर्द किया. इसके बाद सभी सदस्य लाहौर चले गए, जहां 2 दिन रुकने के बाद वे अपने वतन वापस आ गए. फिर यहां से वे हवाई जहाज़ द्वारा ईरान के लिए रवाना हो गए.

ग़ज़ा जाने वाले एशियाई अमन कारवां की रवानगी से पूर्व इन देशों में फ़िलिस्तीनियों के दर्द और उनकी कठिनाइयों को उजागर करने के लिए फ़िल्म, सेमिनार, धरने और जुलूसों का भी आयोजन किया गया. यह कारवां जिन शहरों और देशों से गुज़रा, वहां बड़े-बड़े जलसे और आमसभाएं की गईं. ग़ज़ा से वापस आकर कारवां के सदस्य भारत के 15 बड़े शहरों में कांफ्रेंस करेंगे, ताकि भारत सरकार और जनता फ़िलिस्तीन का उसी तरह समर्थन करे, जिस तरह महात्मा गांधी, पंडित जवाहर लाल नेहरू और इंदिरा गांधी ने किया था, क्योंकि दुनिया भर में जहां कहीं भी स्वतंत्रता आंदोलन हुए, उन्हें भारत ने समर्थन दिया. महात्मा गांधी कहते थे कि फ़िलिस्तीन उसी तरह फ़िलिस्तीनियों का है, जिस तरह तुर्की तुर्कियों का है, ईरान ईरानियों का और हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का. जिस तरह भारत और पाकिस्तान में इस कारवां को जनसमर्थन मिला, जिस तरह अधिकारियों ने मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश की, उससे साफ़ ज़ाहिर है कि कारवां को लेकर भारत, पाकिस्तान और इज़रायल की सरकार चिंतित है. अब सबकी निगाहें अमन कारवां पर टिकी हैं. क्या यह ग़ज़ा पहुंच पाएगा, क्या इजरायल इसे गज़ा में घुसने देगा या फिर इस कारवां को भी फ्रीडम फ्लोटिला की तरह रोका जाएगा. अगर इस कारवां को रोका जाता है तो भारत सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी और अगर कारवां ग़ज़ा के लोगों तक भारत और एशिया की जनता का पैग़ाम पहुंचा पाता है तो भारत और फिलिस्तीन की जनता के बीच दोस्ती और भाईचारे के इतिहास में यह मील का पत्थर साबित होगा.

feedback@chauthiduniya.com

झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय कार्यसमिति के एक सदस्य का कहना है कि राज्य में झामुमो और भाजपा के गठबंधन वाली सरकार है.

झारखंड

रंग बदलती राजनीति

प्रशांत कुमार झा

झारखंड की राजनीतिक हवा इन दिनों बदली हुई है. मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा को शपथ लिए तीन माह हो गए. शपथ ग्रहण के छह महीने के भीतर उन्हें चुनाव जीतकर विधानसभा आना है. इसलिए राज्य में विधानसभा एवं लोकसभा के एक-एक उपचुनाव की बिसात बिछनी शुरू हो गई है. फलत: सूबे में सियासी सरगर्मी बढ़ रही है. बीते 11 सितंबर को अर्जुन मुंडा ने झारखंड के आठवें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. बतौर मुख्यमंत्री मुंडा की यह तीसरी पारी है. जमशेदपुर लोकसभा सीट से सांसद अर्जुन मुंडा को मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए राज्य की किसी भी विधानसभा सीट से जीत हासिल करना आवश्यक है. राज्य के मुखिया पद पर आसीन हुए मुंडा को ढाई महीने बीत जाने तक चुनाव की कोई चर्चा ही नहीं थी, परंतु गत 30 नवंबर को जमशेदपुर की खरसावां विधानसभा सीट से भाजपा विधायक मंगल सिंह सोय ने इस्तीफ़ा दे दिया. उन्होंने अर्जुन मुंडा के चुनाव लड़ने के लिए सीट छोड़ी है. उनका इस्तीफ़ा स्वीकार भी कर लिया गया है. इसी के साथ मुंडा के चुनाव लड़ने, न लड़ने या सीट की उपलब्धता न होने जैसी अटकलों पर विराम लग गया. कुछ लोगों को यह भी लग रहा था कि मुंडा का हाल भी शिबू सोरेन जैसा न हो जाए. उल्लेखनीय है कि पिछली सरकार में सोरेन मुख्यमंत्री पद पर काबिज़ थे. उन्हें मुख्यमंत्री बने रहने के लिए विधानसभा चुनाव जीतना अनिवार्य था, मगर झामुमो प्रमुख होने के बावजूद पार्टी के किसी विधायक ने उनके लिए सीट नहीं छोड़ी. यहां तक कि उनके विधायक पुत्र एवं पुत्रवधू ने भी उनके लिए सीट की क़ुर्बानी नहीं दी. ठीक इसके विपरीत अर्जुन मुंडा के साथ ऐसी स्थिति नहीं थी. मुख्यमंत्री मुंडा अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत से ही खरसावां सीट से जीतते आ रहे हैं. 2009 के लोकसभा चुनाव में वह जमशेदपुर सीट से सांसद चुने गए. झारखंड में नवंबर 2009 में हुए विधानसभा चुनाव में मुंडा की सरपरस्ती में खरसावां सीट से मंगल सिंह सोय ने जीत हासिल की थी. जीतने के पश्चात विधायक मंगल सिंह सोय का पहला बयान यही था कि जब भी अर्जुन मुंडा कहेंगे, तब वह सीट उनके लिए छोड़ देंगे. अब जब सोय ने मुंडा के लिए सीट छोड़ दी है तो राज्य में दो उपचुनावों की संभावना बन गई है. विधानसभा में आने के लिए मुंडा खरसावां विधानसभा सीट से लड़ेंगे और साथ ही जमशेदपुर संसदीय सीट से इस्तीफ़ा देंगे. इस वजह से सूबे में कानाफूसी और लॉबिंग तेज हो गई है. लड़ने के इच्छुक विभिन्न उम्मीदवार जहां टिकट पाने के लिए ताल ठोंक रहे हैं, वहीं राज्य की विभिन्न पार्टियां जोड़तोड़ में जुट गई हैं. सूबे में जलवायु का तापमान गिर रहा है, वहीं इसके उलट भावी चुनाव के कारण राजनीतिक तापमान बढ़ रहा है.

सुविधानुसार अपनी नीति और विचार में निरंतर परिवर्तनशील पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा की आंखें जमशेदपुर लोकसभा सीट पर गड़ी हुई हैं. मंगल सिंह सोय द्वारा अपना इस्तीफ़ा विधानसभा अध्यक्ष सी पी सिंह को सौंपने के बाद से ही झामुमो जमशेदपुर संसदीय सीट पर अपना दावा करने लगा है. उसका कहना है कि वहां से पिछले दो दशकों में उसी उम्मीदवार ने ही विजयश्री पाई है, जिसका जुड़ाव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से झामुमो से रहा है. झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक बड़े नेता के अनुसार, जमशेदपुर के निवासियों ने अर्जुन मुंडा को संसद इसलिए भेजा, क्योंकि वे आज भी मुंडा को झामुमो के नेता के तौर पर समझते हैं. अर्जुन मुंडा ने अपने सियासी करियर की शुरुआत इसी पार्टी से की थी और इसी के टिकट पर वह पहली बार विधायक बन सके थे. चूंकि अर्जुन मुंडा झामुमो प्रमुख गुरु जी के नज़दीकी रहे हैं, इसलिए जमशेदपुर की जनता आज भी पुराने नज़रिए से देखकर ही मुंडा को अपना प्यार देती है. 90 के दशक में जमशेदपुर सीट से भाजपा के टिकट पर आभा महतो जीती थीं. उनकी जीत के पीछे कारण यह था कि उनके पति शैलेंद्र महतो झामुमो के नेता थे. आभा महतो से पहले उस सीट पर शैलेंद्र महतो का क़ब्ज़ा था. बतौर झामुमो प्रत्याशी उन्होंने यह सीट हासिल की थी, लेकिन नरसिम्हाराव के प्रधानमंत्रित्व काल के कुख्यात घूसकांड में शिबू सोरेन के साथ नाम आने के बाद शैलेंद्र ने पार्टी का दामन छोड़ने का फ़ैसला किया था.

झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय कार्यसमिति के एक सदस्य का कहना है कि राज्य में झामुमो और भाजपा के गठबंधन वाली सरकार है. हम लोग खरसावां सीट पर अर्जुन मुंडा का समर्थन कर रहे हैं. इसलिए भाजपा को चाहिए कि वह जमशेदपुर सीट से अपना दावा छोड़ दे. खरसावां सीट पर हम अर्जुन मुंडा को पूरा सहयोग देंगे, बदले में जमशेदपुर सीट हमें दी जाए. यदि भाजपा राज्य में स्थिर सरकार चाहती है तो उसे हमारी भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए. दूसरी तरफ़ राज्य भाजपा के अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी एवं मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा का कहना है कि कोई भी फ़ैसला सही समय पर ही लिया जाएगा. अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, भाजपा झामुमो को जमशेदपुर सीट नहीं देना चाहती, क्योंकि उसे खरसावां सीट पर झामुमो के समर्थन की कोई ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है. पार्टी का विश्वास है कि खरसावां से अर्जुन मुंडा की जीत पक्की है. चुनाव तो महज़ औपचारिकता है. वर्ष 1995 में पहली बार मुंडा ने झामुमो के टिकट पर खरसावां से उस समय के दबंग प्रत्याशी विजय सिंह सोय के विरुद्ध चुनाव लड़ा था. विजय सिंह को टक्कर देने के लिए नामांकन कर सबको भौंचक करने वाले अर्जुन ने पहली बार में ही सोय को 5000 से अधिक वोटों से शिकस्त देकर अपना लोहा मनवाया था. बिहार विधानसभा में एक ओजस्वी वक्ता की छवि बनाने वाले मुंडा 1999 में झामुमो छोड़ भाजपा में शामिल हुए थे. 2000 के विधानसभा चुनाव में अर्जुन मुंडा खरसावां सीट से भाजपा के टिकट पर जीतकर विधायक बने. इस चुनाव में जीत का अंतर 13 हज़ार मतों से ज़्यादा था. मुंडा के 44521 वोटों के मुक़ाबले विजय सिंह सोय को 30847 वोट मिले थे. वर्ष 2005 के विधानसभा चुनाव में अर्जुन मुंडा के सामने थीं दिवंगत विजय सिंह सोय की पत्नी कुंती सोय, मगर मुंडा ने बड़े अंतर से चुनाव जीता. अर्जुन को 74797 वोट मिले, वहीं कुंती को केवल 19453 वोट मिले थे. 2009 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के मंगल सिंह सोय ने खरसावां सीट जीती. ऐसे में खरसावां सीट पर झामुमो के समर्थन के बदले जमशेदपुर सीट उसे दे देने में भाजपा को बुद्धिमानी नज़र नहीं आ रही है.

उधर विपक्षी दलों में बाबूलाल मरांडी की पार्टी झारखंड विकास मोर्चा एवं कांग्रेस के बीच खरसावां उपचुनाव को लेकर तक़रार तय है. सियासी गठजोड़ होने के बाद भी दोनों अलग-अलग राग अलाप रहे हैं. दोनों पार्टियों के बीच फाड़ स्पष्ट दिख रहा है. झाविमो एवं कांग्रेस के बीच 2009 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन हुआ था, परंतु अब दोनों के संबंधों में गर्मजोशी नहीं रही. झाविमो विधायक दल के नेता एवं पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रदीप यादव कहते हैं कि झाविमो खरसावां सीट पर अर्जुन मुंडा के ख़िलाफ़ अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी. पार्टी ने तय कर लिया है कि वह आने वाले चुनावों में अकेले लड़ेगी. यादव ने साफ कहा कि झाविमो ने कांग्रेस से नाता तोड़ लिया है. कांग्रेस पार्टी खरसावां उपचुनाव के लिए क्या कर रही है, उससे झाविमो को कुछ लेना-देना नहीं है. दूसरी ओर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस विधायक दल के नेता राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि खरसावां सीट पर प्रत्याशी उतारने का फ़ैसला उपयुक्त समय पर केंद्रीय नेतृत्व करेगा. झाविमो-कांग्रेस के संबंधों पर सिंह ने अभी कुछ खुलासा नहीं किया है. जबकि कांग्रेस के झारखंड में एकलौते सांसद एवं केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री सुबोधकांत सहाय कहते हैं कि झाविमो का अस्तित्व कांग्रेस की बदौलत है. बकौल सहाय, जमशेदपुर लोकसभा सीट के उपचुनाव में कांग्रेस का ही दावा बनता है. झाविमो तो उस क्षेत्र में आधारहीन है.

feedback@chauthiduniya.com

कानकुन जलवायु सम्मेलन

एक क़दम आगे-दो क़दम पीछे

क्योतो प्रोटोकॉल में यह सिद्धांत आम सहमति से मंजूर किया गया था कि जिस मुल्क की, धरती के वातावरण को प्रदूषित करने में जितनी भूमिका है, वह उसके ख़तरों से धरती को बचाने के लिए उतनी ही ज़िम्मेदारी निभाएगा. इस प्रोटोकॉल में अमीर मुल्कों को एक अलग खाने में रखा गया और उनके लिए बाकायदा ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती के बाध्यकारी लक्ष्य तय किए गए.

ज़ाहिद ख़ान

मेक्सिको के कानकुन में हुआ 16वां जलवायु परिवर्तन विषयक सम्मेलन अमेरिका और विकसित मुल्कों के अड़ियल रवैये के चलते बिना किसी ठोस नतीजे के ख़त्म हो गया. बीते साल कोपेनहेगन में हुए सम्मेलन की तरह यहां भी ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती को लेकर विकसित और विकासशील मुल्कों के बीच कोई आम सहमति नहीं बन पाई. सम्मेलन शुरू होने के पहले हालांकि यह उम्मीद की जा रही थी कि विकसित मुल्क इस मर्तबा उत्सर्जन कटौती संबंधी कोई क़ानूनी बाध्यकारी समझौते पर अपनी राय बना लेंगे, लेकिन दो हफ़्ते की लंबी कवायद के बाद भी कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए कोई वाजिब समझौता आकार नहीं ले सका. अलबत्ता सम्मेलन का जो आख़िरी मसौदा सामने निकल कर आया, उसमें कार्बन उत्सर्जन कम करने की बात ज़रूर कही गई है, मगर इसे कैसे हासिल किया जाएगा, इस पर साफ-साफ कुछ नहीं कहा है.

ग़ौरतलब है कि 1997 में जापान के क्योतो शहर में हुआ ऐतिहासिक अंतरराष्ट्रीय क़रार क्योतो प्रोटोकॉल, जो 2004 से अमल में आया, में यह तय हुआ था कि 37 विकसित मुल्क स्वैच्छिक कटौती के तहत आहिस्ता-आहिस्ता अपने यहां 2012 तक 4 ग्रीनहाउस गैस और 2 दीगर ख़तरनाक गैसों का प्रदूषण 1990 के स्तर पर 5 फ़ीसदी घटा देंगे. लेकिन जलवायु परिवर्तन पर अंतर्शासकीय पैनल (आईपीसीसी) जो संयुक्त राष्ट्र संघ का ही एक अंग है, की हालिया रिपोर्ट इस बात की तस्दीक करती है कि क्योतो संधि से ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन पर कोई खास असर नहीं पड़ा. इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका का शुरू से ही इस संधि से बाहर रहने का फ़ैसला था. जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यदि देखें तो हवा में कार्बनडाई ऑक्साइड घोलने में अकेला अमेरिका 26 फ़ीसदी का हिस्सेदार है. एक आकलन के मुताबिक़, भारत द्वारा उत्सर्जित ग्रीनहाउस गैसों के बरक्स अमेरिका दस गुना अधिक गैस वातावरण में उगलता है. प्रति व्यक्ति स्तर पर नापा जाए तो यह अनुपात और भी ख़तरनाक है.

क्योतो प्रोटोकॉल में यह सिद्धांत आम सहमति से मंजूर किया गया था कि जिस मुल्क की, धरती के वातावरण को प्रदूषित करने में जितनी भूमिका है, वह उसके ख़तरों से धरती को बचाने के लिए उतनी ही ज़िम्मेदारी निभाएगा. इस प्रोटोकॉल में अमीर मुल्कों को एक अलग खाने में रखा गया और उनके लिए बाकायदा ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती के बाध्यकारी लक्ष्य तय किए गए. प्रोटोकॉल में बाक़ी विकासशील मुल्कों, जिनमें भारत भी शामिल है, के लिए इस तरह का कोई बाध्यकारी लक्ष्य नहीं था. देखा जाए तो यह सही भी था, क्योंकि पिछड़े और विकासशील मुल्क जैसे-जैसे विकास करेंगे, वैसे-वैसे उनके यहां उत्सर्जन भी बढ़ेगा. अमेरिका और तमाम विकसित मुल्कों से यह पूछा जाना चाहिए कि भारत और बाक़ी विकासशील मुल्कों को विकास के उस स्तर तक पहुंचने का क्या कोई हक़ नहीं है, जहां अमीर मुल्क पहले ही पहुंच चुके हैं? इस क्रम में यदि इन मुल्कों में ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन होता है तो क्या इन पर नियंत्रण की वही कसौटियां अमल में लाई जाएंगी, जो तरक़्क़ी कर चुके मुल्कों के लिए ज़रूरी हैं?

सच बात तो यह है कि जलवायु संकट की प्राथमिक ज़िम्मेदारी पश्चिम के औद्योगिक मुल्कों की है, जिन्होंने वातावरण में अभी जमा ग्रीनहाउस गैसों का 80 फ़ीसदी उगला है. पर कानकुन जलवायु सम्मेलन में विकसित मुल्कों ने इस अहम मसले पर दुनिया से कोई वादा नहीं किया. संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत हुए जलवायु परिवर्तन क़रार (यूएनएफसीसीसी) के बुनियादी उसूलों से उन्होंने पूरी तरह किनारा कर लिया. यही इस सम्मेलन की सबसे बड़ी नाकामी है. विकासशील मुल्क एकजुट होकर यदि इस मुद्दे पर विकसित मुल्कों से संघर्ष करते तो शायद कोई सर्वमान्य रास्ता निकल भी आता, लेकिन वे भी अपनी लड़ाई सही तरह नहीं लड़ पाए. बेसिक समूह जिसमें भारत, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ़्रीका जैसे मुल्क शामिल हैं, उन पर यह ज़िम्मेदारी थी कि वे आगे बढ़कर विकासशील मुल्कों की रहनुमाई करें और कोई ऐसा समझौता कराने में कामयाब हों, जो विकासशील मुल्कों के हित में हो. लेकिन बेसिक समूह ख़ुद कई मुद्दों पर आपस में बंटा नज़र आया.

विकसित मुल्कों द्वारा मूलभूत उत्सर्जन में कमी का मसला अभी भी अनसुलझा है. क्योतो प्रोटोकॉल को आगे बढ़ाने और उत्सर्जन कटौती का लक्ष्य तय न करने का मतलब सीधे-सीधे पर्यावरण को नुक़सान है. ज़ाहिर है, इससे जलवायु संकट से निपटने में कोई मदद नहीं मिलेगी.

जहां तक कानकुन में हमारे मुल्क की भूमिका का सवाल है, वहां पहुंचने से पहले ही पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने अपने बयानों से यह इशारा देना शुरू कर दिया था कि सभी मुल्कों को अपने यहां वाजिब क़ानूनी स्वरूप के तहत उत्सर्जन रोकने की बाध्यकारी प्रतिबद्धता जतानी चाहिए. लेकिन भारत के इस रुख़ से जहां विकसित मुल्क के नुमाइंदे रजामंद नहीं हुए, वहीं बेसिक समूह भी इस मुद्दे पर बंटा हुआ था, जिसके चलते उत्सर्जन कटौती पर क्योतो प्रोटोकॉल को 2012 के आगे बढ़ाने पर कोई उचित समझौता शक्ल नहीं ले पाया. हां, अलबत्ता आख़िरी मसौदे में भारत की कई राय ज़रूर शामिल कर ली गईं. इसमें खास तौर पर उसके अंतरराष्ट्रीय परामर्श और विश्लेषण (आईसीए) जैसे सुझाव शामिल हैं. आईसीए एक पारदर्शी निगरानी प्रणाली है, जो आइंदा इस बात पर नज़र रखेगी कि कोई मुल्क घरेलू स्तर पर अपने यहां जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए कोई कारगर क़दम उठा रहा है या नहीं? क्योतो क़रार का परिणाम 2012 के बाद क्या होगा? हालांकि इस पर सम्मेलन में कोई वाजिब फ़ैसला नहीं हो पाया, लेकिन विकसित मुल्क तमाम जद्दोज़हद के बाद आख़िरकार इस बात के लिए रजामंद हो गए हैं कि विकासशील मुल्कों की ख़ातिर 100 अरब डॉलर का हरित कोष बनाया जाए, जो जलवायु संकट से निपटने में काम आएगा. सम्मेलन में प्रौद्योगिकी साझीदारी की प्रणाली पर भी व्यापक समझौता हुआ. इसके तहत यह सुनिश्चित होगा कि ग़रीब और जलवायु परिवर्तन से प्रभावित मुल्कों तक प्रौद्योगिकी की पहुंच आसानी से हो और उसकी लागत भी कम हो. जलवायु संरक्षण योजना बनाने वाले मुल्कों की मदद अब एक विशेष समिति करेगी. साथ ही उत्सर्जन में कमी पर भी नज़र रखी जाएगी.

विकसित मुल्कों द्वारा मूलभूत उत्सर्जन में कमी का मसला अभी भी अनसुलझा है. क्योतो प्रोटोकॉल को आगे बढ़ाने और उत्सर्जन कटौती का लक्ष्य तय न करने का मतलब सीधे-सीधे पर्यावरण को नुक़सान है. ज़ाहिर है, इससे जलवायु संकट से निपटने में कोई मदद नहीं मिलेगी. वैश्वीकरण का फ़ायदा लेने वाले अहम औद्योगिक मुल्क एवं बड़ी विकासशील अर्थव्यवस्थाएं अरसे से ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने की पहल का इस बिना पर मुख़ालफ़त करती रहीं हैं कि इसमें भारी लागत की दरकार है और इसमें उनकी आर्थिक वृद्धि और विकास प्रभावित होंगे, लेकिन इसके उलट सच्चाई कुछ और है. आईपीसीसी, जिसमें तमाम मुल्कों के तीन हज़ार से अधिक वैज्ञानिक शामिल हैं, की रिपोर्ट कहती है कि ऊर्जा मामलों में महत्वपूर्ण बदलावों से महज़ 5-10 फ़ीसदी अधिक ख़र्च ही लगेगा. 2030 तक ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन के आंकड़ों को 450 पीपीएस के इर्द-गिर्द तक ले आने के लिए यदि कमी लाने की तमाम तरकीबें अमल में लाई जाएं तो आगामी दो दशकों में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में महज़ 3 फ़ीसदी की कमी आएगी. यानी हर साल एक फ़ीसदी का दसवां हिस्सा. कम ऊर्जा लागत, बेहतर बाज़ार क्षमताओं और प्रौद्योगिकी में सुधार की वजह से कुछ मॉडल तो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ोत्तरी तक बताते हैं. ज़ाहिर है, ज़रूरत सिर्फ़ मज़बूत इच्छाशक्ति की है.

feedback@chauthiduniya.com

हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के खाद्यान्न घोटाले पर ज़बरदस्त तल्ख़ टिप्पणी की कि पूरा प्रशासनिक तंत्र भ्रष्ट हो चुका है.

खा गए खाद्यान्न

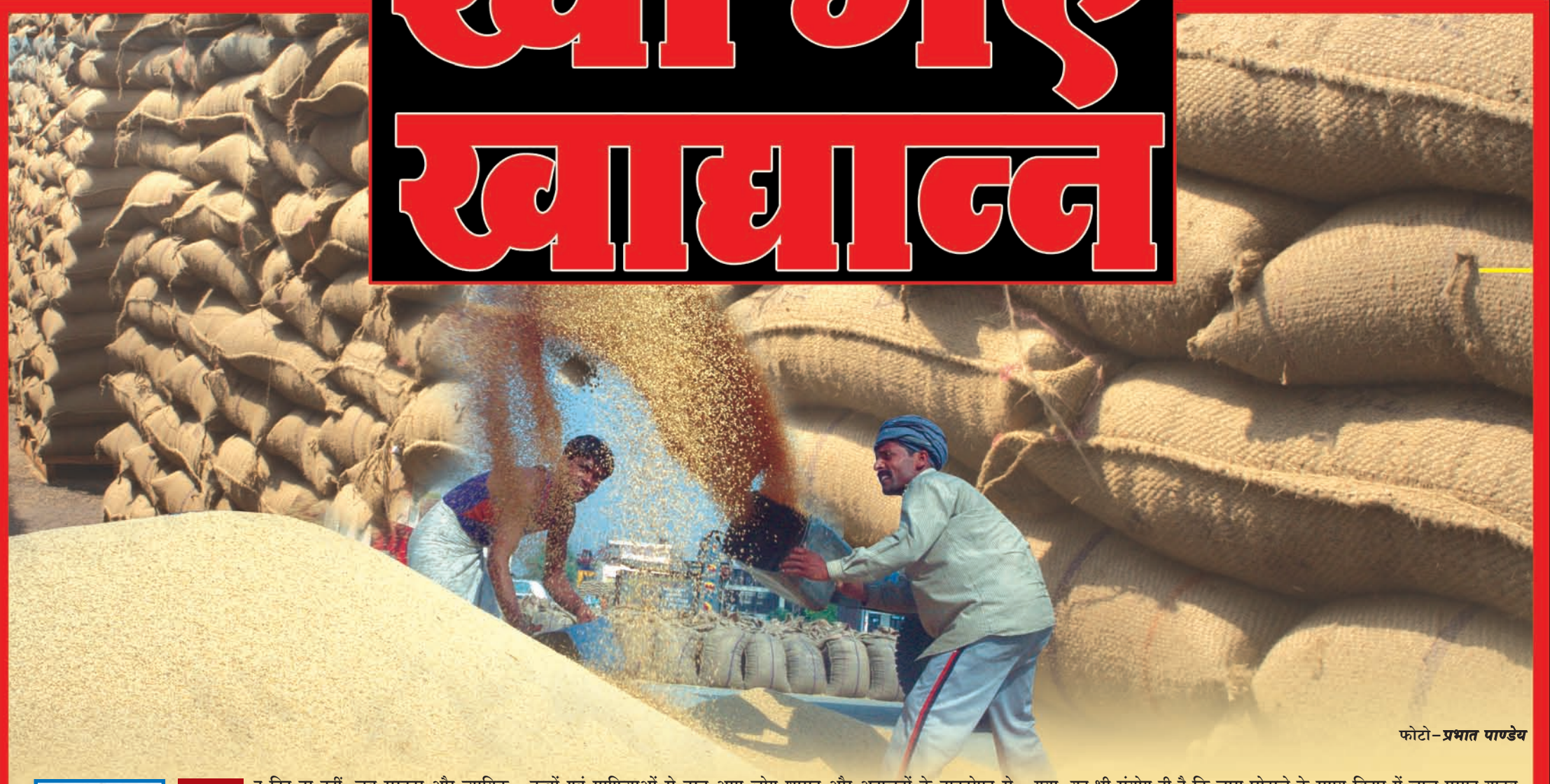

फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

प्रभात रंजन दीन

वह दिन दूर नहीं, जब सरकार और न्यायिक व्यवस्था से ऊबे देश के आम लोग क़ानून को अपने हाथ में ले लें, सार्वजनिक हत्याएं शुरू हो जाएं और देश फिर से विखंडित हो जाए. ऐसी गंभीर आशंका जताते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शासनिक और न्यायिक व्यवस्था की कमज़ोर नब्ज़ पर हाथ रखकर देश की विस्फोटक हालत को जैसे रोशनी में ला दिया है. हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि भ्रष्टाचार में लिप्त लोकसेवकों पर अभियोजन चलाने की स्वीकृति न देकर सत्ता में बैठे नेता ही भ्रष्टाचार का पालन-पोषण करते हैं. सीबीआई या दूसरी कोई भी जांच एजेंसी जांच का काम पूरा करके भ्रष्टाचार में लिप्त नेताओं या अधिकारियों के ख़िलाफ़ अभियोजन की स्वीकृति के लिए सरकार को दरख्वास्त देती है, लेकिन सरकार उसे दबाए बैठी रहती है. केंद्र का यह हाल है और राज्य सरकारों का भी यही हाल है. अभियोजन की स्वीकृति के सैकड़ों मामले लंबित पड़े हैं. उत्तर प्रदेश के खाद्यान्न घोटाले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य के प्रशासनिक तंत्र को आड़े हाथों लेते हुए एक बड़ा सवाल देश के सामने खड़ा कर दिया है, लेकिन बहस इस पर नहीं हो रही. बहस बरगदी भ्रष्टाचार की शाखाओं पर है, पत्तियों पर है, लेकिन विस्तार लेती, गहरे समाती जाती जड़ पर नहीं है.

खाद्यान्न घोटाले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अभियोजन की स्वीकृति को लेकर सत्ता-सरकार द्वारा किए जाने वाले विलंब के ख़िलाफ़ एक मानक निर्णय लिया है, जो सुप्रीमकोर्ट से लेकर देश की तमाम अदालतों के लिए नज़ीर होना चाहिए. हाईकोर्ट ने साफ-साफ कहा कि जांच एजेंसी द्वारा दाखिल अभियोजन स्वीकृति के आवेदन पर शासन ने अगर तीन महीने के भीतर निर्णय नहीं लिया तो वह स्वत: मंजूर मान लिया जाएगा और लिप्त अधिकारी के ख़िलाफ़ अभियोजन की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के न्यायाधीश देवी प्रसाद सिंह और एस सी चौरसिया का यह फ़ैसला भले ही एक मामले को लेकर आया, लेकिन इसने देश की समस्त न्यायिक व्यवस्था को दूरगामी संदेश दिया है. इस पर देश भर की अदालतें अडिग हुईं तो भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ हम वाकई एक ठोस क़दम आगे ले पाएंगे.

हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के खाद्यान्न घोटाले पर ज़बरदस्त तल्ख टिप्पणी की कि पूरा प्रशासनिक तंत्र भ्रष्ट हो चुका है. लेकिन यह विडंबना है कि एक सरकार जाती है और नई सरकार पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के घोटालों पर सख्ती बरतने की प्रतिबद्धता जताती है. उत्तर प्रदेश की मायावती सरकार ऐसा ही कर रही है. समाजवादी पार्टी की सरकार के कार्यकाल में हुए खाद्यान्न घोटाले को लेकर हाईकोर्ट की तल्खी पर मायावती सरकार भी सख्त कार्रवाई के संवाद दोहरा रही है. फिर दूसरी सरकार आएगी तो बसपा सरकार के कार्यकाल का पत्थर घोटाला सामने आएगा और उस पर इसी तरह तल्ख बयान जारी होंगे...और इसी तरह भ्रष्टाचार, घपले-घोटाले होते रहेंगे. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देश में लगातार बढ़ते भ्रष्टाचार के मद्देनज़र भ्रष्टाचार निरोधक क़ानून (प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988) को व्यवहारिकता और तात्कालिकता की कसौटी पर रखकर देखे जाने की हिमायत की है. हाईकोर्ट के इस ऐतिहासिक फ़ैसले के मोटे दस्तावेजों की गहराई में जाएं तो उनकी पंक्तियों के सूक्ष्म मायने देखकर आप चौंकेंगे. हाईकोर्ट ने साफ-साफ कह दिया है कि वह दिन अब दूर नहीं, जब देश को चारों तरफ़ से ग्रसते भ्रष्टाचार, असामाजिक तत्वों एवं माफ़ियाओं से त्रस्त आम लोग शासन और अदालतों के नाकारेपन से ऊबकर ख़ुद हथियार उठा लें. लिहाजा, क़ानून बनाने वाली संसद के लिए ज़रूरी है कि वह समय रहते भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ क़ानून को अधिक से अधिक सख्त बनाए और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की अप्रासंगिक धाराओं को प्रासंगिक बना ले. जेम्स बॉन्ड की फिल्म लाइसेंस टू किल का हवाला देते हुए अदालत को अगर यह कहना पड़ा कि लोकसेवा लाइसेंस टू करप्ट होकर रह गई है और प्रशासन में ईमानदारी अपवाद और भ्रष्टाचार नियम बन गया है तो आप स्थिति की गंभीरता के बारे में सोच सकते हैं. हाईकोर्ट ने देश के सामने साफ चुनौती दे दी है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा. भ्रष्टाचार का राक्षस गांधी, नेहरू, पटेल एवं अंबेडकर के सिद्धांतों को निगलने जा रहा हो तो ऐसे में क्या अदालतों को चुप्पी साधे बैठे रहना चाहिए? पर देश की अदालतें, मीडिया या अन्य सामाजिक मंच सब चुप्पी साधे बैठे हैं. कितनी विवशता है कि हाईकोर्ट को भी आख़िर यह कहना पड़ा कि हे ईश्वर, रास्ता दिखाओ...मदद करो.

जिस घोटाले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने अपनी तकलीफ और नाराज़गी ज़ाहिर की, ज़रा उसे भी देखते चलें. बिहार के चारा घोटाले और उत्तर प्रदेश के अनाज घोटाले में बहुत समानता है. दोनों घोटालों की मोडस-ऑपरेंडाई अगर ग़ौर से देखें तो आपको लगेगा कि चारा घोटाले के तौर-तरीक़ों को बहुत क़ायदे से सीखा गया और उसे अनाज घोटाले में आजमाया गया. यह भी संयोग ही है कि चारा घोटाले के समय बिहार में लालू प्रसाद यादव की सरकार थी और जब उत्तर प्रदेश में अनाज घोटाला परवान चढ़ा तो उस समय मुलायम सिंह यादव की सरकार थी. बसपा-भाजपा गठबंधन सरकार के कार्यकाल से शुरू हुआ अनाज घोटाला मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्रित्व काल में जवान होता हुआ मायावती के मुख्यमंत्रित्व काल तक पहुंचा है. अनाज घोटाला लगातार जारी है और अगर सख्ती से इसकी जांच हुई तो बड़ी संख्या में नेता, नौकरशाह, कर्मचारी और दलाल सलाखों के पीछे जाएंगे. बिहार में चारा हड़प करने में जिन ट्रकों पर ढुलाई दिखाई गई थी, उनके नंबर स्कूटर-मोटरसाइकिलों के पाए गए थे. उत्तर प्रदेश में भी अनाज की ढुलाई जिन ट्रकों पर दिखाई गई, उनके नंबर स्कूटर-मोटरसाइकिलों के पाए गए. अनाज घोटाला करने वाले अपेक्षाकृत अधिक शातिर निकले. उन्होंने उत्तर प्रदेश का अनाज बांग्लादेश, नेपाल और अफ्रीका के बाज़ारों तक बेच डाला. अभी उत्तर प्रदेश के 31 ज़िलों में 50 हज़ार करोड़ के खाद्यान्न घोटाले की आशंका है, लेकिन जिस तरह हाईकोर्ट ने सीबीआई को समेकित जांच का आदेश दिया है, उससे घोटाले की रकम और बढ़ सकती है, इसकी अधिक संभावना है. सरकार की विभिन्न योजनाओं का अनाज को सरकारी तंत्र और माफ़ियाओं ने खुले बाज़ार में बेचकर खा लिया. बीपीएल योजना, मिड डे मील एवं अंत्योदय समेत अन्य कई सरकारी योजनाओं के तहत आने वाले गेहूं और चावल को न केवल देश के अन्य राज्यों में चोरी-चोरी भेजा गया, बल्कि उसकी भारी तादाद में बांग्लादेश, नेपाल और अफ्रीकी देशों में तस्करी की गई. इसमें राज्य से लेकर केंद्र तक के अधिकारी-कर्मचारी शामिल रहे हैं, तभी तो रेलवे की रेकों में भर-भरकर चोरी का अनाज सीमाई राज्यों तक गया और वहां से लदकर विदेशों तक पहुंचा. उत्तर प्रदेश के 31 जिलों में 2002 से लेकर 2007 के बीच 5 करोड़, 10 लाख, 62 हज़ार, 792 मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन हुआ, लेकिन इससे कहीं अधिक 15 करोड़, 41 लाख, 89 हज़ार, 678 मीट्रिक टन माल मंडियों में पहुंच गया और खुले बाज़ार में बिक गया. साफ है कि केंद्र की विभिन्न योजनाओं के तहत मिलने वाला अनाज भी उन योजनाओं में न जाकर मंडी में बेच डाला गया. अभी तक जो भी आधी-अधूरी जांच हुई है, उसके मुताबिक़, प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत शाहजहांपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इलाहाबाद, फतेहपुर, प्रतापगढ़, ललितपुर, चित्रकूट, जौनपुर, चंदौली, महराजगंज, कुशीनगर, उन्नाव, रायबरेली, हरदोई, फ़ैजाबाद, गोंडा, बहराइच, सुल्तानपुर, बलिया, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, सोनभद्र, बस्ती, बलरामपुर, श्रावस्ती, सीतापुर और लखीमपुर खीरी आदि 31 जिलों में 50 हजार करोड़ के अनाज घोटाले का पता चला है. अदालत के ताज़ा आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के खाद्यान्न घोटाले के हतप्रभ करने वाले आंकड़ों के उजागर होने की प्रतीक्षा कीजिए.

prabhatranjandeen@chauthiduniya.com

घोटाले ने बलि भी ली

खाद्यान्न घोटाला करने वाले नेता, अधिकारी और माफ़ियाओं ने घोटाले में क़ानूनी रोड़ा अटकाने वाले लोगों की जान भी ली. लखीमपुर खीरी में एकाउंट अफसर एवं निरीक्षण दल के सदस्य डी के शुक्ला को विभागीय अधिकारियों ने जमकर प्रताड़ित किया और उन्हें निलंबित कर जांच की प्रक्रिया में बाधा डालने की आपराधिक कोशिश की. शुक्ला की मुहिम को वे फिर भी नहीं रोक पाए तो उनकी हत्या के बाद लाश तक ग़ायब करा दी गई. शुक्ला की लाश लखीमपुर खीरी में मिलने के बजाय रायबरेली ज़िले के गुरुबख्शगंज थाना क्षेत्र में पाई गई थी. इस हत्या के बरक्स कोई क़ानूनी कार्रवाई नहीं हुई. अब हाईकोर्ट ने उस हत्या के प्रति गंभीर रुख़ अपनाया है. सनद रहे, यह वही लखीमपुर खीरी है, जहां किस्म-किस्म के माफ़िया नेताओं के संरक्षण में फलते-फूलते हैं. यहीं भ्रष्टाचार का विरोध करने पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अधिकारी पी मंजूनाथ को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था. अनाज का घोटाला करने वाले माफ़िया राजनीतिक-प्रशासनिक संरक्षण पाकर इतने दुस्साहसी हो गए कि वे अनाज के गोदाम तक लूट लिया करते थे. सीतापुर ज़िले में चौकीदार की हत्या कर सरकारी गोदाम में भरा अनाज लूट लिया गया, लेकिन प्रशासन कुछ नहीं कर पाया. चौकीदार की हत्या करने के बाद अपराधी ट्रकों पर लूट का अनाज लदवाते रहे, लेकिन पुलिस सोई रही.

लखनऊ में जमे भ्रष्ट नौकरशाह

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में घोटालेबाज़ अधिकारियों का जमावड़ा है. इनका लखनऊ से कहीं बाहर तबादला नहीं किया जा सकता. सत्ता किसी भी पार्टी की हो, इन पर तबादले का कोई नियम काम नहीं करता. बरसों से ये लखनऊ में जमे विभिन्न महकमों को प्रदूषित करने में लगे हैं. खाद्य विभाग इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है. वर्ष 2002 से लेकर 2007 के बीच लखनऊ में 10 लाख 26 हज़ार 614 मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन हुआ, लेकिन आधिकारिक दस्तावेज बताते हैं कि इसी दरम्यान मंडी में 32 लाख 40 हज़ार 440 मीट्रिक टन गेहूं बिका. खाद्य विभाग के इन भ्रष्ट अधिकारियों से कोई पूछे कि उत्पादन से 22 लाख 13 हज़ार 826 मीट्रिक टन अधिक गेहूं मंडी में कैसे पहुंच गया? मिड डे मील योजना के तहत ग़रीब बच्चों के भोजन के लिए आया अनाज कहां गया? बीपीएल कार्डधारकों और अंत्योदय योजना का अनाज किनके पेट में चला गया?

मैं ही नहीं, तू भी है हम्माम में...

अनाज घोटाले पर ख़ुद को घिरता देख समाजवादी पार्टी ने बसपा सरकार पर घोटालों का आरोप तेज़ कर दिया. सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने खाद्यान्न घोटाले का ठीकरा बसपा-भाजपा गठबंधन की सरकार के मत्थे फोड़ा तो उनके भाई शिवपाल सिंह यादव ने मायावती सरकार के ताजा घोटालों की जांच की मांग कर डाली. शिवपाल यादव ने कहा कि सरकार का एक ताजा घोटाला हज़ार करोड़ का है, जिसमें मुख्यमंत्री के निर्देश पर गोपनीय तरीक़े से उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) की साहिबाबाद (गाजियाबाद) स्थित लगभग क़रीब नौ एकड़ ज़मीन एक कॉरपोरेट घराने को औने-पौने दामों में बेचने की तैयारी चल रही है. जबकि उस ज़मीन का मौजूदा बाज़ार मूल्य एक हज़ार करोड़ रुपये है. उक्त बेशक़ीमती ज़मीन को रफा-दफा करने के लिए गाजियाबाद के डीएम ने आनन-फानन दो दिनों में समिति का गठन कर दिया और समिति ने भी उक्त ज़मीन से बस अड्डा और वर्कशॉप हटाने की फ़ौरन सिफ़ारिश जारी कर दी. मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारी रोडवेज प्रबंधन पर उक्त भूमि को वापस कर देने का दबाव बना रहे हैं. नौ सौ करोड़ का वित्तीय घाटा झेल रहे परिवहन निगम को साहिबाबाद की वह ज़मीन वर्ष 2003 में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम ने 90 साल की लीज पर बसों के संचालन के लिए दी थी. सपा नेता ने कहा कि मायावती सरकार एक-एक करके सरकारी निगमों को हड़प रही है. उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की मिलें बेच दी गईं. राज्य सहकारी चीनी मिल संघ की मिलें और डिस्टलरी बेचने का प्रयास हो रहा है. मुख्यमंत्री ख़ुद ताज कॉरीडोर और आय से अधिक संपत्ति के मामले में फंसी हैं, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रही हैं. लोकायुक्त ने दो मंत्रियों को भ्रष्टाचार का दोषी पाया, पर कार्रवाई नहीं हो रही है. अंबेडकर उद्यान, रमाबाई पार्क, अन्य स्मारकों और नोएडा में निर्माण कार्यों में ज़बरदस्त घोटाले हुए, जिनका हिस्सा सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंच रहा है.

श्रम एवं रोज़गार राज्यमंत्री हरीश रावत के मुताबिक़, 31 मार्च तक दो लाख 88 हज़ार 462 बंधुआ मज़दूरों को मुक्त कराया जा चुका है

कब ख़त्म होगी बंधुआ मज़दूरी

फोटो-*प्रभात पाण्डेय*

फ़िरदौस ख़ान

आज़ादी के छह दशक बाद भी देश में बंधुआ मज़दूरी जारी है. हालांकि सरकार ने 1975 में एक अध्यादेश के ज़रिए बंधुआ मज़दूरी पर प्रतिबंध लगा दिया था, मगर इसके बावजूद सिलसिला आज भी जारी है. सरकार भी इस बात को मानती है कि देश में बंधुआ मज़दूरी जारी है. दूर जाने की बात नहीं, देश की राजधानी दिल्ली को ही लीजिए. पुलिस ने पिछले दिनों राजधानी के नबी करीम इलाक़े में बैग बनाने वाले एक कारखाने में काम करने वाले 22 बच्चों को छुड़ाया. इन बच्चों की उम्र सात से 12 वर्ष के बीच है. शिक़ायत मिलने पर केंद्रीय ज़िला टास्क फोर्स, एनसीओ सलाम बालक ट्रस्ट एवं ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क, दिल्ली पुलिस और श्रम विभाग के अधिकारियों-प्रतिनिधियों ने कारखाने पर छापा मारा था.

ये बच्चे बिहार के सीतामढ़ी, दरभंगा और नेपाल के बताए गए. अधिकारियों के मुताबिक़, इन बच्चों से प्रतिदिन 12 से 14 घंटे काम लिया जाता था.

श्रम एवं रोज़गार राज्यमंत्री हरीश रावत के मुताबिक़, 31 मार्च तक दो लाख 88 हज़ार 462 बंधुआ मज़दूरों को मुक्त कराया जा चुका है और इनके पुनर्वास के लिए 7015.46 लाख रुपये मुहैया कराए गए हैं. इसके अलावा ज़िलावार सर्वेक्षण कराने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को 676 लाख रुपये दिए जा चुके हैं. प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देशों के अनुरूप बंधुआ मज़दूर प्रणाली उन्मूलन क़ानून 1976 के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए श्रम एवं रोज़गार सचिव की अध्यक्षता में एक विशेष दल भी गठित किया गया है, जिसकी अब तक क्षेत्रवार 18 बैठकें हो चुकी हैं. सरकार ने 1980 में ऐलान किया था कि अब तक एक लाख 20 हज़ार 500 बंधुआ मज़दूरों को आज़ाद कराया जा चुका है. श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक़, देश में 19 प्रदेशों से 31 मार्च तक देश भर में दो लाख 86 हज़ार 612 बंधुआ मज़दूरों की पहचान की गई और उन्हें मुक्त कराया गया. नवंबर तक एकमात्र राज्य उत्तर प्रदेश में 28 हज़ार 385 में से केवल 58 बंधुआ मज़दूरों को पुनर्वासित किया गया, जबकि शेष 18 राज्यों में एक भी बंधुआ मज़दूर पुनर्वासित नहीं किया गया.

रिपोर्ट के मुताबिक़, देश में सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में 65 हज़ार 573 बंधुआ मज़दूरों की पहचान कर उन्हें मुक्त कराया गया. कर्नाटक में 63 हज़ार 437 और उड़ीसा में 50 हज़ार 29 बंधुआ मज़दूरों को मुक्त कराया गया. रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 19 राज्यों को 68 करोड़ 68 लाख 42 हज़ार रुपये की केंद्रीय सहायता मुहैया कराई गई, जिसमें सबसे ज़्यादा 16 करोड़ 61 लाख 66 हज़ार 94 रुपये राजस्थान को दिए गए. 15 करोड़ 78 लाख 18 हज़ार रुपये कर्नाटक और नौ करोड़ तीन लाख 34 हज़ार रुपये उड़ीसा को मुहैया कराए गए. इसी समयावधि के दौरान सबसे कम केंद्रीय सहायता उत्तराखंड को मुहैया कराई गई. उत्तर प्रदेश को पांच लाख 80 हज़ार रुपये की केंद्रीय सहायता दी गई. इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को 31 मार्च 2006 तक बंधुआ बच्चों का सर्वेक्षण कराने और जागरूकता सृजन कार्यक्रमों के लिए चार करोड़ 20 लाख रुपये दिए गए. श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय के महानिदेशक अनिल स्वरूप के मुताबिक़, बंधुआ मज़दूरों के पुनर्वास के लिए मुक्त कराने के तुरंत बाद हर श्रमिक को एक हज़ार रुपये की तात्कालिक सहायता, 19 हज़ार रुपये की पुनर्वास सहायता, आवास, कृषि भूमि एवं रोज़गार के साधन उपलब्ध कराने का प्रावधान है. राजस्थान के प्रमुख शासन सचिव श्रम एवं नियोजन मनोहरकांत के मुताबिक़, प्रदेश में 1976 से अब तक 11 हज़ार 319 बंधुआ मज़दूरों की पहचान की गई. इनमें से नौ हज़ार 112 मज़दूरों का पुनर्वास किया गया, जबकि 1467 को अन्य दूसरे राज्यों में पुनर्वास हेतु भिजवाया गया. राज्य में बंधुआ श्रमिक रखने वाले नियोजकों के ख़िलाफ़ 370 चालान पेश किए गए, जिनमें 137 प्रकरण निरस्त, 75 में जुर्माना, 56 प्रकरणों में सज़ा दी गई और 102 प्रकरणों में आरोपियों को दोष मुक्त किया गया. उन्होंने बताया कि राजस्थान में भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण अधिनियम के तहत 50 लाख रुपये उपकरण के रूप में प्राप्त किए गए तथा 7 हज़ार 497 श्रमिकों का पंजीयन किया गया.

जयपुर के सांगानेर में मज़दूरी का काम कर रहे सत्यप्रकाश ने बताया कि इससे पहले वह अलवर के सागर ईंट भट्ठे पर काम करता था, जहां उसे परिवार सहित बंधुआ मज़दूर के तौर पर रखा गया था. ठेकेदार न तो पूरी मज़दूरी देते थे और न उसे जाने देते थे. यहां मज़दूरों से 15 से 16 घंटे तक काम कराया जाता है. इन मज़दूरों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं. पिछले मई माह में बंधुआ मुक्ति मोर्चा की शिक़ायत पर एसडीएम, नायब तहसीलदार और श्रम निरीक्षक ने राजस्व स्टाफ के साथ भट्ठे पर छापा मारकर मज़दूरों को मुक्त कराया. सत्यप्रकाश के अलावा कई अन्य मज़दूरों को मुक्त कराया गया. प्रशासन ने उन्हें बकाया भुगतान के अलावा किराया भी दिलवाया. देश में ऐसे ही कितने भट्ठे और अन्य उद्योग धंधे हैं, जहां मज़दूरों को बंधुआ बनाकर उनसे कड़ी मेहनत कराई जाती है और मज़दूरी की एवज में नाममात्र पैसे दिए जाते हैं, जिनसे उन्हें दो वक़्त भरपेट रोटी भी नसीब नहीं हो पाती. अफ़सोस की बात यह है कि सब कुछ जानते हुए भी प्रशासन मूक दर्शक बना रहता है, लेकिन जब बंधुआ मुक्ति मोर्चा जैसे संगठन मीडिया के ज़रिए प्रशासन पर दबाव बनाते हैं तो अधिकारियों की नींद टूटती है और कुछ जगहों पर छापा मारकर वे रस्म अदायगी कर लेते हैं. श्रमिक सुरेंद्र कहता है कि मज़दूरों को ठेकेदारों की मनमानी सहनी पड़ती है. उन्हें हर रोज़ काम नहीं मिल पाता, इसलिए वे काम की तलाश में ईंट भट्ठों का रुख़ करते हैं, मगर वहां भी उन्हें अमानवीय स्थिति में काम करना पड़ता है. अगर कोई मज़दूर बीमार हो जाए तो दवा दिलाना तो दूर की बात, उसे आराम तक करने नहीं दिया जाता.

दरअसल, अंग्रेज़ी शासनकाल में लागू की गई भूमि बंदोबस्त प्रथा ने भारत में बंधुआ मज़दूरी के लिए आधार प्रदान किया था. इससे पहले तक ज़मीन को जोतने वाला ज़मीन का मालिक भी होता था. ज़मीन की मिल्कियत पर राजाओं और जागीरदारों का कोई दावा नहीं था. उन्हें वही मिलता था, जो उनका वाजिब हक़ बनता था और यह कुल उपज का एक फ़ीसदी होता था. किसान ही ज़मीन के स्वामी थे. हालांकि ज़मीन का असली स्वामी राजा था. फिर भी एक बार जोतने के लिए तैयार कर लेने के बाद मिल्कियत किसान के हाथ में चली गई. राजा के आधिराज्य और किसान के स्वामित्व के बीच किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं था. वक़्त के साथ राजा और राजत्व में परिवर्तन होता रहा, लेकिन किसानों की ज़मीन की मिल्कियत पर कभी असर नहीं पड़ा, राजा और किसान के बीच कोई बिचौलिया भी नहीं था. भूमि प्रशासन ठीक से चलाने के लिए राजा गांवों में मुखिया नियुक्त करता था, लेकिन वक़्त के साथ इसमें बदलाव आता गया और भूमि के मालिक का दर्जा रखने वाला किसान महज़ खेतिहर मज़दूर बनकर रह गया.

कहने को तो श्रम प्रणाली अधिनियम 1976 के लागू होने के साथ ही बंधुआ मज़दूरी पर पाबंदी लग चुकी है, लेकिन हक़ीक़त यह है कि श्रम क़ानूनों के लचीलेपन के कारण मज़दूरों के शोषण का सिलसिला जारी है. आज़ादी के इतने सालों बाद भी हमारे देश में मज़दूरों की हालत दयनीय है. शिक्षित और जागरूक न होने के कारण इस तबके की तरफ़ किसी का ध्यान नहीं गया. सरकार को चाहिए कि वह श्रम क़ानूनों का सख़्ती से पालन कराए, ताकि मज़दूरों को शोषण से निजात मिल सके. हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मज़दूर भी इस देश की आबादी का एक अभिन्न अंग हैं और देश के विकास का प्रतीक बनी गगनचुंबी इमारतों में उनका ख़ून-पसीना शामिल होता है.

feedback@chauthiduniya.com

राजधानी लखनऊ से लगे सीतापुर जनपद में शिवकुमार गुप्ता नामक बसपा नेता के यहां बड़ी मात्रा में नकली खाद मिलने की घटना एकलौती नहीं है.

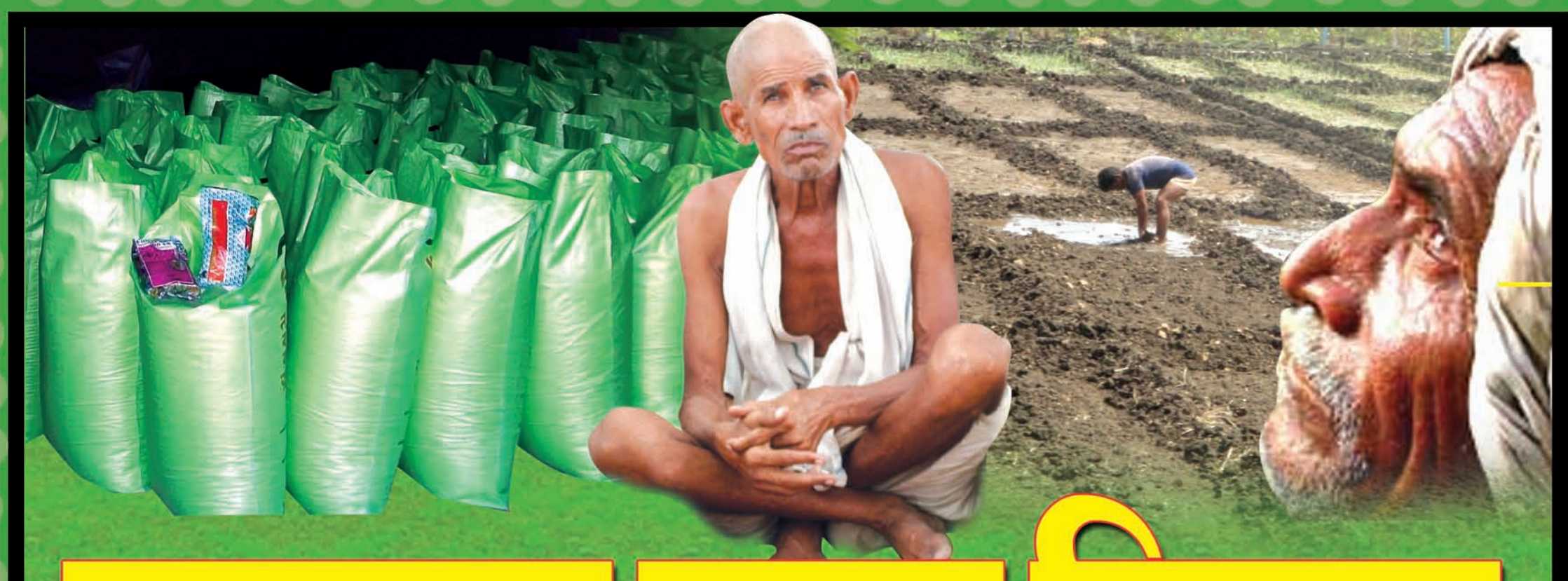

हाहाकार करता किसान

सुरेंद्र अग्निहोत्री

उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाक़ों में खाद-बीज को लेकर हाहाकार मचा हुआ है. गोरखपुर-देवरिया मार्ग पर चौरीचौरा स्थित कृषक भारती सेवा केंद्र पर खाद-बीज न बांटे जाने से आक्रोशित किसानों ने रास्ता जाम कर दिया. पुलिस ने किसानों पर लाठियां भांजी, जिससे कई किसानों को चोटें आईं. किसानों का आरोप है कि खाद-बीज की कालाबाज़ारी की जा रही है. यही हाल सिकरीगंज बेलघाट ब्लॉक के साधन सहकारी समिति कोटियां बिशुनी का है. किसान राधेश्याम, संतोष, रमाशंकर, अमरजीत, बलवंत, जयप्रकाश, संगम, रविंद्र प्रताप सिंह आदि का कहना है कि डेहरा टीकर न्याय पंचायत में कम से कम चार ट्रक खाद और चाहिए. पिपराइच क्षेत्र के गोदामों में पर्याप्त खाद होने के बाद भी ताले लटक रहे हैं.

गोला बाज़ार के किसानों ने प्रशासन को ज्ञापन देकर खाद-बीज उपलब्ध कराने की मांग की. पंचायत गोला में दस साधन सहकारी समितियां हैं, जिनमें गोपालपुर, बनवारपार, नीबीदूबे एवं भरोंह समितियां निष्क्रिय हैं. इन समितियों पर सिर्फ़ नकद खाद वितरण किया जाता है. रबी के सीजन में अभी तक नीबी दूबे, परसिया मिश्र और भरोंह की समितियों पर एक भी बोरी खाद-बीज नहीं है. शेष बची समितियां रानीपुर, ककरही, चिलवां, गोपालपुर, विशुनपुर राजा, बनवारपार और पकड़ी में 12 से 15 टन डीएपी उपलब्ध कराकर किसानों का मुंह बंद कर दिया गया और अब यहां बीज आना बंद हो गया. सिर्फ़ राजकीय कृषि इकाई गोला पर बीज का वितरण किया जा रहा है. उप ज़िलाधिकारी विजय नाथ पांडेय का कहना है कि उच्चाधिकारियों को पत्र लिखकर पर्याप्त मात्रा में खाद-बीज उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है. शासन-प्रशासन बीज और खाद उपलब्ध होने की घोषणा कर रहा है, परंतु गगहा विकास खंड में किसानों के चेहरे पर छाई उदासी असलियत की पोल खोल रही है. हटवा न्याय पंचायत की साधन सहकारी समिति पर अभी तक एक भी बोरी खाद और बीज का वितरण नहीं हुआ है, जबकि जीवकर, कतकौली, ताल देवन्ना में सैकड़ों एकड़ खेत अभी से बुआई के लिए तैयार हो चुके हैं. शत्रुघ्न, रमाकांत यादव, पंकज सिंह सहित दर्जनों किसान खाद-बीज के लिए इधर-उधर भटक रहे हैं. किसान नेता सबल सिंह ने कहा कि किसान अपने हक के लिए संघर्ष करने को आगे आएं. रकहट निवासी घनश्याम पांडेय, कृष्णानंद पांडेय, रियांव के हरीश सिंह, बेलकुर के राम प्रताप सिंह, डेमुसा के बाबूलाल निषाद, आशापार के मिश्रीलाल आदि का कहना है कि खाद- बीज के अभाव में खेत बेकार हो रहे हैं. महावनखोर समिति पर ताला लगा होने से खाद-बीज वितरण की व्यवस्था लड़खड़ा गई है. कैपियरगंज तहसील की चौमुखा क्षेत्रीय सहकारी समिति ज़िले की सबसे बड़ी सहकारी समिति है. इसके अंतर्गत 21 ग्रामसभाएं आती हैं. खाद की कालाबाज़ारी करने वाले दुकानदार ख़ूब लाभ उठा रहे हैं. अवैध रूप से पांच से छह सौ रुपये बोरी खाद बेचे जाने की सूचना है. डुमरियागंज क्षेत्र में किसान परेशान हैं. अधिकांश किसानों को खाद नहीं मिल रही है. किसी दिन खाद आती है तो उसकी मात्रा कम रहती है, जबकि किसानों की संख्या दुगनी-तीन गुनी अधिक रहती है. कुछ किसानों में खाद बांटकर वितरण यह कहकर बंद कर दिया जाता है कि खाद ख़त्म हो गई.

उमेश कुमार, राजेंद्र, महबूब आलम, अनीस अंसारी, संजय कुमार, मोहम्मद अजीज, सुनील मिश्र आदि का कहना है कि यदि समय रहते खाद उपलब्ध नहीं हुई तो खेतों की बुआई संभव नहीं हो पाएगी. उप ज़िलाधिकारी रामसूरत पांडेय ने ग्राम करहिया में दबिश देकर घनश्याम विश्वकर्मा की दुकान-गोदाम से 700 बोरी और अबुबकर की दुकान से 50 बोरी अवैध खाद बरामद की थी. दोनों के पास वैध लाइसेंस नहीं है. इनके विरुद्ध धारा इटवा थाने में मुक़दमा कायम कराया गया. छिबरामऊ, फर्रुखाबाद जनपद किसान सेवा सहकारी समिति पूर्वी में छह हज़ार सदस्य हैं, जबकि एक हज़ार बोरी खाद आई है. समिति से 46 गांव जुड़े हैं. बलरामपुर में खाद की उपलब्धता काग़ज़ों में भले ही चौकस हो, लेकिन किसान एक-एक बोरी खाद के लिए भटक रहे हैं. डीएपी खाद 700 रुपये में खुलेआम बेची जा रही है. ज़िला कृषि अधिकारी रजई राम कहते हैं कि रासायनिक उर्वरकों की कमी नहीं है. 15 नवंबर तक 3850 एमटी यूरिया, 2768 एमटी डीएपी, 900 एमटी एमओपी व 2210 एमटी एनपीके की मांग थी. मांग के सापेक्ष 4342 एमटी यूरिया, 3762 एमटी डीएपी, 700 एमटी एनओपी व 852 एमटी एनपीके उपलब्ध कराई गई. उरई जनपद के भारतीय किसान यूनियन के प्रतिनिधिमंडल ने ज़िलाधिकारी को ज्ञापन देकर सहकारी समितियों में खाद पहुंचाने की ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने की मांग की. भाकियू के ज़िलाध्यक्ष राजवीर सिंह जादौन के नेतृत्व में रामकुमार, लल्लूराम, परमेश्वरी दयाल, विनोद तिवारी, बृजेश राजपूत, रामलखन मास्टर ने डीएम को किसानों की समस्याओं से अवगत कराया.

राजधानी लखनऊ से लगे सीतापुर जनपद में शिवकुमार गुप्ता नामक बसपा नेता के यहां बड़ी मात्रा में नकली खाद मिलने की घटना एकलौती नहीं है. पिछले वर्ष बिजनौर में भी करोड़ों रुपये की नकली खाद बरामद हो चुकी है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश नकली खाद-बीज का गढ़ बन गया है. तमाम सरकारी दावों के बावजूद सीतापुर जनपद के तंबौर थाना क्षेत्र के ग्राम छतांगूर निवासी नरेश (37) और बांदा जनपद के गिरवा थाना क्षेत्र के ग्राम पैगंबरपुर निवासी राम बहोरी उर्फ जरैला (35) ने आर्थिक तंगी के कारण अपनी जान दे दी. राम बहोरी जैसे अनेक किसान हैं, जिनका नाम सरकार स्वीकार नहीं करती. बाढ़ और सूखे के चलते भुखमरी की कगार पर पहुंचे बुंदेलखंड-पूर्वांचल के किसान मौत को गले लगाकर पीपली लाइव के नत्था की तरह तथाकथित लोकप्रिय सरकारों को चुनौती दे रहे हैं. विशेष पैकेज के तहत यहां छोटे किसानों को नि:शुल्क स्प्रिंकलर योजना में बड़े पैमाने पर धांधली हुई. इंडियन जस्टिस पार्टी के प्रदेश महासचिव इशरार उल्लाह सिद्दीकी ने बांदा, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर, ललितपुर एवं जालौन में हुई लूट की जांच कराने की मांग की है. वर्ष 2009-10 में इस योजना के तहत 1040 किसानों को स्प्रिंकलर सेट वितरित किए गए थे. इस संबंध में तत्कालीन उप कृषिनिदेशक प्रसार बृजेश चंद्र से आख्या प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था. उनके द्वारा अवगत कराया गया कि शासनादेश के अनुसार संपूर्ण अनुदान की धनराशि अप्रैल 2010 तक जमा कर दी गई है. इस पर ज़िलाधिकारी को अवगत कराया गया कि उप कृषि निदेशक द्वारा फ़र्ज़ी आख्या प्रस्तुत की गई है. फलस्वरूप ज़िलाधिकारी ने वरिष्ठ कोषाधिकारी को जांच हेतु नामित किया था. जांच के दौरान उप कृषि निदेशक का तबादला हो गया. कोषाधिकारी द्वारा जांच में पाया गया कि आख्या वाकई फ़र्ज़ी थी एवं कई चेकों पर हस्ताक्षर ही नहीं किए गए थे. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने बताया कि बुंदेलखंड पैकेज के तहत किसानों को दिए जा रहे सिंचाई संसाधनों में लूट की जांच कराने के लिए प्रदेश सरकार से अनुरोध किया गया है और युवक कांग्रेस गांवों में लाभार्थी किसानों का भौतिक सत्यापन भी कर रही है. कांग्रेस नेता नम्रता तिवारी बताती हैं कि चित्रकूट से ललितपुर तक जन जागरण यात्रा के दौरान जलसंचन योजना के तहत वितरण किए गए स्प्रिंकलर एवं पंप सेट की सूची के ग्रामवार सर्वेक्षण में अनेक चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं.

feedback@chauthiduniya.com

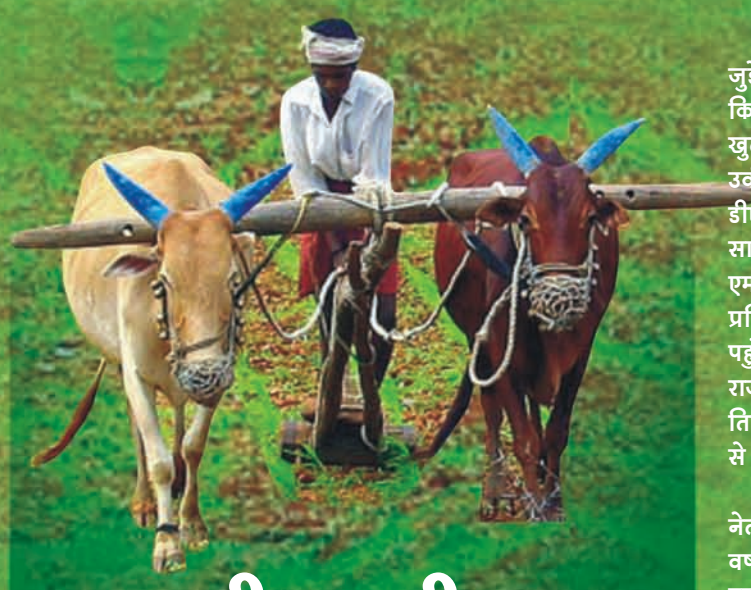

असली-नकली खाद की पहचान के तरीक़े

कृषि विशेषज्ञों ने रासायनिक खादों के असली-नकली होने की पहचान करने के लिए कुछ सरल एवं परंपरागत तरीक़े सुझाए हैं. उन्होंने बताया कि यूरिया की जांच के लिए हथेली पर थोड़ा सा पानी लेकर उसमें 10-15 दाने यूरिया के डालने पर शुद्ध यूरिया का घोल साफ बनता है. यदि तलछटी में सफेद पदार्थ जमा हो तो वह यूरिया मिलावटी या नकली होता है. इसी प्रकार शुद्ध डीएपी के दानों का आकार एकदम गोलाकर नहीं होता तथा यदि डीएपी के दानों को गर्म करने या जलाने पर उनका आकार साबूदाने की भांति फूलकर खिल जाता है और लगभग दोगुना हो जाता है तो वह शुद्ध है. शुद्ध डीएपी के दानों को फर्श पर बिखेर कर बलपूर्वक रगड़ने से आसानी से दाने नहीं टूटते है, जबकि अशुद्ध एवं मिलावटी डीएपी के दाने आसानी से टूट जाते हैं. विशेषज्ञों ने बताया कि यदि म्यूरेट ऑफ पोटाश को आग में डालने से वह पीले रंग की लौ से जले तो उसमें मिलावट की आशंका होती है. शुद्ध म्यूरेट ऑफ पोटाश पानी में पूरी तरह घुल जाता है और रंगीन एवं पोटाश का लाल भाग पानी के ऊपर तैरता रहता है. ऐसा न होने पर उसमें मिलावट हो सकती है. सिंगल सुपर फास्फेट की जांच के लिए बताया गया कि यह दानेदार पाउडर काला व भूरे रंग का होता है. यदि हथेली पर रगड़ने से दाने आसानी से टूट जाएं तो सुपर फॉस्फेट खाद शुद्ध होती है. ज़िंक सल्फेट की गुणवत्ता की जांच के लिए बताया गया कि इसका पानी में बना घोल म्यूरेट ऑफ पोटाश व यूरिया की तरह ठंडा न होकर हल्का गरम होता है. शासन द्वारा उर्वरक, बीज और कीटनाशकों के गुणवत्तायुक्त उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित कराए जाने के लिए उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985, बीज नियंत्रण आदेश 1983 और कीटनाशी अधिनियम 1968 बनाया गया है. इन आदेशों के उल्लंघन पर दंडात्मक कार्यवाही की जाती है. कृषि आदान सामग्री व्यवस्था अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे में आती है. इन नियमों का पालन न करना अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम की धारा-7 के प्रावधानों के अनुरूप दंडनीय अपराध है.

श्याबाओ का इस पुरस्कार के लिए चयन अपने आप में विवादों से घिरा रहा. पाकिस्तान ने चीन के विरोध का समर्थन किया और इस चयन को चीन को बदनाम करने वाला करार दिया.

मेघनाद देसाई

उदारवादी लोकतांत्रिक मूल्य और आतंकित ड्रैगन

आख़िरकार भारत ने एक अच्छा काम किया. इसने चीन के लू श्याबाओ को मिले नोबल पुरस्कार समारोह में शिरकत करने का फ़ैसला किया. भारत ने उन देशों से अलग रहने का निर्णय किया, जो इस मुद्दे पर चीन के समर्थन में थे और ली को मिलने वाले पुरस्कार का बहिष्कार कर रहे थे. इस मुद्दे पर चीन का साथ देने वाले ज़्यादातर देशों का रिकॉर्ड मानवाधिकार के मामले में बहुत ख़राब रहा है. मैं जानता हूं, इनमें से कई गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में भारत का गुट निरपेक्ष आंदोलन में बने रहना बेतुका लगता है. इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि सउदी अरब, क्यूबा और सोमालिया चीन के साथ खड़े नज़र आए. लेकिन विचित्र बात यह है कि चीन अंतरराष्ट्रीय अनुमोदन से कैसे डरा हुआ है? एक असहमत आदमी को मिले पुरस्कार से चीन इतना चिंतित है कि उसने इसके बहिष्कार की घोषणा कर दी और बाक़ी देशों से भी इसके लिए अपील की. यही कारण है कि चीन ने जल्दबाज़ी में कन्फ्यूशियस पुरस्कार की घोषणा कर दी. मुझे शक है कि हो न हो, अगले साल फिर एक किसी असंतुष्ट चीनी को कहीं नोबल पुरस्कार न मिल जाए.

शूद्र या दलित भारत में कभी भी समान अधिकार नहीं पा सके. मुस्लिम शासक भी इस्लाम के मूल तत्व समानता की बात लागू नहीं करा पाए. सच्चाई यह है कि औपनिवेशिक काल ने आर्थिक शोषण करने के बावजूद भारत को लोकतांत्रिक मूल्यों को आत्मसात करने के हिसाब से काफी कुछ दिया है. स्वतंत्रता के 63 सालों बाद भारत औपनिवेशिक काल की बुरी यादों को पीछे छोड़कर एक आर्थिक शक्ति बनने की दिशा में अग्रसर है.

मुझे याद आ रहा है कि कैसे 1958 में संयुक्त सोवियत रूस अपने नागरिक बोरिस पैसट्रेनक को उनके उपन्यास डॉक्टर शिवागो के लिए नोबल पुरस्कार मिलने पर डरा हुआ था. हमारे देश में भी स्थानीय कम्युनिस्ट हैं, जो इस उपन्यास को बिना पढ़े ही इसकी निंदा करते नहीं थकते. इनमें से बहुतों का कहना है कि बोरिस को पुरस्कार देने के पीछे अमेरिका की वह साम्राज्यवादी सोच थी, जो रूस को बदनाम करना चाहती थी. चूंकि ख़ुश्चेव ने ख़ुद ही स्टालिन के कृत्यों की घोर निंदा की थी, ऐसे में मैं नहीं जानता कि कोई और इससे ज़्यादा बुरा क्या कर सकता था. लेकिन एक ताक़तवर तानाशाही शासन की यही प्रकृति भी होती है. ये लोग आम आदमी की राय से डरते हैं. घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर दोनों पर. चीन ताक़तवर है, लेकिन इसका शासन एक भुरभुरे पदार्थ की तरह है. यदि आप थ्यानमेन टेप कार्यवाही को ग़ौर से पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि पोलित ब्यूरो के बूढ़े सदस्य कितने डरे हुए थे. उनमें इतना साहस नहीं था कि वे विरोध कर रहे नौजवानों से बातचीत कर सकें. चीनी शासन इतना डरा हुआ था कि उसने इन निहत्थे नौजवानों के ख़िलाफ़ टैंक का इस्तेमाल किया.

मतभेद के किसी मसले पर भारत में भी कई ऐसे क्षण आए हैं, जब सरकार ने सही क़दम नहीं उठाए. मक़बूल फ़िदा हुसैन को ज़बरन देश निकाला और हिंदू कट्टरवादियों द्वारा उनका अपमान एक लोमहर्षक घटना थी. सलमान रुश्दी की किताब को प्रतिबंधित करने, ऐसे लोगों द्वारा उसकी प्रतियां जलाने और दंगा भड़काने की कोशिश, जिन्होंने कभी उस किताब को पढ़ा ही नहीं, भी ऐसे ही उदाहरणों में शामिल हैं. इस तरह संविधान में मौलिक अधिकार की व्यवस्था के बाद भी सरकार ने किताब को प्रतिबंधित करके भारत को ऐसे देशों की कतार में शामिल कर दिया, जो प्रतिक्रियावादी माने जाते हैं. चीन के मामले में भी अगर देखा जाए तो यह हो सकता है कि भारत में भी कई लोग लू श्याबाओ की क़ैद को जायज़ समझते हों. लेकिन एक देश के रूप में भारत इस सोच का साथी नहीं बन सकता. भारत का संविधान एक ऐसा दस्तावेज है, जो उदारवादी लोकतांत्रिक परंपरा के प्रति भारत के लगाव को सुनिश्चित करता है. इसी परंपरा ने अंग्रेजों के ख़िलाफ़ भारत के शस्त्रविहीन आंदोलन को रास्ता दिखाया. असल में गांधी, नेहरू या कांग्रेस के ज़्यादातर नेताओं ने ब्रिटेन में रहने के दौरान ही इन मूल्यों को भलीभांति समझ लिया था. दादाभाई नौरोजी के जमाने से ब्रिटिश साम्राज्यवाद की मूल आलोचना इसी बात को लेकर थी कि भारत में ब्रिटिश शासन ग़ैर ब्रिटिश रूप से चल रहा था.

बहुत से लोगों के लिए इस धारणा को मानने में शर्म महसूस होती है कि मानवाधिकार पश्चिमी देशों से आया है, लेकिन बहुत कम लोगों को यह मालूम है

कि भारत के अतीत ने ही हमें बताया है कि कैसे लोगों के बीच समान अधिकार की बात की जा सकती है. अशोक या अकबर की सहनशीलता या जहांगीर का न्याय, ये ऐसी बातें हैं, जिन पर गर्व किया जा सकता है. लेकिन समग्र रूप से देखें तो भारतीय समाज ने इस समानता को कभी स्वीकार नहीं किया. शूद्र या दलित भारत में कभी भी समान अधिकार नहीं पा सके. मुस्लिम शासक भी इस्लाम के मूल तत्व समानता की बात लागू नहीं करा पाए. सच्चाई यह है कि औपनिवेशिक काल ने आर्थिक शोषण करने के बावजूद भारत को लोकतांत्रिक मूल्यों को आत्मसात करने के हिसाब से काफी कुछ दिया है. स्वतंत्रता के 63 सालों बाद भारत औपनिवेशिक काल की बुरी यादों को पीछे छोड़कर एक आर्थिक शक्ति बनने की दिशा में अग्रसर है. ज़रूरत सिर्फ़ उदारवादी लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण की है. अगर भारत इस चीज को खो देता है तो यह भी चीन की तरह एक आतंकित तानाशाह बन जाएगा.

feedback@chauthiduniya.com

महाशक्तियों की चुप्पी का राज़

राफिया ज़कारिया

बीते दस दिसंबर को जब ओस्लो में नोबल पुरस्कार समारोह का आयोजन चल रहा था, वहां एक कुर्सी खाली थी. लू श्याबाओ यानी 2010–शांति के लिए नोबल पुरस्कार के विजेता उस कुर्सी पर बैठने के लिए उपस्थित नहीं थे, क्योंकि वह चीन की एक जेल में अभी भी बंद हैं. श्याबाओ की पत्नी उनके नाम पर इस पुरस्कार को स्वयं ग्रहण कर सकती थीं, लेकिन उन्हें भी उनके घर में ही चीनी अधिकारियों ने नजरबंद कर दिया था. पाकिस्तान सहित 18 देश चीन के साथ खड़े नज़र आए, जो इस पुरस्कार समारोह में शामिल नहीं हुए. श्याबाओ 11 साल की सज़ा काट रहे हैं. उनका अपराध यह है कि उन्होंने चैप्टर 8 नामक घोषणापत्र लिखा, जिसमें चीन में मानवाधिकार

एक आम चीनी प्रोफेसर, जो चीन में बहुत प्रसिद्ध नहीं था, अपने चीनी राज्य का विरोध करने और जेल जाने की वजह से आज पूरे विश्व में लोकतंत्र का चेहरा बन गया है और पूरी दुनिया के सामने चीन की पोल खुल गई है. जब चीन की बदनामी का पैकेज नोबल कमेटी के हाथों तैयार किया जा रहा था, तभी अमेरिका द्वारा विकीलीक्स का मुंह बंद करने के लिए जुलियन असांजे के विरुद्ध झूठा मामला बनाने की कोशिश चल रही थी.

न होने और एक दल के शासन का विरोध किया गया. इस कारण उन पर राज्य के विरुद्ध जंग छेड़ने का आरोप लगा दिया गया. 8 दिसंबर, 2008 को यह घोषणापत्र छपने के दस घंटे बाद ही श्याबाओ को जेल में डाल दिया गया. श्याबाओ 1989 में थ्यानमेन चौराहे पर हुए नरसंहार के विरोधियों में अव्वल थे और छात्रों के नेता भी. उन्हें मात्र तीन घंटे में देशद्रोही करार दिया गया, एक ऐसे मुकदमे में, जिसमें उनके वकीलों को उनकी तरफ़ से दलील देने का भी मौका नहीं दिया गया. ध्यान देने की बात है कि नोबल पुरस्कार मिलने के बाद से उनके और उनकी पत्नी के कुशल क्षेम की कोई सूचना नहीं है.

श्याबाओ का इस पुरस्कार के लिए चयन अपने आप में विवादों से घिरा रहा. पाकिस्तान ने चीन के विरोध का समर्थन किया और इस चयन को चीन को बदनाम करने वाला करार दिया. यह याद रखना चाहिए कि चीन एक ऐसा देश है, जो सेंसरशिप और राजनीतिक विरोध की हत्या के लिए करोड़ों रुपये ख़र्च करता है. लगभग 30 हज़ार सीक्रेट पुलिस उसके इस काम को अंजाम देती है. यह पुलिस नित्य नए सॉफ्टवेयर के ज़रिए सारे ब्लॉगर्स और विश्लेषकों का मुंह बंद कर देती है. अब तक चीन यह समझता था कि विरोध का मुंह बंद कर देने से और अपने नागरिकों को अंधेरे में रखकर वह अपनी इस नीति में सफल हो जाएगा, परंतु नोबल जैसे बड़े पुरस्कार के लिए श्याबाओ का चयन इस बात पर पानी फेर देता है. एक आम चीनी प्रोफेसर, जो चीन में बहुत प्रसिद्ध नहीं था, अपने चीनी राज्य का विरोध करने और जेल जाने की वजह से आज पूरे विश्व में लोकतंत्र का चेहरा बन गया है और पूरी दुनिया के सामने चीन की पोल खुल गई है. जब चीन की बदनामी का पैकेज नोबल कमेटी के हाथों तैयार किया जा रहा था, तभी अमेरिका द्वारा विकीलीक्स का मुंह बंद करने के लिए जुलियन असांजे के विरुद्ध झूठा मामला बनाने की कोशिश चल रही थी. जब बात अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आती है तो अमेरिका भी चीन से बहुत अलग दिखाई नहीं पड़ता. ग़ौरतलब है कि अमेरिका में सरकारी दस्तावेजों को लीक करने वाले अफसरों के विरुद्ध सख्त क़ानून हैं, लेकिन वहां ऐसे भी क़ानून हैं, जो एक बार ऐसे दस्तावेज मीडिया जगत में आ जाने पर उन्हें छापने की स्वतंत्रता देते हैं. इस आधार पर जुलियन असांजे के विरुद्ध कोई मुकदमा नहीं बनता, क्योंकि पूर्व सीआईए इंस्पेक्टर जनरल फ्रेडरिक हिड्स के अनुसार, ऐसा कुछ भी सरकार के पास नहीं है, जो असांजे को ब्रैडली मैनिंग नामक सिपाही से जोड़ सके. यह वही सिपाही है, जिस पर विकीलीक्स को सरकारी दस्तावेज चुराकर देने का आरोप है. एक और मौका अमेरिकी सरकार के पास अभी बाकी है, जिससे जुलियन असांजे के विरुद्ध मामला दर्ज किया जा सकता है, जासूसी एक्ट 1917. इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के ख़िलाफ़ किसी भी व्यक्ति के पास अनाधिकृत रूप से पाया गया कोई भी दस्तावेज़ उसे जासूस बना देता है. लेकिन मज़े की बात यह है कि आज तक इस एक्ट के तहत जितने भी मुकदमे दायर किए गए, वे सब ख़ारिज़ हो गए, क्योंकि अमेरिकी न्याय व्यवस्था प्रेस की स्वतंत्रता को बचाने में तत्पर रही है. इसी कारण जुलियन असांजे कदाचित आज भी सुरक्षित हैं.

पाकिस्तान जैसे ग़रीब देश के लिए चीन या अमेरिका का पिछलग्गू बनना इन हालात में ठीक नहीं, जबकि उक्त देश अपनी ही धरती पर राजनीतिक विरोध और सामाजिक स्वतंत्रता पर हर प्रकार से अंकुश लगाने में जुटे हैं. पहले तो ये महा शक्तिशाली देश वर्चुअल सूचना का आधार बने इंटरनेट पर किसी प्रकार का कोई अंकुश न होने पर दुःख जताते हैं, इसलिए कि इंटरनेट पर सूचना के विस्तार की कोई सीमा नहीं है. दूसरी ओर ऐसे काम कर देते हैं, जो सदैव इन्हें नीचा दिखाते हैं और स्वतंत्रता के लिए काम करने वालों को जनता का हीरो बना देते हैं. इन बातों को देखते हुए यह कहना बिल्कुल उचित होगा कि जब किसी राष्ट्र के समक्ष ऐसी परिस्थिति आ जाए, जैसी अमेरिका के सामने विकीलीक्स को लेकर आई या चीन के सामने श्याबाओ को लेकर, तो उसे बोलने की स्वतंत्रता को जनता के सामने नहीं नकारना चाहिए. होना तो यह चाहिए कि ऐसी अवस्था में वह देश स्वतंत्रता को अवरुद्ध करने के बजाय उसे बढ़ावा दे और ऐसी बातों को तूल देने से बचे.

(लेखिका संवैधानिक विधि और राजनैतिक दर्शन की प्रोफेसर हैं)

feedback@chauthiduniya.com

नीतीश की जीत के मायने

नीतीश कुमार का जीतना वास्तव में स्थिरता की ओर बढ़ना है, यह सीधे-सीधे साफ-सुथरे और ईमानदार नेतृत्व का चयन है, जिससे भाजपा को भी सबक लेना चाहिए और कांग्रेस को तो आपने सही निष्कर्ष दे ही दिया है.

-पी सी राय, ई-मेल से.

मीडिया निष्पक्ष नहीं

बिहार में नीतीश कुमार के साथ भाजपा की भी ऐतिहासिक जीत हुई है, पर उस पर आपने कुछ नहीं लिखा. मीडिया निष्पक्ष नहीं रहा. आप भी निष्पक्ष नहीं हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है.

-अरुण, ई-मेल से.

धन्य बिहारी

चालाकी इक ना चली, चला न कुनबावाद,
जातिवाद को भूलकर, रखा काम को याद.
रखा काम को याद, धन्य हैं सभी बिहारी,
दिया यही संदेश, मिटें अब भ्रष्टाचारी.
कहे ओम कविराय, सीख लें सूबे बाक़ी,
लोग चाहते काम ,चले न अब चालाकी.

-ओम वर्मा, ई-मेल से.

घोटाले पर घोटाले

13-19 दिसंबर के अंक में भारतीय व्यवस्था का काला सच लेख पढ़ा, बढ़िया लगा. घोटाले में शामिल सभी चेहरे जनता को दिखाने और उनके बारे में बताने के लिए आपको धन्यवाद. सही लिखा गया है कि नीरा राडिया के टेप ने पूरी सरकार को हिलाकर रख दिया है. दिनोंदिन नए खुलासे हो रहे हैं. राजनीतिज्ञों और उद्योगपतियों के बीच दूरी बनाई जानी चाहिए.

-अमन रावत, लखनऊ, उत्तर प्रदेश.

भ्रष्टाचार खत्म हो

आदर्श सोसाइटी घोटाले पर आधारित आलेख पढ़ा. हर घोटाले और भ्रष्टाचार पर नेता चुप रहते हैं और अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश करते रहते हैं. चारों तरफ़ घोटाला ही घोटाला सुनने को मिलता है. सुप्रीमकोर्ट अगर इनसे जवाब मांगता है तो भी ये जल्दी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं होते.

-राहुल कुमार, हुगली, पश्चिम बंगाल.

नैतिक दायित्व

जब हम कोई विशेषाधिकार प्राप्त कर लेते हैं तो यह भूल जाते हैं कि हमारा जनता और देश के प्रति भी कोई नैतिक दायित्व बनता है. हम सभी वैभव और धन की चाहत में अपने नैतिक दायित्वों को भूल जाते हैं. जो कुछ आजकल देखने को मिल रहा है, वह इसी का नतीजा है. हम मानव जाति में जन्म लेकर जानवर क्यों बनते जा रहे हैं?

-नेम सिंह, ई-मेल से.

रामदेव और आंदोलन

देश के हर कोने से रोज किसी न किसी घोटाले की ख़बर सुनने को मिल जाती है. कोई इसके बारे में कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है, सभी अपना पल्ला झाड़ने में लगे हुए हैं. इन घोटालों को लेकर बाबा रामदेव आंदोलन करने की बात कर रहे हैं. बाबा शायद भूल गए हैं कि योग और राजनीति में बहुत फ़र्क है.

-राजकुमार, गुना, मध्य प्रदेश.

सच्चाई सामने आई

विकीलीक्स ने पाकिस्तान की पोल खोलकर सामने रख दी है. यह बात खुलकर सामने आ गई है कि आतंकवाद पाकिस्तान की विदेश नीति का एक अहम अंग है, जिसके ज़रिए वह अमेरिका और भारत को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता रहता है.

-राम किशन शर्मा, मधुबनी, बिहार.

आप अपने स्वतंत्र विचार तथा प्रतिक्रियाएं हमें इसी पते पर भेजें. संपादक, चौथी दुनिया, एफ-2, सेक्टर-11 नोएडा, (उत्तर प्रदेश) पिन-201301

ई-मेल पता : feedback@chauthiduniya.com

जब तोप मुक़ाबिल हो

संतोष भारतीय

सुरेंद्र मोहन सच्चे समाजवादी थे

छोटे लोहिया यानी जनेश्वर मिश्र के निधन के बाद इस देश में समाजवादी आंदोलन की आख़िरी कड़ी के रूप में रह गए थे सुरेंद्र मोहन, लेकिन यह आखिरी कड़ी भी टूट गई. 17 दिसंबर की सर्द सुबह. नियति ने प्रख्यात समाजवादी नेता सुरेंद्र मोहन को हमसे छीन लिया और इस तरह समाजवादी आंदोलन की अंतिम याद भी हमसे छिन गई. उनके निधन के साथ ही प्रतिबद्ध, स्पष्टवक्ता और सत्ता के लालच से कोसों दूर रहने वाले नेताओं की एक छोटी, लेकिन मज़बूत कतार भी ख़त्म हो गई. जानने वाले उन्हें समाजवाद की डायरेक्टरी कहते थे. कुछ दिनों पहले ही पता चला था कि सुरेंद्र जी लोहिया के सपनों को एक बार फिर से पूरा करने की तैयारी में लगे हैं. दरअसल, वह राजिंदर सच्चर के साथ लोहिया के विचारों से जुड़ी एक समाजवादी पार्टी का गठन करने वाले थे, लेकिन ईश्वर को शायद यह मंजूर नहीं था.

चार दिसंबर, 1926 को अंबाला में जन्मे सुरेंद्र मोहन समाजवादी आंदोलन से बहुत गहरे तक जुड़े हुए थे. लोकनायक जय प्रकाश नारायण एवं डॉ. राम मनोहर लोहिया के निकट सहयोगी रहे सुरेंद्र मोहन सही मायनों में पक्के समाजवादी थे, जिन्होंने हमेशा जनता की आवाज़ को सत्ता के गलियारों तक पहुंचाने का काम किया. ज़रूरत पड़ी तो सत्ता के ख़िलाफ़ आवाज़ भी बुलंद की, जेल गए. 1975 में देश में जब आपातकाल लगा था तो उस दौरान वह क़रीब 19 महीने जेल में रहे. जेल में रहने के दौरान ही उन्हें ज़बरदस्त हृदयाघात पहुंचा, तब जय प्रकाश नारायण ने उनसे कहा कि वह पेरोल पर बाहर आ जाएं, ताकि उनका समुचित इलाज हो सके, लेकिन सुरेंद्र जी ने इस प्रस्ताव को नहीं माना. 1977 में जब जनता पार्टी का गठन हुआ, तब उन्हें पार्टी का महासचिव और प्रवक्ता बनाया गया. मोरार जी देसाई जब प्रधानमंत्री बने, तब उन्हें जनता पार्टी सरकार में मंत्री बनने का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया. सुरेंद्र मोहन 1978 से 1984 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे. 1996–98 में खादी ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष भी रहे. पूर्व प्रधानमंत्री मोरार जी देसाई, चंद्रशेखर, विश्वनाथ प्रताप सिंह, इंद्र कुमार गुजराल एवं एच डी देवेगौड़ा उनके अभिन्न मित्र थे. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान जैसे अनेक नेता राजनीति में उनके शिष्य रहे. लेकिन सत्ता में बैठे लोगों से इतने अच्छे संबंधों के बावजूद उन्होंने कभी भी अपने लिए कुछ नहीं मांगा.

और, शायद यही वजह थी कि जब भी उन्हें लगा कि लोहिया और जेपी के नाम पर राजनीति करने वाले लोग रास्ते से भटक रहे हैं, तब उन्होंने ऐसे नेताओं को बेझिझक सरेआम डांट भी पिलाई. उन्होंने बिहार में जेपी आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं को पेंशन देने के नीतीश कुमार के फ़ैसले की भी कड़ी आलोचना की. सुरेंद्र मोहन ने कहा कि यह सही है कि जेपी आंदोलन देश की एक बड़ी राजनीतिक घटना थी और आज़ादी के बाद ऐसा आंदोलन नहीं हुआ था, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उसके आंदोलनकारियों को आज पेंशन दी जाए. आज ज़रूरत है जेपी के सपनों को पूरा करने की. उन्होंने कहा कि इमरजेंसी के बाद दिल्ली सरकार ने जेपी आंदोलन के ऐसे आंदोलनकारियों को 25 हज़ार रुपये की एकमुश्त राशि प्रदान की थी, जो जेल गए थे, पर पेंशन देना उचित नहीं है. यह एक ग़लत परंपरा की शुरुआत है.

सुरेंद्र मोहन समाजवादी आंदोलन के ऐसे स्तंभ थे, जिन्होंने अपने जीते जी इस आंदोलन की तपिश को ख़त्म नहीं होने दिया. 2010 में ही उनकी अध्यक्षता में लोहिया जन्मशती समारोह दिल्ली के मावलंकर हॉल में मनाया गया. एक सुर में समाजवादियों और साम्यवादियों ने इस बात को माना कि आज लोहिया और उनके विचारों की प्रासंगिकता कितनी ज़्यादा है. यह सुरेंद्र मोहन का ही कमाल था कि एक मंच पर बैठे अलग-अलग विचारधारा के नेताओं ने लोहिया की सप्तक्रांति को फिर से दोहराए जाने की वकालत की. सीपीआई नेता ए बी वर्धन ने तो यहां तक कहा कि अब वक़्त आ गया है, जब समाजवादियों और साम्यवादियों को एक साथ मिलकर लोहिया की क्रांति को आगे बढ़ाया चाहिए. लेकिन दुर्भाग्य से सुरेंद्र मोहन जी को नियति ने इतना वक़्त नहीं दिया कि वह इस सपने को पूरा कर सकते. सुरेंद्र मोहन जी वर्तमान राजनीति और राजनीतिक रवैये से ज़्यादा ख़ुश नहीं थे. बिहार में नीतीश कुमार जब लगातार अपने प्रशंसकों की संख्या बढ़ा रहे थे, तब सुरेंद्र मोहन जी का मानना था कि प्रशंसक पार्टी के भीतर के सहयोगियों का स्थान नहीं ले सकते. नीतीश कुमार को अपनी सीमाओं का भी बख़ूबी अंदाज़ा है, यह इस बात से भी साबित होता है कि उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी महत्वाकांक्षा से बार-बार इंकार किया. ऐसी खरी बात बोलने के लिए नेताओं में नैतिक साहस होना चाहिए, जो आज के दौर में सुरेंद्र मोहन जी जैसे लोगों के पास ही बचा था.

सुरेंद्र मोहन जी का मानना था कि प्रशंसक पार्टी के भीतर के सहयोगियों का स्थान नहीं ले सकते. नीतीश कुमार को अपनी सीमाओं का भी बख़ूबी अंदाज़ा है, यह इस बात से भी साबित होता है कि उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी महत्वाकांक्षा से बार-बार इंकार किया. ऐसी खरी बात बोलने के लिए नेताओं में नैतिक साहस होना चाहिए, जो आज के दौर में सुरेंद्र मोहन जी जैसे लोगों के पास ही बचा था.

सुरेंद्र मोहन जी एक दार्शनिक और लेखक भी थे. सरकार की नीतियों और राजनीतिक दलों के क्रियाकलापों पर वह पैनी नज़र रखते थे. जिस तरह राजनीति में वह साफ़-साफ़ बोलते थे, उसी तरह उनकी लेखनी भी धारदार थी. सुरेंद्र मोहन जी वर्तमान आर्थिक नीतियों के विरोधी थे. उन्हें लगता था कि इससे देश में उपभोक्तावाद के दौर में समाज को झोंक दिया गया है. उदारवाद और मुक्त अर्थव्यवस्था के बारे में उनका मानना यह था कि भारत में इस व्यवस्था का नुकसान ग़रीबों को होगा और सारा फ़ायदा देश के उद्योगपति उठा ले जाएंगे. शहर और गांव, ग़रीब और अमीर में इतना ज़्यादा अंतर हो जाएगा, जहां से सामाजिक समानता का लक्ष्य ओझिल हो जाएगा. अपने लेखों के ज़रिए सुरेंद्र जी राजनीतिक दलों और नेताओं से कठिन सवाल पूछा करते थे. वह एक्सप्रेस वे और एसईजेड के नाम पर किसानों की ज़मीन के अधिग्रहण के ख़िलाफ़ रहे.

बहरहाल, सुरेंद्र जी को हमारी ओर से सच्ची श्रद्धांजलि तो यही हो सकती है कि हम उस जनता की आवाज़ बने, जिसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता और हम ऐसा ही करेंगे. बारी वैसे नेताओं की है, जो ख़ुद को लोहिया और जेपी का शिष्य साबित करते हैं, लेकिन सत्ता के लालच में समाजवाद और सच्चे समाजवादियों को भूल गए हैं. ज़रूरत इस बात की है, एक बार फिर से समाजवाद और समाजवादी आंदोलन को याद किया जाए. सच्चे मन से. और उस रास्ते पर आगे बढ़ने का प्रण किया जाए. शायद सुरेंद्र मोहन जी के लिए इससे सच्ची श्रद्धांजलि और कुछ नहीं होगी.

संपादक
editor@chauthiduniya.com

कितना और क्यों ज़रूरी है मीडिया ट्रायल

सौमित्र मोहन

मीडिया ट्रायल, इस बहुप्रचारित शब्द को लेकर काफी लंबी-चौड़ी बहस हो चुकी है और अभी भी हो रही है. इसके पक्ष और विपक्ष में ख़ूब सारे तर्क भी दिए जा रहे हैं. दरअसल, किसी भी निर्णय तक पहुंचने से पहले हमें इससे जुड़ी हर एक बारीक़ी और अर्थ को समझना होगा. सबसे पहले सवाल यह उठता है कि मीडिया ट्रायल जैसा शब्द आया कहां से? यह एक नई अवधारणा है या तबसे इसका अस्तित्व है, जबसे चौथे स्तंभ की शुरुआत हुई? कोई यह तर्क भी दे सकता है कि मांग के हिसाब से ही इस दुनिया में कोई चीज अस्तित्व में आती है. इसलिए यदि मीडिया ट्रायल शुरू हुआ तो इसके लिए व्यवस्था में शामिल संस्थाओं की निष्क्रियता या असफलता जैसे तर्क ही सूझते हैं. एक ऐसे वक़्त में, जब अन्य संस्थाएं असफल हो रही हों, तब न्यायपालिका की तरह मीडिया ख़ुद को सामने खड़ा कर अपने तरह से उस शून्य को भरने की कोशिश करता है, जो अन्य संस्थाओं की असफलता की वजह से पैदा हुआ है और इस तरह न्यायिक सक्रियता या मीडिया ट्रायल जैसी अवधारणाओं का जन्म होता है. और हां, मीडिया ट्रायल कोई नई अवधारणा नहीं है, बल्कि काफी समय से यह चला आ रहा है. दुनिया भर में हुए आंदोलनों या ख़ुद भारत के स्वतंत्रता संग्राम में प्रेस की भूमिका को कौन नकार सकता है. या आपातकाल के दौरान प्रेस ने जो भूमिका निभाई, उसे कौन भूल सकता है? इसलिए आज मीडिया ट्रायल जैसा शब्द चौंकाता नहीं है.

मीडिया ट्रायल का अस्तित्व पारंपरिक न्याय व्यवस्था, ग़ैर सरकारी संगठनों, कई दबाव और हित समूह तथा नागरिक समाज के साथ मिलकर काम करता है. मीडिया ट्रायल आम आदमी की आकांक्षा और जनमत को अभिव्यक्ति देने का एक माध्यम है. मीडिया प्राय: किसी पक्षपातपूर्ण ज्यूडिसियल ट्रायल के समर्थन या विरोध या कार्यपालिका के किसी खास निर्णय के समर्थन या विरोध में आगे आता है. पिछले दिनों कुछ चर्चित न्यायिक या भ्रष्टाचार के मामले मीडिया के माध्यम से ही आम आदमी की नज़र में आए. मीडिया की वजह से ही किसी खास मामले में हुए भ्रष्टाचार की ख़बर आम आदमी तक पहुंची. जेसिका लाल, प्रियदर्शिनी मट्टू, रिजवानुर रहमान, शिवानी भटनागर, रुचिरा गिरहोत्रा जैसे मामले या सुकना भूमि घोटाला, आदर्श सोसाइटी घोटाला, आईपीएल में भ्रष्टाचार, कई सारे स्टिंग ऑपरेशन, ये सारे खुलासे मीडिया की वजह से ही संभव हो सके. ये सारे ऐसे मामले हैं, जिनमें मीडिया ने जनता की आवाज़ कार्यपालिका और न्यायपालिका तक पहुंचाई और सफलतापूर्वक कई निर्णयों को बदलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

हालांकि मीडिया ज़्यादातर मामलों में न्यायपूर्ण दिखता है, लेकिन कुछ ऐसे भी मामले हैं, खासकर वे, जो ख़ुद मीडिया हाउसों के हितों से जुड़े हों, वहां मीडिया पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगा है. यह भी आरोप लगता रहा है कि मीडिया अपने व्यापारिक हितों को साधने के लिए एक अलग तरह की पत्रकारिता करने लगा है. कई बार अपने मालिकों के हित का ध्यान रखते हुए कुछ ख़बरें ज़बरन प्लांट कराई जाती है. कभी-कभी तो कोई ख़बर किसी पत्रकार की व्यक्तिगत सोच, उसके पक्षपातपूर्ण व्यवहार और छुपे हित को दर्शाती हुई नज़र आती है. लेकिन दु:खद बात यह है कि मीडिया भावना में बहकर किसी घटना का विश्लेषण करता है या उस पर निर्णय लेता है और इस चक्कर में मामले से जुड़े तथ्य गौण हो जाते हैं. कभी-कभी किसी एक ही मुद्दे पर अलग-अलग मीडिया हाउस अलग-अलग प्रतिक्रिया देने लगते हैं. इस देश में मीडिया ने एक खास राज्य सरकार की कटु आलोचना की, क्योंकि सत्ता पक्ष के एक विधायक के साथ स्थानीय लोगों ने दुर्व्यवहार किया था. मीडिया ने यह कहकर आलोचना की कि सरकार चक्रवात प्रभावित लोगों के लिए कुछ करने में असफल रही है, इसलिए लोगों का गुस्सा जायज़ है. इस तरह मीडिया ने लोगों के गुस्से को जायज़ ठहराया.

एक बार फिर स्थानीय लोगों ने विपक्ष के एक विधायक के साथ दुर्व्यवहार किया. इस बार फिर मीडिया ने सरकार की आलोचना की. इस बात पर कि सरकार उक्त विधायक को उचित सुरक्षा मुहैया कराने में असफल रही. इस मामले में मीडिया ने लोगों के गुस्से को जायज़ नहीं ठहराया. हालांकि सच्चाई यह है कि उक्त दोनों मामलों में वे लोग ग़लत थे, जिन्होंने क़ानून को अपने हाथ में लिया और विधायकों के साथ बदतमीजी की. इसके लिए उन्हें सज़ा मिल सकती थी, लेकिन मीडिया ने एक मामले में लोगों के गुस्से को जायज़ ठहराया और दूसरे मामले में ऐसा नहीं किया. दोनों ही मामलों में सरकार की आलोचना की गई. यहीं आकर मीडिया की निष्पक्षता और उसे मिला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार सवालों के घेरे में आ जाता है. लॉर्ड एक्टन ने सही कहा था कि अधिकार आपको भ्रष्ट करता है और पूर्ण अधिकार आपको पूरी तरह भ्रष्ट करता है. यदि किसी को यह अधिकार मिल जाता है कि वह किसी को गोली मार सकता है तो उससे यह आशा की जाती है कि उसे पता होगा कि किसे मारना है, कब मारना है और कैसे मारना है. अगर वह ऐसा नहीं करता है तो फिर उसे नियंत्रित करने की ज़रूरत होती है. इसी प्रकार मीडिया को भी ख़ुद ज़्यादा उत्तरदायी बनाने की ज़रूरत है, जब वह अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहा हो. बिना उत्तरदायित्व के मिले अधिकार की जांच और इसके इस्तेमाल में सावधानी भी ज़रूरी है. ऐसे लोग जो मीडिया में कुछ समय के लिए भी काम कर चुके हैं, उन्हें पता है कि कैसे उन्हें किसी खास ख़बर को करने, न करने या औरों से अलग अंदाज़ में करने के लिए कहा जाता है, ताकि उससे किसी खास गुट के हित या उनके हित, जिससे मीडिया हाउस संबद्ध है, पूरे हो सकें. कई बार मीडिया हाउस विज्ञापनदाताओं को ध्यान में रखते हुए भी किसी खास ख़बर को करने से परहेज करते हैं. इन्हीं वजहों से मीडिया की निष्पक्षता संदेह के घेरे में आ जाती है. बरखादत्त का उदाहरण सामने है. मीडिया ट्रायल के साथ एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि मीडिया ज़्यादातर हाई प्रोफाइल और चर्चित मामलों में ही दख़ल देता है. जबकि लाखों ऐसे मामले, जिनके लिए आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है, चर्चा में नहीं आ पाते. फिर भी सब यह मानते हैं कि मीडिया ट्रायल एक ऐसी घटना है, जिसका इस्तेमाल समाज के एक बड़े तबके की बेहतरी के लिए किया जा सकता है. आज स्टिंग ऑपरेशन और आरटीआई के समय में सारे नीति निर्माता और सरकारी अधिकारी सतर्क हैं. उन्हें मालूम है कि अब वे ऐसा कुछ नहीं कर सकते, जो कल तक करते आ रहे थे. अब नेता, पुलिस और नौकरशाह सभी पहले से ज़्यादा ज़िम्मेदार हो गए हैं. अबसे पहले यह कोई सोच नहीं सकता था कि कोई मंत्री जेल भी जा सकता है. कोई आईएएस या आईपीएस गिरफ़्तार भी हो सकता है या किसी ताक़तवर नेता को सज़ा भी मिल सकती है. जैसा कि आज के दौर में देखने को मिल रहा है. मनु शर्मा, संतोष सिंह, हरियाणा के पूर्व आईजीपी आर के शर्मा, हरियाणा के ही पूर्व डीजीपी एच के एस राठौर को मिली सज़ा ने तुरंत न्याय दिलाने में मीडिया ट्रायल की भूमिका और प्रभाव को ही साबित किया है. मीडिया से यह उम्मीद है कि वह अपनी ताक़त का विवेक और जवाबदेही के साथ इस्तेमाल करेगा, ताकि बजाय पारंपरिक न्याय व्यवस्था और निर्णय प्रक्रिया की वर्तमान व्यवस्था को बदलने के, यह और आगे बढ़ता रहे और आम आदमी के लिए सुगम बन सके. इसी तरह प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, ताकि वह यह सुनिश्चित कर सके कि मीडिया स्वतंत्रता के अधिकार का बेजा इस्तेमाल न कर पाए.

ऐसे लोग जो मीडिया में कुछ समय के लिए भी काम कर चुके हैं, उन्हें पता है कि कैसे उन्हें किसी खास ख़बर को करने, न करने या औरों से अलग अंदाज़ में करने के लिए कहा जाता है, ताकि उससे किसी खास गुट के हित या उनके हित, जिससे मीडिया हाउस संबद्ध है, पूरे हो सकें. कई बार मीडिया हाउस विज्ञापनदाताओं को ध्यान में रखते हुए भी किसी खास ख़बर को करने से परहेज करते हैं.

(लेखक पश्चिमी बंगाल में आईएएस अधिकारी हैं. आलेख में व्यक्त विचार उनके ख़ुद के हैं और इनका सरकार के विचारों से कोई संबंध नहीं है.)

feedback@chauthiduniya.com

विवाह अच्छे इंसान को और भी बेहतर बनाता है. शोध से पता चला कि 17 से 20 वर्ष के सभ्य युवक आगे चलकर विवाह कर लेते हैं और सुखी दांपत्य जीवन बिताते हैं.

सूचना का अधिकार
जानने का अधिकार जीने का अधिकार
चौथी दुनिया की पहल

आपके पत्र, आपके अनुभव और हमारी सलाह

सड़क टूट रही है

मेरे इलाक़े में एक सड़क दो साल पहले बनी थी और अब टूट रही है. मैं इस संबंध में सूचना का अधिकार क़ानून का इस्तेमाल करना चाहता हूं. मुझे बताएं कि इस मामले में कैसे आवेदन दिया जा सकता है. **–मोजिबुल्लाह खान,** *जनता बाजार, सारण, बिहार.*

–आप चौथी दुनिया में प्रकाशित होने वाले आवेदन प्रारूप को देखें. उसी आधार पर आप जिस विभाग से सूचना चाहते हैं, उसका नाम, पीआईओ का नाम और अपने सवाल लिखें और उसे डाक द्वारा या स्वयं विभाग में जाकर जमा करें.

गैस की कालाबाज़ारी

मेरे शहर में गैस की कालाबाज़ारी जोरों पर है, जिससे आम जनता को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. 45 दिनों में हमें एक गैस सिलेंडर दिया जाता है. इस मामले में आरटीआई का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है. **–नीरज राय,** *अररिया, बिहार.*

–आप पहले इसकी शिक़ायत ज़िलाधिकारी और गैस कंपनी के पास करें. हफ्ता–दस दिन बाद, अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आप सूचना का आवेदन उन्हीं जगहों पर देकर पूछें कि आपकी शिक़ायत पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है. अपना आवेदन संबंधित विभाग के लोक सूचना अधिकारी के नाम से भेजें.

मिली ग़लत सूचना

मैंने सिंगरौली नगर पालिका से तहबाज़ारी वसूली की नीलामी (2004–05 से 2008–09 के दौरान) में अनुमानित 50 लाख रुपये के घोटाले से संबंधित सूचना मांगी थी, लेकिन मामले को राज्य सूचना आयोग में ले जाने और आयोग द्वारा आदेश दिए जाने के बाद भी मुझे पूर्ण सूचना नहीं मिली. जो मिली भी, वह भ्रामक और ग़लत थी. प्रथम अपील अधिकारी, जो नगर पालिका के आयुक्त भी हैं, ने तो अपील पर सुनवाई करना भी ज़रूरी नहीं समझा. इसलिए इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि वह भी इस घोटाले में संलिप्त हों. मैं आपके अख़बार के माध्यम से ज़िला प्रशासन और राज्य सरकार से अपील करता हूं कि इस मामले की जांच कराई जाए.

–दीनानाथ सिंह, *सिंगरौली, मध्य प्रदेश.*

–आप चाहें तो इसकी शिक़ायत राज्य सूचना आयोग से करके लोक सूचना अधिकारी पर जुर्माना लगाने की मांग कर सकते हैं.

अपर कलेक्टर सूचना नहीं देते

मैंने अपर कलेक्टर कार्यालय, सागर, मध्य प्रदेश से कुछ सूचनाएं मांगी थीं, लेकिन यह कहकर मुझे कोई सूचना नहीं दी गई कि मांगी गई सूचनाएं प्रश्नात्मक हैं. प्रथम अपील के बाद भी अब तक सूचना नहीं मिली है. **–डॉ. जी एस वर्मा,** *सागर, मध्य प्रदेश.*

–यदि आप इस मामले को सूचना आयोग में नहीं ले गए हैं तो तत्काल ले जाएं. दोबारा आवेदन देकर भी सूचना मांग सकते हैं. सीधे सवाल करें. ऐसे सवाल, जो सिर्फ़ आपके द्वारा चाही गई सूचना से संबंधित हों.

निराधार अर्जियों पर जुर्माना

सीआईसी एम एम अंसारी ने कहा है कि निराधार आरटीआई अर्जियों पर जुर्माना लगाना चाहिए. यह ख़बर चौंकाने वाली है. चिंता का विषय है. मैं उनसे सहमत नहीं हूं. वह क़ानून से ऊपर नहीं हैं. सरकार अभी तक इस क़ानून को लोगों के बीच ले जाने का काम नहीं कर पाई है. ऐसे में सूचना आयुक्त का बयान आरटीआई आवेदकों को हैरान करने वाला है. जब आवेदक ही नहीं होंगे तो क़ानून, आयोग और आयुक्त की क्या ज़रूरत होगी?

–गिरीश प्रसाद गुप्ता, *बेगूसराय, बिहार.*

सरकारी स्कूल को प्राइवेट बताया

हमारे यहां के एक सरकारी हाईस्कूल के लिए ज़मीन चाहिए थी. सीओ ने रिश्वत की मांग की, न देने पर स्कूल को प्राइवेट घोषित कर दिया. जब सूचना क़ानून के तहत जानकारी मांगी गई तो सीओ ने काम कर देने का आश्वासन दिया, लेकिन अनुमंडलाधिकारी भी नहीं चाहते कि काम हो. वह प्रथम अपील अधिकारी भी हैं. इन परिस्थितियों में क्या किया जाए.

–दीनबंधु सिंह. *निहालपुर, बक्सर.*

–इस मामले में आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया, इसके लिए आपको बधाई. हमारी सलाह है कि आप इस मामले को यदि ज़रूरत पड़े तो राज्य सूचना आयोग तक ले जाएं. साथ ही एक शिक़ायती पत्र ज़िलाधिकारी को भी दे दें, इस सबूत के साथ कि उक्त स्कूल सरकारी है (यदि सबूत हो तो), ताकि आगे चलकर यदि जिलाधिकारी इस मामले में सही निर्णय नहीं लेते हैं तो उसी शिक़ायती पत्र के आधार पर उनसे सवाल पूछे जा सकें.

सूचना कैसे मिलेगी

मैं आरटीआई का इस्तेमाल करना चाहता हूं. किसी भी विभाग से कोई सूचना कैसे निकाली जा सकती है. कृपया पूरी प्रक्रिया बताने का कष्ट करें. **–लक्ष्मीकांत तिवारी,** *ई-मेल से.*

–चौथी दुनिया में हम लगातार इस संबंध में आवेदन के प्रारूप, सलाह और आलेख प्रकाशित कर रहे हैं. सूचना क़ानून को समझने और उसके इस्तेमाल के लिए इतना काफी होगा कि आप अख़बार में प्रकाशित आवेदनों और सलाह पर ध्यान देते रहें.

उर्दू टीवी का प्रसारण बंद

हमारे यहां 15 अक्टूबर, 2009 से पीस टीवी, क्यू टीवी एवं ईटीवी उर्दू का प्रसारण बंद कर दिया गया है. मैंने एस आर चैनल के प्रबंधक नीरज राय से इस संबंध में फोन पर बात की तो उन्होंने कहा, हमें ऊपर से ऑर्डर हैं. मेरे निवेदन पर उन्होंने संबंधित मंत्रालय के सर्कुलर की प्रतिलिपि भिजवा दी. मैंने आरटीआई क़ानून के तहत उक्त मंत्रालय से इस पाबंदी पर जानकारी मांगी, लेकिन मुझे जो जवाब मिला है, वह मेरी समझ से परे है.

–अनवार हुसैन, *झांसी, उत्तर प्रदेश.*

–आप इस मामले में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से जानकारी मांग सकते हैं, साथ ही उक्त सर्कुलर की प्रति भी.

डीलर बेईमान है

हम लोगों को प्रतिमाह राशन एवं किरोसिन नहीं मिलता. हमने 29 अगस्त, 2010 को डीलर के ख़िलाफ़ मोर्चा खोला और जाम भी लगाया, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई. हमें क्या करना चाहिए? **–मुहम्मद इम्तियाज़ अंसारी,** *छपरा, बिहार.*

–आप इस मामले में पहले एक शिक़ायती पत्र दें और तब सूचना क़ानून के तहत आवेदन देकर ज़िला आपूर्ति अधिकारी से सवाल पूछ सकते हैं.

आरटीआई कार्यकर्ता बनना चाहता हूं

मैं गाशेवारा उर्दू का रिपोर्टर और समाज सेवक हूं और आरटीआई कार्यकर्ता बनना चाहता हूं. कृपया मुझे सलाह दें कि इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए. **–डॉ. अफ़ज़ाल अंसारी,** *सहारनपुर, उत्तर प्रदेश.*

–आपको सूचना क़ानून से संबंधित कुछ सामग्री भेजी जा रही है, जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी. साथ ही आप चौथी दुनिया में प्रकाशित आरटीआई कॉलम लगातार पढ़ते रहें. आरटीआई का इस्तेमाल करें. प्राप्त सूचना को सार्वजनिक करते रहें.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमें पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है :

चौथी दुनिया

एफ–2, सेक्टर–11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश, पिन –201301
ई–मेल : rti@chauthiduniya.com

ज़रा हट के

इंटरनेट पर नया विवाद

इंटरनेट पर पहले से ही विकीलीक्स जैसे विवाद सुर्ख़ियों में हैं और अब एक और नया विवाद चर्चा में आ गया है. इस बार मामला है लोगों की पर्सनल प्राइवेसी का. सवाल है कि गूगल स्ट्रीट व्यू पर लोगों की निजता भंग करने वाली सामग्रियां डालना उचित है? ग़ौरतलब है कि गूगल स्ट्रीट व्यू हमेशा विवादों से घिरी रही परियोजना है. कई देशों ने इस पर प्रतिबंध लगाया है और जहां प्रतिबंध नहीं लगा है, वहां भी लोग इसे शंका की निगाहों से ही देखते हैं. गूगल स्ट्रीट व्यू गूगल मैप्स का एक और संस्करण है, जो प्रयोगकर्ताओं को शहर की सड़कों का अवलोकन करने की सुविधा देता है, परंतु इसके लिए फुटेज लेते समय कई ऐसी तस्वीरें कैद हो जाती हैं, जो सार्वजनिक नहीं की जा सकतीं.

दरअसल, अभी तक इससे किसी को कोई खास समस्या नहीं थी. मामला तब ज़्यादा गर्मा गया, जब कनाडा के क्यूबैक शहर के एक अनजाने व्यक्ति की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें खींच ली गईं. वह अपने घर के बरामदे में नग्नावस्था में बैठा किताब पढ़ रहा था. जैसे ही इन तस्वीरों को लोगों ने देखा, चर्चा का बाज़ार गर्म हो गया. यह ख़बर दुनिया भर के टेबलाइड अख़बारों में छा गई. हालांकि इस तरह का यह पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी एक जर्मन व्यक्ति की नग्न छवि कैद हो गई थी. अब लोग सवाल कर रहे हैं कि गूगल के संचालनकर्ताओं से. उनका कहना है कि स्ट्रीट व्यू में वैसे तो कोई ख़राबी नहीं है, लोगों को इससे रास्ता ढूंढने में मदद मिलती है, लेकिन जब इस रास्ते में किसी की निजी और आपत्तिजनक तस्वीरें सार्वजनिक होने लगें तो फिर इसका समाधान निकालना ज़रूरी हो जाता है.

शादी से आता है सलीक़ा

अपने यहां एक पुरानी कहावत है, अगर कोई जवान ज़्यादा बिगड़ने लगे तो उसकी शादी कर दो. अब आप सोच रहे होंगे कि लोगों के बिगड़ने का शादी से क्या वास्ता. दरअसल लोगों के पुराने प्रयोग और मान्यताओं के मुताबिक़, बिगड़े नौजवान की अगर शादी कर दी जाए तो वह सुधर जाता है. लेकिन क्या यह सच है? कुछ नए शोध साबित करते हैं कि विवाह से पुरुषों के स्वभाव में सुधार आता है और वे अधिक सभ्य बन जाते हैं. मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के एस अलेक्जेंड्रा बर्ट एवं उनके सहयोगियों ने एक शोध के दौरान पाया कि विवाह करने वाले अधिकतर पुरुष स्वभावगत रूप से कम असामाजिक होते हैं और विवाह के बाद वे और भी ज़्यादा सामाजिक बन जाते हैं.

अलेक्जेंड्रा बर्ट के अनुसार, विवाह अच्छे इंसान को और भी बेहतर बनाता है. शोध से पता चला कि 17 से 20 वर्ष के सभ्य युवक आगे चलकर विवाह कर लेते हैं और सुखी दांपत्य जीवन बिताते हैं. यह शोध कुछ जुड़वां लोगों पर भी किया गया, जिससे साबित हुआ कि लगभग एक जैसे लोगों पर भी विवाह करने या न करने का असर ज़रूर पड़ता है. अगर आपके घर में कोई बिगड़ा शहजादा है तो जल्द ही उसकी शादी की तैयारी कीजिए और उसे सभ्य बनाइए.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

राशिफल

दिल्ली, 27 दिसंबर 2010–02 जनवरी 2011

मेष (21 मार्च से 20 अप्रैल)
इस सप्ताह आपका ध्यान खाने, पीने और मनोरंजन में लगा रहेगा. बुजुर्ग लोगों का मन अध्यात्म में लगेगा और विद्यार्थियों का पढ़ाई–लिखाई में. कुछ ऐसे काम करने का मौक़ा भी आएगा, जब आपको अपना नुक़सान या फ़ायदा सोचे बग़ैर फ़ैसले लेने होंगे.

वृष (21 अप्रैल से 20 मई)
इस सप्ताह आपको आज़ादी का एहसास होगा. ऑफिस में कोई ऐसा काम दिया जाएगा, जिसमें आपको दूसरों से काम निकलवाने की पूरी छूट होगी. सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा. लोगों को अपनी तरफ़ आकर्षित करने में सफल रहेंगे.

मिथुन (21 मई से 20 जून)
प्रॉपर्टी के मामले में बदलाव आने की पूरी संभावना है. सप्ताह के मध्य कोई नया सौदा कर सकते हैं. घर में सजावट या व्यवस्था में समय बीतेगा, लेकिन सामान ख़रीदते समय अपनी जेब का ख्याल रखना ज़रूरी है.

कर्क (21 जून से 20 जुलाई)
इस सप्ताह कुछ लोगों को नौकरी का ऑफर आ सकता है. शिक्षा से जुड़े मसलों में आपकी राय ज़रूरी होगी. मैनेजमेंट का काम संभालना पड़ सकता है. घर में शुभ कार्य के बारे में किसी बुजुर्ग से बातचीत करेंगे.

सिंह (21 जुलाई से 20 अगस्त)
सप्ताह के पहले दिन कई परेशानियों का हल निकालने में कामयाबी मिलेगी. कोई ज़रूरी समाचार मिलेगा, जो काम में आपको मदद करेगा. धन का लाभ होगा और बचत करने के तरीक़े मिलेंगे.

कन्या (21 अगस्त से 20 सितंबर)
किसी पुराने झगड़े का निपटारा होगा. किसी अनुभवी वकील से क़ानूनी मसले पर राय लेना बेहद ज़रूरी है. किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे अच्छी तरह पढ़ लें.

तुला (21 सितंबर से 20 अक्टूबर)
सप्ताह की शुरुआत में कुछ लोगों को अपनी संतान के बारे में गंभीर रूप से सोचना होगा. बच्चों की पढ़ाई को लेकर कई सवाल खड़े हो सकते हैं, लेकिन आपकी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा.

वृश्चिक (21 अक्टूबर से 20 नवंबर)
कुछ ऐसे लोगों के बारे में भ्रम दूर हो जाएंगे, जिन्हें आप बेहद मददगार और अच्छा समझते थे. सप्ताह के दूसरे हिस्से में अचानक कोई काम बन जाने से ख़ुशी का एहसास होगा. घर में बच्चों को समय देना ज़रूरी होगा.

धनु (21 नवंबर से 20 दिसंबर)
आपके कई काम एक साथ बनते चले जाएंगे. आपके विरोधी सिर नहीं उठा पाएंगे. व्यवसायिक क्षेत्र में किसी खास शख्स के प्रति आपकी ग़लतफहमी दूर हो जाएगी. सट्टेबाज़ी का जोखिम लेना ठीक नहीं होगा. घरवाले आपसे ज़्यादा अपेक्षाएं करेंगे.

मकर (21 दिसंबर से 20 जनवरी)
सप्ताह का पहला दिन आपके लिए अच्छा है. दूसरों की भावनाओं को समझने के लिए समय निकालना होगा. परिवार के छोटे सदस्यों पर ध्यान देने की ज़रूरत है. बच्चों के साथ समय अच्छा गुजरेगा. व्यवसायिक क्षेत्र में छोटा–मोटा परिवर्तन आ सकता है.

कुंभ (21 जनवरी से 20 फरवरी)
इस सप्ताह कुछ लोग दिल के हाथों मजबूर होंगे. काम में मन लगाने में दिक्कत महसूस हो सकती है. बेहतर यही होगा कि किसी बड़े प्रोजेक्ट या ज़िम्मेदारी को अपने हाथ में न लें. दो–तीन दिनों के लिए उसे टालने में भलाई है.

मीन (21 फरवरी से 20 मार्च)
आप साहस और मेहनत से ऑफिस में आई किसी बड़ी समस्या का हल निकाल लेंगे. आसपास की यात्रा टालनी पड़ सकती है. वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, अन्यथा दुर्घटना होने की आशंका है.

पंडित सुदर्शन
feedback@chauthiduniya.com

ओबामा ने यह जताने की कोशिश की कि अन्य देशों की अपेक्षा अमेरिका भारत से ज़्यादा प्यार करता है.

यार का प्यार बेशुमार

राजीव रंजन तिवारी

नवंबर में ओबामा और दिसंबर में सरकोजी. इन स्वयंभू महाशक्तियों ने अपनी-अपनी यात्राओं के दौरान जिस तरह दिल खोलकर हर मुद्दे पर भारत के समर्थन का वादा किया है, वह निश्चित रूप से अभिभूत करने वाला है. भारत को मिले इनके बेशुमार प्यार के निहितार्थ जो हों, पर फ़िलहाल तो इस पर सकारात्मक नज़रिया ही रखा जाना चाहिए. अपनी चार दिवसीय भारत यात्रा पर आए फ्रांस के राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी ने यह बताने की कोशिश की कि उन्हें भारत से ज़्यादा प्यार है. यात्रा के दौरान उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी का समर्थन करने का ऐलान किया. साथ ही सभी तरह के परमाणु कार्यक्रमों में भारत की मदद करने की भी घोषणा की. उन्होंने कहा कि यह कल्पना करना मुश्किल है कि एक अरब से ज़्यादा आबादी वाला देश भारत सुरक्षा परिषद से बाहर कैसे है. इससे पूर्व बीते माह कोलंबिया विश्वविद्यालय में वर्ल्ड लीडर्स फोरम के तहत व्याख्यान देते वक़्त भी सरकोजी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया था. वहां भी उन्होंने कहा था कि अगले 30 सालों में भारत विश्व में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा, लेकिन उसके पास अभी तक सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता नहीं है. भारत यात्रा के दौरान सरकोजी ने न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप (एनएसजी) में भी भारत के प्रवेश का समर्थन किया. उन्होंने दुनिया की अस्थिरता के लिए अफ़ग़ानिस्तान-पाकिस्तान में पनप रहे आतंकवाद को ज़िम्मेदार ठहराया. उन्होंने साफ कहा कि फ्रांस भारत का दोस्त है. वह परमाणु उद्योग और प्रदूषण न फैलाने वाली ऊर्जा के विकास में भारत की मदद करेगा.

सरकोजी का यह कहना भी काफी सुखद है कि हमें एटमी बिरादरी में अलग-थलग पड़े भारत की मदद करनी होगी. उन्होंने फ्रेंच कंपनी अरेवा द्वारा महाराष्ट्र के जैतापुर में एटमी प्लांट लगाने की जानकारी दी. इस प्लांट के ज़रिए 10 हज़ार मेगावॉट प्रदूषणविहीन ऊर्जा का उत्पादन होगा. पिछले तीन वर्षों के भीतर सरकोजी की यह दूसरी भारत यात्रा है. समझा जा रहा है कि सरकोजी के इस दौरे से दोनों देशों के बीच असैन्य परमाणु और विज्ञान के क्षेत्रों में परस्पर सहयोग बढ़ेगा. इसके अलावा आर्थिक-व्यापारिक रिश्ते भी मज़बूत होंगे. सरकोजी ने सुरक्षा परिषद की सदस्यता एवं आतंकवाद के मुद्दे पर समर्थन कर यह जता दिया कि उनके देश के लिए भारत महत्वपूर्ण है. इससे पूर्व नवंबर में अपनी तीन दिवसीय भारत यात्रा पर आए अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के समक्ष भी सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता और पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों का मुद्दा उठा था. ओबामा ने कहा था कि पाकिस्तान अपनी ज़मीन से आतंकवाद को ख़त्म करे, मुंबई हमले के दोषियों पर कार्रवाई करे और सीमावर्ती इलाक़ों में चरमपंथियों पर लगाम लगाए. उन्होंने यह भी कहा कि कश्मीर मसला दोनों देश आपस में ही सुलझाएं.

सरकोजी का यह कहना भी काफी सुखद है कि हमें एटमी बिरादरी में अलग-थलग पड़े भारत की मदद करनी होगी. उन्होंने फ्रेंच कंपनी अरेवा द्वारा महाराष्ट्र के जैतापुर में एटमी प्लांट लगाने की जानकारी दी. इस प्लांट के ज़रिए 10 हज़ार मेगावॉट प्रदूषणविहीन ऊर्जा का उत्पादन होगा. पिछले तीन वर्षों के भीतर सरकोजी की यह दूसरी भारत यात्रा है. समझा जा रहा है कि सरकोजी के इस दौरे से दोनों देशों के बीच असैन्य परमाणु और विज्ञान के क्षेत्रों में परस्पर सहयोग बढ़ेगा.

फोटो- *सुनील मल्होत्रा*

सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के सवाल पर ओबामा का यह कहना कि भारत और अमेरिका विश्व सुरक्षा के लिए भागीदारी कर सकते हैं, खास तौर पर जब भारत दो साल तक सुरक्षा परिषद के सदस्य के रूप में काम करेगा, खास है. उन्होंने कहा कि हम सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता का समर्थन करते हैं. मैं आने वाले वर्षों में पुनर्गठित सुरक्षा परिषद देखना चाहूंगा, जिसमें भारत स्थायी सदस्य हो. आज आपस में जुड़ी दुनिया में अमेरिका जिस भविष्य को देखना चाहता है, उसमें भारत के बिना काम नहीं चल सकता. वक़्त की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत-अमेरिका की साझीदारी अनिवार्य है. अमेरिका भारत का बढ़ती ताक़त के रूप में न सिर्फ़ स्वागत करता है, बल्कि वह पूरी शिद्दत से इसमें मदद भी करेगा. ओबामा ने यह जताने की कोशिश की कि अन्य देशों की अपेक्षा अमेरिका भारत से ज़्यादा प्यार करता है. अमेरिका और फ्रांस द्वारा समर्थन के बाद सुरक्षा परिषद की सदस्यता के मुद्दे पर भारत की राह आसान होती जा रही है. परिषद के मौजूदा पांच सदस्यों यानी अमेरिका, फ्रांस, जापान, चीन और रूस में से अमेरिका, फ्रांस एवं जापान का समर्थन भारत को हासिल है. जबकि रूस सर्वसम्मति बनाने के पक्ष में है. ठीक इसी तरह आतंकवाद के सवाल पर भी भारत विरोधी देशों के अलग-थलग पड़ने की उम्मीद है. बशर्ते, अमेरिका एवं फ्रांस की कथनी और करनी में एकरूपता हो.

feedback@chauthiduniya.com

चुनौती बनता चीन

चीन की नई-नई गतिविधियां चिंतित कर रही हैं. वह अपने आगे भारत सरीखे देशों को तो कुछ समझता ही नहीं है, उसके लिए अमेरिका की भी कोई खास अहमियत नहीं है. वह अमेरिका विरोधी गतिविधियां भी संचालित कर रहा है. वैसे भारत के लिए यह सुखद है कि वह चाहे तो चीन को सबक सिखाने के लिए अमेरिका के कंधे से कंधा मिलाकर चल सकता है. चीनी गतिविधियों से अमेरिका भी ख़फ़ा है और चीन के विरुद्ध कार्रवाई के लिए मौक़े की तलाश में है. चीन दुनिया के कई देशों के लिए चुनौती बनता जा रहा है. वह भारत, जापान, नार्वे, दक्षिण कोरिया जैसे देशों को जब-तब झिड़क देता है और अब अमेरिका के विरुद्ध भी चलने की हिम्मत जुटाने लगा है. बावजूद इसके यह समझ से परे है कि आख़िर कोई भी देश चीन के विरुद्ध ठोस क़दम क्यों नहीं उठा रहा है. खासकर अमेरिका को तो चीन के मसले पर कोई न कोई निर्णय लेना ही चाहिए. दुनिया में चीन की दबंगई बढ़ती जा रही है और अन्य देश चुपचाप इसे देख रहे हैं. चुनौती बनते चीन की चतुराई भरी गतिविधियों को सहन करना भविष्य के लिए ठीक नहीं है.

पिछले दिनों नोबेल शांति पुरस्कार समारोह क़रीब आते ही चीन ने विरोधियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया. उसने भारत समेत कई देशों से स्पष्ट कहा कि वे समारोह में अपना प्रतिनिधि न भेजें. इससे भारत की उलझन बढ़ गई. ग़ौरतलब है कि चीन के लोकतंत्र समर्थक नेता लिउ जियाबाओ को ओस्लो (नार्वे) में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाना था. चीन के प्रतिनिधियों ने बीजिंग में सभी देशों के प्रतिनिधियों से मिलकर उन पर समारोह का बहिष्कार करने का दबाव डाला. भारतीय राजदूत एस जयशंकर से भी कहा गया कि वह अपनी सरकार से समारोह में भाग न लेने के लिए कहें. चीन ने धमकी भी दी कि यदि उसकी बात न मानी गई तो उसका असर चीनी प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ की भारत यात्रा पर भी पड़ सकता है. चीन, रूस, कजाकिस्तान, क्यूबा, मोरक्को एवं इराक कार्यक्रम के बहिष्कार का निर्णय पहले ही ले चुके थे. समझा जा रहा है कि यह चीन के दबाव का ही असर था. बाद में पाकिस्तान भी इस समूह में शामिल हो गया. लिउ जियाबाओ चीन में लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के पक्षधर हैं. चीन की सरकार ने उन्हें अपराधी क़रार देकर 11 साल के लिए जेल में बंद कर रखा है. नोबेल पुरस्कार समिति द्वारा लिउ के नाम की घोषणा के बाद से ही चीन भड़का हुआ है. उसने नार्वे के साथ अपने व्यापारिक संबंधों में कटौती कर ली और कहा कि दोनों देशों के संबंध अब पहले की तरह नहीं रह सकेंगे. वहीं ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी समेत 36 देशों के राजदूतों ने चीनी मुहिम के विरुद्ध समारोह में भाग लेने के लिए बिना समय गवांए सहमति दे दी.

इसी तरह वर्ष 2007 में फ्रांस द्वारा दलाईलामा का स्वागत करने के कारण चीन उस पर भी समय-समय पर आंखें तरेरता रहता है. इससे ख़फ़ा फ्रांस के नागरिकों ने बीजिंग ओलंपिक टॉर्च रिले का भी पेरिस में विरोध किया था. इसके बाद चीन से यूरोप के दौरे पर जाने वाले दो व्यापारिक प्रतिनिधिमंडलों के कार्यक्रम से फ्रांस का नाम हटा दिया गया. 2009 में फ्रांस ने यह संदेश दिया कि वह तिब्बत पर चीन के नियंत्रण का सम्मान करता है. फिर चीन का एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल फ्रांस पहुंचा. इन उदाहरणों से साफ है कि चीन अपनी कूटनीतिक और राजनीतिक सहूलियत की राह में रोड़ा बनने वाले देशों के ख़िलाफ़ कार्रवाई से हिचकता नहीं है. यानी उसका फ्रांस से भी पंगा हो चुका है. बताते हैं कि चीन उन देशों के साथ व्यापार कम कर देता है, जो तिब्बत के धर्मगुरु दलाईलामा का स्वागत करते हैं. एक अध्ययन के मुताबिक़, दुनिया के उन देशों, जो दलाईलामा की मेज़बानी करते हैं, पर चीन अपनी आर्थिक ताक़त की धौंस जमाता है. ऐसे देशों द्वारा चीन के लिए होने वाले निर्यात पर 8.1 से 16.9 फ़ीसदी तक का असर पड़ता है. इस अध्ययन को आधार मानकर 8 फ़ीसदी के हिसाब से असर का आकलन करने पर भारत को ही क़रीब 42 अरब रुपये का घाटा होने का आंकड़ा सामने आता है. भारत द्वारा चीन को क़रीब 3 ख़रब 37 अरब रुपये का निर्यात किया जाता है. इसके अलावा जापान और चीन के बीच एक द्वीप पर दावे को लेकर विवाद बढ़ गया है. इस द्वीप पर जापान के दावे के ख़िलाफ़ हज़ारों चीनी सड़कों पर उतरे. दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच ब्रूसेल्स में एशिया यूरोप शिखर सम्मेलन के दौरान हुई बैठक में भी यह तनाव देखा गया. पूर्वी चीन सागर स्थित इस द्वीप को जापान सेनकाकू के नाम से भी पुकारता है. भारत, जापान, नार्वे एवं दक्षिण कोरिया सरीखे देशों को कुछ न समझने वाले चीन को अमेरिका से भी डर नहीं है. अमेरिकी विरोध के बावजूद वह उत्तर कोरिया की मदद कर दक्षिण कोरिया पर हमले करा रहा है. इस तरह चीन दुनिया के कई छोटे-बड़े देशों के लिए चुनौती बनता जा रहा है. इस पर अंकुश लगाने की ज़रूरत है.

राजीव रंजन
feedback@chauthiduniya.com

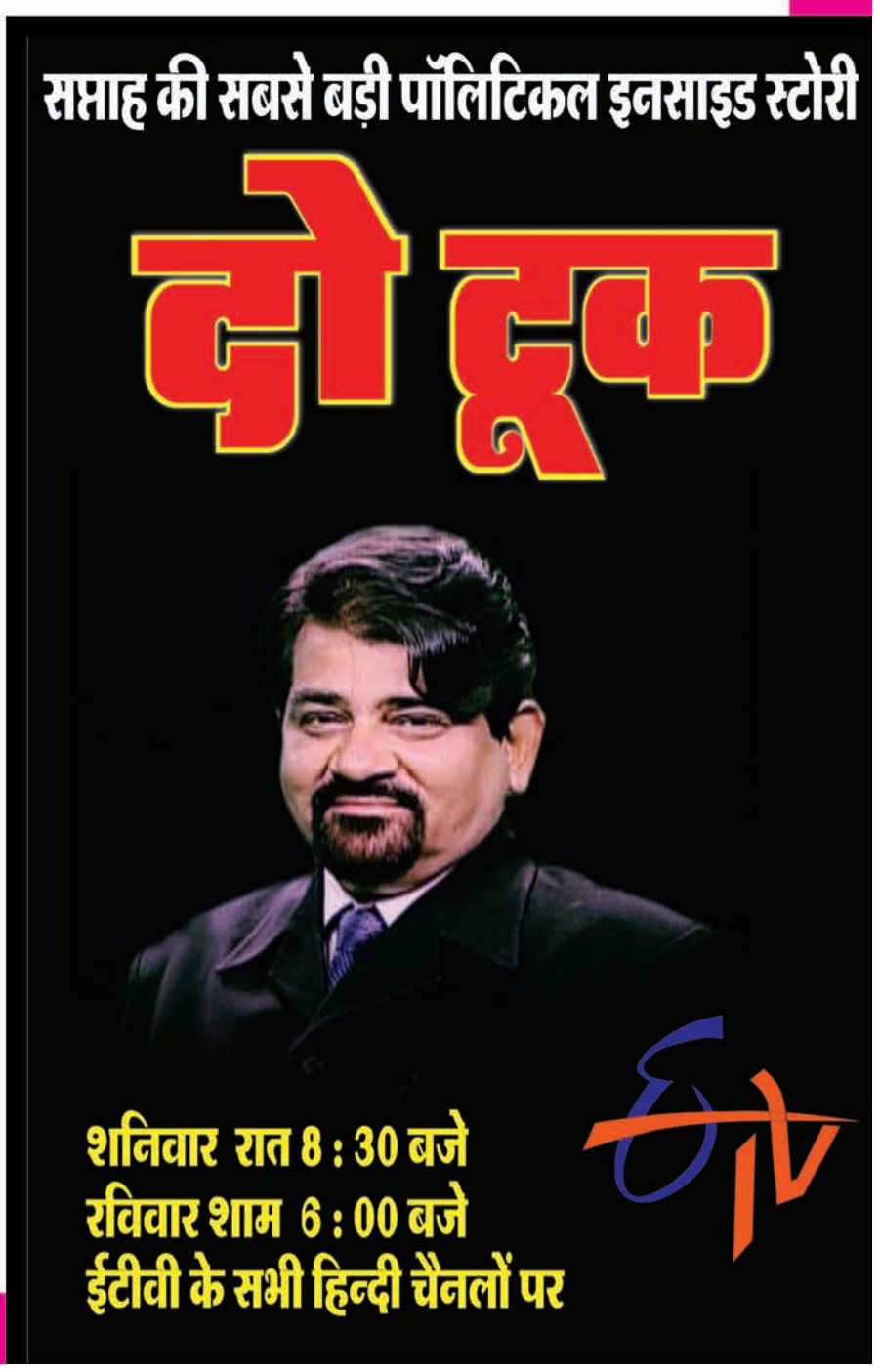

साई बाबा का मंत्र सबका मालिक एक यही बताता है कि परमात्मा एक है और वही हम सभी का पालन-पोषण करता है.

बाबा का न्यायालय

द्वारकामाई में बाबा हर उस आने वाले की इच्छा पूरी करते थे, जो उनसे कुछ मांगता था. लेकिन बाबा ने ऐसा भी कहा कि अगर सभी बौर बन जाएं तो फलों की गिनती करना ही असंभव हो जाएगा. यानी बाबा सबको देने की सामर्थ्य रखते हुए भी सुपात्र का विचार ज़रूर करते थे.

आरती श्री साई गुरूवर की, परमानंद सदा सुखवर की
जाकी कृपा विपुल सुखकारी, दुख, शोक, संकट, भयहारी
शिरडी में अवतार रचाया, चमत्कार से तत्व दिखाया
कितने भक्त चरण पर आए, वे सुख शांति चिरतंन पाए
भाव धरे मन में जैसा, पावत अनुभव वो ही वैसा
गुरू की लगावे तन को, समाधान लाभत उस मन को
साई नाम सदा जा गावे, सो फल जग में शाश्वत पावे
गुरूबारसर करि पूजा सेवा, उस पर कृपा करत गुरुदेवा
राम, कृष्ण, हनुमान रूप में, दे दर्शन जानत जो मन में
विविध धर्म के सेवक आते, दर्शन से इच्छित फल पाते
जय बोलो साई बाबा की, जय बोलो अवधूत गुरू की
साईदास आरती को गावे, घर में बसि सुख मंगल पावे.

मशीद माई से कोई खाली हाथ नहीं लौटता, यह वचन जितना तब सत्य था, उतना ही आज भी. मेरी शरण आ खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए, बाबा के यही वचन आज भी उनकी संतानों में जीवन के प्रति जोश पैदा कर रहे हैं और एक सतत आश्वासन हैं कि बाबा से कुछ भी मांगो, वह ज़रूर देते हैं. लगभग 36,525 दिन पहले बाबा ने द्वारकामाई के अलावा एक और जगह को अपना ठिकाना बनाया था. बाबा ने फ़ैसला किया कि वह एक दिन छोड़ कर पास ही में एक टूटी सी इमारत में रात को विश्राम करेंगे. द्वारकामाई में तात्या और म्हालसापति जी बाबा के साथ रात को चिंतन, मनन, ध्यान और विश्राम करते थे, मगर चावड़ी में किसी को भी बाबा के साथ रुकने की आज्ञा नहीं थी. बाबा चावड़ी में ध्यान करते और अपने भक्तों के लिए मालिक से प्रार्थना भी करते. चावड़ी में बाबा को छोड़ने के बाद शिरडी के किसी भी व्यक्ति ने उनकी आवाज़ नहीं सुनी. बाबा चावड़ी में केवल ध्यान ही करते थे? बाबा का चावड़ी में सोने का क्या कारण था? चावड़ी में महिलाओं का प्रवेश वर्जित क्यों था? वैसे तो बाबा की लीला वह ही जानें, मगर उनकी ही कृपा और करुणा से हम बाबा की इस मनमोहक लीला को समझने का प्रयास करते हैं.

बाबा हर दूसरे दिन चावड़ी में रात बिताते थे. बाबा की दया से जहां तक मेरा विचार है, वास्तव में चावड़ी बाबा का न्यायालय था. द्वारकामाई में बाबा हर उस आने वाले की इच्छा पूरी करते थे, जो उनसे कुछ मांगता था. लेकिन बाबा ने ऐसा भी कहा कि अगर सभी बौर बन जाएं तो फलों की गिनती करना ही असंभव हो जाएगा. यानी बाबा सबको देने की सामर्थ्य रखते हुए भी सुपात्र का विचार ज़रूर करते थे. द्वारकामाई में जब वह भक्तों को मुंहमांगा दे देते थे, तब चावड़ी में बैठकर उस भक्त को अपनी दी हुई भेंट के लिए सुपात्र बनाने का कार्य भी करते थे. एक वर्णन आता है, जहां बाबा ने अपने एक भक्त की शराब की बुरी आदत छुड़ाने के लिए उसे बहुत मारा था. वह मारना स्वप्न में ज़रूर था, मगर उसका असर वास्तविक था. आज भी अगर हम बाबा से कुछ मांगते हैं तो हो सकता है कि हम अपनी मांगी हुई चीज़ के लिए सुपात्र न हों, लेकिन बाबा आज भी चावड़ी में बैठकर हमें, हमारी मांग के लिए हमें सुपात्र बनाते हैं. बाबा ने हमेशा कहा, श्रद्धा रखो और सब्र से काम लो. अब सवाल उठता है कि अगर बाबा को हमें कुछ देना ही है तो सब्र किस बात का? वास्तव में बाबा ने सब्र करने को इसीलिए कहा कि वह चाहते हैं कि हम बौर की तरह पूरी श्रद्धा और सब्र से इंतज़ार करें, जिससे हमें हमारे कर्मों का स्वादिष्ट और सुगंधित फल मिले. चावड़ी में बैठकर बाबा का न्यायालय पूरा न्याय करता है. अगर दोष हमारा है तो सज़ा भी हमें ही भुगतनी होगी. बाबा ने तो साफ़ बताया है कि कई जन्मों में सज़ा पूरी करने से अच्छा है कि हम इसी जन्म में उनकी निगरानी में अपनी सज़ा पूरी करें और फिर स्वयं बाबा के चरणों में विलीन हो जाएं. इस विचार से लोग कितना इत्तेफाक रखते हैं, यह अलग बात है, लेकिन बात एकदम सही है कि आज भी चावड़ी में अपने किए तमाम गुनाहों की माफ़ी मांग लेने से बाबा हमें मालिक से इंसाफ़ दिलाते हैं और ग़लती करने से रोक भी लेते हैं. चावड़ी में बाबा का दरबार भले ही न लगता हो, मगर फ़ैसला तो बाबा चावड़ी में बैठकर ही सुनाते हैं. हम यह मान सकते हैं कि मशीद माई हमें कभी निराश नहीं करतीं. मशीद माई का साई हमें देता है, मगर चावड़ी में बैठकर हमारी समीक्षा और समाधान करने के बाद देता है. श्री साई का न्यायालय शायद सृष्टि का एकमात्र ऐसा न्यायालय होगा, जिसके फ़ैसले कभी ग़लत नहीं होते. जय साई राम.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

गुरुवार और बाबा की विशेष पूजा

साई बाबा एक ऐसे फकीर हैं, जिन्हें हर धर्म के लोग बड़ी श्रद्धा से पूजते हैं. बाबा की आराधना किसी भी विशेष मुहूर्त या वार को की जा सकती है, परंतु गुरुवार को इनकी पूजा का विशेष महत्व माना गया है. गुरुवार को इनकी आराधना का इतना महत्व क्यों है? इस संबंध में यही तथ्य है कि गुरुवार गुरु का दिन माना जाता है. सभी धर्मों में गुरु का खास स्थान है, गुरु ही हमें आदर्श जीवन जीने के सूत्र बताता है. गुरु ही सही राह पर चलने की प्रेरणा देता है. साई बाबा ने हमेशा सभी को आदर्श और उच्च जीवन जीने की प्रेरणा दी. इसी वजह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा को अपना गुरु मानते हैं. साथ ही ऐसा माना जाता है कि इनकी आराधना से जल्द ही हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं. साई बाबा के मंदिर में सभी धर्मों के लोगों के लिए समभाव रखा जाता है. गुरुवार गुरु का दिन है, इसलिए बाबा को गुरु मानने वाले सभी भक्त इस दिन मंदिर ज़रूर जाते हैं.

साई बाबा का मंत्र सबका मालिक एक यही बताता है कि परमात्मा एक है और वही हम सभी का पालन-पोषण करता है. इसी मंत्र की वजह से वह सर्वधर्म के लोगों के लिए भगवान और गुरु के समान हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

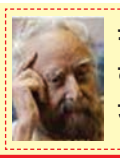

2010 का लेखा-जोखा

अनंत विजय

वर्ष 2010 बीत गया. नया साल आ गया, शताब्दी के दूसरे दशक की शुरुआत हो गई है. वक़्त आ गया है पिछले वर्ष प्रकाशित पुस्तकों पर एक नज़र डालने का. मेरा मानना है कि आप उन किताबों पर ही लिखें, जो आपने पढ़ी हों और उनके बारे में आपकी कोई स्पष्ट राय बन सके. पिछले वर्ष मैंने हिंदी की बहुत कम किताबें पढ़ीं और उनमें से दो-तीन को छोड़कर किसी ने मेरे मानस पर कोई छाप नहीं छोड़ी. 2010 हिंदी साहित्य में पुस्तकों के प्रकाशन की दृष्टि से बेहद कमज़ोर रहा. कई कृतियां आईं और चली गईं, अख़बारों में कुछ चर्चा हुई, लेकिन साहित्य में स्थायी महत्व हासिल करने में वे कामयाब नहीं हो पाईं. वहीं अंग्रेजी में इस वर्ष कई अहम किताबें आईं. सबसे पहले शुरुआत करता हूं अंतरराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त भारतीय इतिहासकार एवं लेखक रामचंद्र गुहा द्वारा संपादित एक अहम किताब मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया से. उन्होंने अपनी इस किताब में उन उन्नीस भारतीय महिलाओं और पुरुषों पर लिखा है, जिन्होंने भारतीय गणतंत्र को गहरे तक प्रभावित किया. ये लोग सिर्फ़ राजनेता ही नहीं थे, बल्कि इन्होंने अपने लेखन से भी समाज और देश को एक नई दिशा दी. किताब में पांच खंड हैं. पहले खंड में राजा राम मोहन राय और विभिन्न विषयों पर उनकी राय संकलित की गई है. यह किताब राजा राम मोहन राय से शुरू होती है, जो लेखक के मुताबिक़ पहले भारतीय विचारक थे, जिन्होंने पश्चिम की चुनौतियों को बेहद गंभीरतापूर्वक लिया. हम कह सकते हैं कि राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के पहले ऐसे विचारक थे, जिन्होंने अंधविश्वास और कुरीतियों के ख़िलाफ़ संघर्ष का बिगुल फूंका था. दूसरे खंड में सैयद अहमद ख़ान, ज्योतिराव फुले, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले एवं ताराबाई शिंदे के बारे में लिखा गया है या उनके अहम विचार संकलित किए गए हैं. तीसरा खंड मोटे तौर पर महात्मा गांधी और उनके जीवन एवं दर्शन के इर्द-गिर्द हुई बहसों पर केंद्रित है. गांधी के बारे में गुहा लिखते हैं कि अपने जीवनकाल में ही गांधी को राष्ट्रपिता का दर्जा मिल गया था, लेकिन वह साथ ही उन सारे विवादों के जन्मदाता भी थे, जो देश के भविष्य को लेकर चले थे. गुहा भारतीय गणतंत्र के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू को आधुनिक समय का सबसे विचारवान राजनेता मानते हैं. नेहरू की अपने देश के इतिहास में बेहद रुचि थी, साथ ही राजनीतिक विचारधारा, नए विचारों और आइडियाज में भी उनकी गहरी रुचि थी, जो उन्हें विश्व राजनीति के पटल पर चर्चिल से अलग खड़ा करता था. इसके अलावा गुहा ने रवींद्र नाथ टैगोर, राम मनोहर लोहिया, जय प्रकाश नारायण, एम एस गोलवलकर आदि के बारे में भी अपनी राय रखी है. लेकिन इस किताब में आधुनिक भारत के तीन अहम किरदारों-सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदिरा गांधी को न चुनना चौंकाने वाला है. इसके लिए लेखक के अपने तर्क हैं. उनका कहना है कि इस किताब में उन्हीं लोगों को जगह मिली, जिनके पास अपने विचार थे. ऐसे विचार, जो न सिर्फ़ मौलिक थे, बल्कि समाज को प्रभावित करने वाले भी थे. गुहा के मुताबिक़, सुभाष चंद्र बोस हमारे देश के महान नेता थे, जिन्होंने तीस और चालीस के दशक में भारत के लोगों को अंग्रेजी शासन के ख़िलाफ़ खड़े होने के लिए प्रेरित किया. ठीक उसी तरह वल्लभ भाई पटेल ने देश को एकसूत्र में बांधने तथा इसे एक राष्ट्र का रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, लेकिन दोनों के पास मौलिक विचारों का अभाव था. इसी तरह तक़रीबन डेढ़ दशक तक भारत की प्रधानमंत्री रहीं इंदिरा गांधी को भी मेकर्स ऑफ इंडिया में शुमार न किए जाने पर लेखक का तर्क है कि उन्होंने मौलिक कुछ नहीं लिखा. यहां तक अपने पिता से उलट उनका भाषण भी कोई और ही लिखता था. इन तीन शख्सियतों को किताब में शामिल न किए जाने पर आलोचकों ने गुहा को कठघरे में खड़ा किया, लेकिन मुझे लगता है कि लेखक को इतनी छूट तो होनी ही चाहिए कि वह जिसे चाहे, अपनी रचना में शामिल करे और उसके लिए उसके अपने तर्क हों.

एक दूसरी अहम किताब आई अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश की, जिसका नाम है डिसीजन प्वाइंट. लगभग पांच सौ पन्नों की इस किताब को जॉर्ज बुश के आत्मकथात्मक संस्मरण की श्रेणी में रखा जा सकता है. अपने स्वभाव की तरह ही जॉर्ज बुश की इस किताब में एक खास किस्म की आक्रामकता दिखाई देती है. जॉर्ज बुश ने इस किताब में अपनी यादों को कालक्रम के हिसाब से नहीं लिखा है, बल्कि एक खास थीम को चुनकर उस पर लिखा है. इस वजह से पाठकों को पढ़ते वक़्त आगे-पीछे करना पड़ता है. जॉर्ज बुश के कार्यकाल की सबसे अहम घटना इराक पर अमेरिका का हमला और 9/11 की आतंकवादी घटना थी. ज़ाहिर है, बुश की इस किताब में इन दोनों घटनाओं का प्रमुखता से वर्णन है. इराक पर अमेरिकी हमले को जायज़ ठहराते हुए बुश कहते हैं, मुझे इराक में हो रही घटनाओं पर पिछले दो साल से ख़ुफ़िया रिपोर्ट मिल रही थी, जो काफी चिंताजनक थी. हमें और हमारे सहयोगी देशों को लगातार यह जानकारी मिल रही थी कि इराक में डब्ल्यूएमडी यानी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मौजूद है. हमने इस ख़ुफ़िया रिपोर्ट पर काफी दिनों तक आत्ममंथन किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि अगर सद्दाम हुसैन पर लगाम नहीं लगाई गई तो वह पूरी मानवता के लिए बड़ा ख़तरा हो सकता है. लेकिन बुश के ये तर्क बाद में ग़लत साबित हुए. बुश ने अपनी इस किताब में अपने विचारों को बेहद ही आक्रामक ढंग से प्रस्तुत किया है और यही आक्रामक शैली इसकी विशेषता भी है. उपरोक्त दो विषयों के अलावा बुश ने परिवार, पत्नी, बच्चों और भगवान से अपने रिश्तों पर अपने खास अंदाज़ में लिखा है. एक कहावत है, जो बुश पर पूरी तरह से लागू होती है कि आप उनसे नफ़रत कर सकते हैं, पर उन्हें दरकिनार नहीं कर सकते. ऐसे वाक्यों की भरमार है, जिनमें अंग्रेजी के सामान्य व्याकरण का भी पालन नहीं किया गया है. पूरी किताब को पढ़ने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि टोनी ब्लेयर की यह आत्मकथा दरअसल उनके प्रधानमंत्रित्व काल का दस्तावेजीकरण है, लेकिन इस दस्तावेज में टोनी ब्लेयर ने अपनी राजनीतिक बदमाशियों का जो ज़िक्र किया है, उसकी वजह से इस भारी- भरकम किताब में थोड़ी रोचकता और पठनीयता बनी रहती है.

दो और उपन्यास, जिन्होंने पश्चिम में धूम मचाई और कई हफ्तों तक बेस्ट सेलर बने रहे. पहला है रूम, जिसकी लेखिका हैं एमा डोनोग और दूसरा है फ्रीडम, जिसके लेखक हैं जोनाथन फ्रेन्ज. अमेरिकी लेखक जोनाथन फ्रेन्ज का उपन्यास फ्रीडम तो महीनों तक बेस्ट सेलर की सूची में बना रहा और पाठकों के साथ-साथ आलोचकों ने भी इसे ख़ूब सराहा. जोनाथन के इस उपन्यास के सारे पात्रों ने कहीं न कहीं ज़बरदस्त पाबंदी के बाद स्वतंत्रता के स्वाद को चखा है, लेकिन ज्यों ही वे स्वतंत्रता के जोश में उन्मादी होने लगते हैं, उन्हें ज़बरदस्त ठोकर लगती है और वे ज़मीन पर आ जाते हैं. इस उपन्यास को लेकर अमेरिका में काफी शोरगुल मचा. आलोचकों ने इसके लेखक को टॉलस्टॉय और टॉमस मान के समानांतर खड़ा कर दिया. टाइम पत्रिका ने अपने कवर पर जोनाथन की तस्वीर छापी और उन्हें पिछले दस सालों में प्रकाशन जगत का सबसे ज़्यादा ध्यान खींचने वाला लेखक क़रार दे दिया. यह पूरा उपन्यास एक फैमिली ड्रामा है, जहां मां पैटी अपने बेटे के पास तो जाना चाहती है, लेकिन उसकी पत्नी कोनी को वह पसंद नहीं करती. बेटा

भारतीय युवा लेखिका अद्वैत काला के उपन्यास ऑलमोस्ट सिंगल का हिंदी में मनीषा तनेजा कृत अनुवाद भी आया. मनीषा दिल्ली विश्वविद्यालय में स्पेनिश पढ़ाती हैं और इसके पहले भी गैबरील गारसिया मारक्वैज के उपन्यास एकाकीपन के सौ साल और पॉउलो नेरुदा के संस्मरण का हिंदी में अनुवाद कर चुकी हैं. अद्वैत काला का यह उपन्यास दरअसल आज की युवा पीढ़ी की कहानी है. इस उपन्यास की केंद्रीय पात्र आयशा एकदम बिंदास और विद्रोही है.

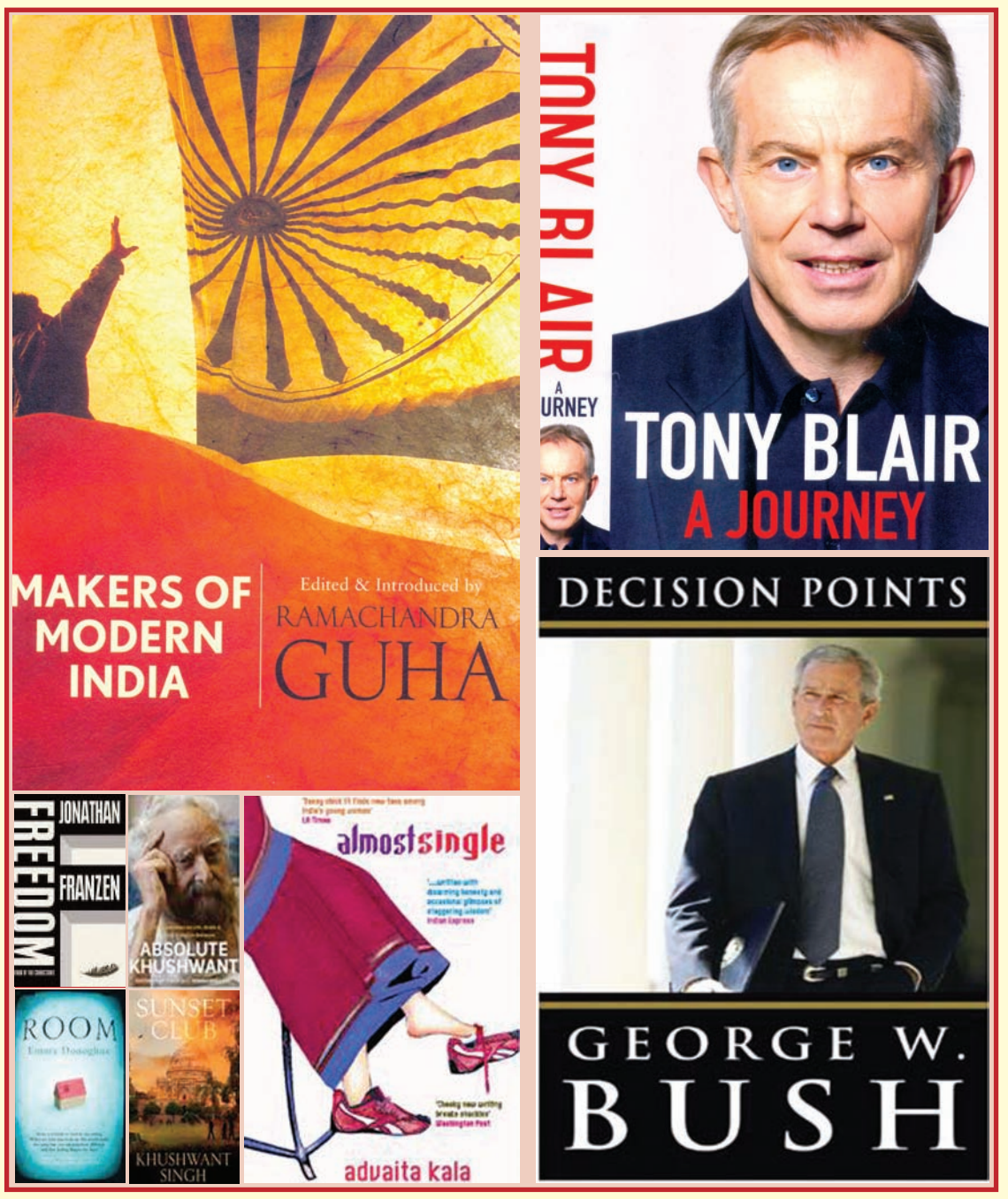

अगर हम वृहत्तर परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह क्राइम स्टोरी न होकर मां-बेटे के रिश्ते की मज़बूती की एक नई इबारत है. कहीं-कहीं इसको पढ़ते हुए तकलीफ होती है, लेकिन अंतत: यह कहानी आपको संतोष देती है.

भारतीय युवा लेखिका अद्वैत काला के उपन्यास ऑलमोस्ट सिंगल का हिंदी में मनीषा तनेजा कृत अनुवाद भी आया. मनीषा दिल्ली विश्वविद्यालय में स्पेनिश पढ़ाती हैं और इसके पहले भी गैबरील गारसिया मारक्वैज के उपन्यास एकाकीपन के सौ साल और पॉउलो नेरुदा के संस्मरण का हिंदी में अनुवाद कर चुकी हैं. अद्वैत काला का यह उपन्यास दरअसल आज की युवा पीढ़ी की कहानी है. इस उपन्यास की केंद्रीय पात्र आयशा एकदम बिंदास और विद्रोही है. दोस्तों के साथ शराब पीना, देर रात तक पार्टी करना, नौकरी करते वक़्त अपने बॉस से घृणा करना, शादी के लिए कहने पर अपनी मां और रिश्तेदारों से उलझना उसके स्वभाव का हिस्सा बन चुका है. अद्वैत काला का यह उपन्यास बदलते भारत की बदलती नारी की तस्वीर है. कहा जाता है कि जब किसी देश में महिलाओं के विचार बदलने लगें तो उसे देश की संस्कृति में बदलाव की आहट के तौर पर समझा जाना चाहिए. अगर इन बातों के इतर हम एक उपन्यास के तौर पर लगभग सिंगल पर विचार करें तो अंग्रेजी की इस युवा लेखिका की तारीफ़ की जानी चाहिए. मनीषा के अनुवाद में मूल की आत्मा की रक्षा की गई है, जिससे उपन्यास के प्रवाह में बाधा नहीं आती.

इसके अलावा अंग्रेजी में ही एक अहम किताब-हियर इज द हॉर्ट ऑफ अ प्रीस्ट प्रकाशित हुई, जिसके प्रकाशन के बाद भारत के कैथोलिक चर्च में आस्था रखने वालों के बीच भूचाल खड़ा हो गया. इस किताब के लेखक हैं के पी शिबू, जो चौबीस साल तक चर्च में प्रीस्ट रहे. *चौथी दुनिया* के पाठकों को याद होगा कि मैंने अपने स्तंभ में पिछले साल सिस्टर जेस्मी की किताब-आमीन एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ नन पर लिखा था. शिबू ने भी चर्च के कर्ताधर्ताओं की सेक्स कुंठाओं और अनैतिक यौन संबंधों को उजागर किया है. शिबू ने यह भी खुलासा किया है कि चर्च में आमतौर पर सीनियर नन अपनी नई सहयोगी को सेक्स के लिए तैयार करती है. कई बार तो नन सेक्स करते वक़्त पकड़ी जाती हैं, लेकिन प्रतिष्ठा बचाने की आड़ में उसे दबा दिया जाता है. शिबू का कहना है कि कई प्रीस्ट तो संकट में फंसी महिलाओं का भी यौन शोषण करते हैं. आर्थिक संकट में फंसी महिलाएं जब प्रीस्ट के पास जाती हैं तो वे उन्हें पैसा तो उपलब्ध करा देते हैं, लेकिन बदले में सेक्स की मांग करते हैं और मजबूर महिला के पास कोई विकल्प नहीं रहता है. सिस्टर जेस्मी की आत्मकथा की तरह इसे भी चर्च ने झूठ का पुलिंदा क़रार दिया है. लेकिन यह सवाल बार-बार मुंह बाए खड़ा हो जाता है कि हर साल ऐसा क्या हो जाता है, जो चर्च से निकल कर उसमें अहम ओहदे पर काम करने वाले सेक्स प्रसंगों पर खुलकर लिखते हैं और सभी के स्वर लगभग एक जैसे होते हैं. दक्षिण के राज्यों में इस किताब को लेकर खासी चर्चा रही.

खुशवंत सिंह पत्रकारिता और साहित्य की दुनिया का एक जाना- माना नाम है. छियानवे साल की उम्र में भी खुशवंत सिंह हर हफ्ते दो स्तंभ लिखते हैं, नियमित अंतराल पर पत्र-पत्रिकाओं में किताबों की समीक्षा लिखते हैं. साथ ही उतनी ही नियमितता के साथ किताबें भी लिखते हैं. इस उम्र में उनकी सक्रियता न सिर्फ़ चौंकाती है, बल्कि प्रेरित भी करती है. इस साल उनकी दो किताबें आईं-एबसोल्यूट खुशवंत, जो उन्होंने हुमा कुरैशी के साथ मिलकर लिखी. दूसरी-सनसेट क्लब, जो दिसंबर के प्रथम सप्ताह में जारी हुई. खुशवंत सिंह का व्यक्तित्व बेहद दिलचस्प है. मैंने दोनों किताबें नहीं पढ़ी हैं, लेकिन राजधानी की दुकानों में जिस तरह ये किताबें बिक रही हैं, उससे लगता है कि पाठकों को पसंद आ रही हैं. इस वजह से मुझे लगा कि इसका उल्लेख ज़रूरी है. मैं इस लेख में हिंदी की किताबों का उल्लेख जानबूझ कर नहीं कर रहा. साल भर जो किताबें पढ़ीं, उनमें से मुझे सिर्फ़ याद है रवींद्र कालिया की किताब-17 रानडे रोड. यह किताब मुझे बेहद पसंद आई थी. पसंद इस वजह से आई कि लेखक रवींद्र कालिया के कहने का अंदाज़ बेहद दिलचस्प है. एक बार जब आप किताब पढ़ना शुरू करेंगे तो फिर ख़त्म करने के बाद ही रुक पाएंगे. मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि कालिया की यह किताब इस वर्ष की उपलब्धि है.

ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर की आत्मकथा-जर्नी भी प्रकाशित होकर खासी चर्चित हो चुकी है. टोनी ब्लेयर ब्रिटेन के पहले ऐसे राजनेता थे, जो बग़ैर किसी सरकारी अनुभव के सीधे प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हुए थे. टोनी ब्लेयर ने 1994 में लेबर पार्टी की कमान संभाली और तीन साल के अंदर पार्टी में जो बदलाव किया, उसे लेकर वहां की जनता में एक उम्मीद जगी और 1997 में ब्लेयर को अपार जनसमर्थन मिला, जो ब्रिटेन के इतिहास में अभूतपूर्व था. तक़रीबन सात सौ पन्नों की इस आत्मकथा में टोनी ने राजनीति में अपने प्रवेश से लेकर समकालीन विश्व राजनेताओं के साथ अपने संबंधों का भी खुलासा किया है. इसके अलावा टोनी ने एक पूरा अध्याय ब्रिटेन की अपूर्व सुंदरी प्रिंसेस डायना पर भी लिखा है. इस अध्याय में टोनी द्वारा डायना के साथ की गई भारत, सऊदी अरब, इटली आदि की यात्रा का उल्लेख भी है. टोनी लिखते हैं, डायना एक आयकॉन थीं और संभवत: विश्व की सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध महिला थीं, जिनके सबसे ज़्यादा फोटोग्राफ खींचे गए थे. वह अपने समय की एक ऐसी ख़ूबसूरत महिला थीं, जो अपने संपर्क में आने वाले लोगों पर अपने व्यक्तित्व की अमिट छाप छोड़ती थीं. दरअसल टोनी ने भी अपनी आत्मकथा को बुश की तरह ही कालक्रम के हिसाब से नहीं लिखा है, उन्होंने हर अध्याय को एक थीम दी है. नतीजा यह हुआ कि पूरी किताब में एक भ्रम की स्थिति बनती नज़र आती है. सांप-सीढ़ी के खेल की तरह संस्मरण भी भटकता नज़र आता है. चार्ल्स मूर ने कहा कि यह किताब बेहद अनाकर्षक ढंग से लिखी गई है. इसमें ऐसे वाक्यों की भरमार है, जिनमें अंग्रेजी के सामान्य व्याकरण का भी पालन नहीं किया गया है. पूरी किताब को पढ़ने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि टोनी ब्लेयर की यह आत्मकथा दरअसल उनके प्रधानमंत्रित्व काल का दस्तावेजीकरण है, लेकिन इस दस्तावेज में टोनी ब्लेयर ने अपनी राजनीतिक बदमाशियों का जो ज़िक्र किया है, उसकी वजह से इस भारी- भरकम किताब में थोड़ी रोचकता और पठनीयता बनी रहती है.

जॉय अपनी पत्नी के अलावा बेहद ख़ूबसूरत लड़की जेना में सुकून तलाशता है. पैटी को पति वॉल्टर की सेक्रेटरी ललिता फूटी आंखों नहीं सुहाती.

इसके अलावा एमा डोनोग के उपन्यास रूम की भी बेहद चर्चा रही. यह कहानी है एक पांच साल के बच्चे जैक की, जिसकी मां को एक व्यक्ति ने अगवा कर बंधक बनाकर एक छोटे से कमरे में कैद कर लिया है, जहां वह रोज रात को आकर उसके साथ बलात्कार करता है. जैक को हर रोज होने वाले बलात्कार की जानकारी नहीं होती है, क्योंकि जब उस व्यक्ति के आने का वक़्त होता है तो उसकी मां जैक को अलमारी के अंदर बंद करके सुला देती है. मां-बेटे ज़हालत की ज़िंदगी जीते रहते हैं और समय बीतता चला जाता है. एमा बंद कमरे में एक मां के दर्द को बग़ैर लिखे इस तरह से पेश करती है और पाठकों को चुनौती देती है कि वे जो नहीं लिखा गया है, उसे महसूस करें. अचानक एक दिन जैक की मां को एहसास होता है कि ओल्ड निक उसके बेटे में रुचि लेने लगा है. ख़तरे को भांपते हुए वह कैदखाने से निकल भागती है. जैक और उसकी मां बाहर की दुनिया को देखते-समझते हुए उसमें ख़ुद को ढालने की भी कोशिश करते हैं. हर पल कहानी में उतार-चढ़ाव आता रहता है. इन पलों को चित्रित करते हुए एमा भावनाओं का इस्तेमाल इस तरह से करती हैं कि कहानी पाठकों को बांध लेती है. एमा डोनोग पर यह आरोप भी लगा कि उसने ऑस्ट्रिया के पापी पिता जोश फ्रिट्ज की दरिंदगी की दास्तां को अपने इस उपन्यास का प्लॉट बनाया. लोग ग़लतफहमी में इसे क्राइम स्टोरी समझ रहे हैं. दरअसल

ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर की आत्मकथा-जर्नी भी प्रकाशित होकर खासी चर्चित हो चुकी है. टोनी ब्लेयर ब्रिटेन के पहले ऐसे राजनेता थे, जो बग़ैर किसी सरकारी अनुभव के सीधे प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हुए थे. टोनी ब्लेयर ने 1994 में लेबर पार्टी की कमान संभाली और तीन साल के अंदर पार्टी में जो बदलाव किया, उसे लेकर वहां की जनता में एक उम्मीद जगी और 1997 में ब्लेयर को अपार जनसमर्थन मिला, जो ब्रिटेन के इतिहास में अभूतपूर्व था.

(लेखक आईबीएन-7 से जुड़े हैं)
anant.ibn@gmail.com

इंडिया यामाहा मोटर के मुख्य कार्याधिकारी एवं प्रबंध निदेशक हिरोयुकी सुजूकी ने कहा कि यामाहा के लिए भारत प्रमुख बाज़ारों में से एक है, जहां वे लोगों को दमदार मोटरसाइकिलें उपलब्ध कराने की लगातार कोशिश कर रहे हैं.

दिल्ली, 27 दिसंबर 2010-02 जनवरी 2011 चौथी दुनिया

निसान माइक्रा के डीजल वेरिएंट

निसान की लोकप्रिय कार माइक्रा का डीजल वर्जन लांच हो गया है. विश्व की अग्रणी वाहन निर्माता कंपनी निसान ने पुश बटन टेक्नोलॉजी वाली कार माइक्रा के दो डीज़ल वेरिएंट लांच किए हैं. भारत में इस कार के पेट्रोल संस्करण की ज़बरस्त सफलता को देखते हुए कंपनी ने इसके डीजल संस्करण बाज़ार में उतारने का फ़ैसला किया था. कंपनी के मुताबिक़ , डीजल माइक्रा 23.08 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देगी. इस कार में 1.5 लीटर का डीज़ल इंजन है. इसका टार्क 2000 आरपीएम पर 160 एनएम का पावर देगा. इसका इंजन पहले से ज़्यादा परिष्कृत और शोर रहित है. यह कार छह रंगों में उपलब्ध होगी, जिसमें सनलाइट ऑरेंज, ब्रिक रेड, पैसिफिक ब्लू, स्टॉर्म व्हाइट, ब्लेड सिल्वर और ऑनिक्स ब्लैक शामिल हैं.

लांचिंग के समय निसान की भारत में संयुक्त रणनीतिकार होवर आटोमोटिव के सीईओ दिनेश जैन भी मौजूद थे. उन्होंने बताया कि सफर को यादगार बनाने वाली इस कार में पुश बटन टेक्नोलाजी है. इसके ज़रिए आप बटन दबाकर इंजन चालू कर सकते हैं. इसकी ईंधन खपत 23.08 किलोमीटर प्रति लीटर है. कंपनी ने डीजल वर्जन के दो मॉडल पेश किए हैं. एक है एक्सवी, जिसकी क़ीमत है 5,58,000 रुपये और दूसरा है एक्सवी प्रीमियम, जिसकी क़ीमत है 6,04,500 रुपये. कंपनी के एमडी एवं सीईओ कोमिनोबु तोकूयामा ने उम्मीद ज़ाहिर की कि यह कार पेट्रोल इंजन वाली कार की तरह ही सफल होगी. कंपनी ने जुलाई में पेट्रोल वर्जन पेश किया था और तबसे अब तक वह ऐसी 6,000 कारें बेच चुकी है. मध्यमवर्गीय लोगों के लिए बनाई गई छोटी कार माइक्रा जल्द ही सड़कों पर दौड़ने लगेगी.

यामाहा की नई बाइक

भारत में लग्ज़री कारों की बिक्री तो तेजी से बढ़ ही रही है, इसके साथ-साथ देश में महंगी बाइक्स के शौकीनों की संख्या में भी तेजी से इज़ाफ़ा हो रहा है. इसे देखते हुए दोपहिया वाहन बनाने वाली जानी-मानी कंपनी यामाहा ने भारत में 998 सीसी की मोटरसाइकिल एफजेड-1 लांच की है. इस बेहद खास बाइक की क़ीमत 8.7 लाख रुपये है. एफजेड-1 में कंपनी ने 4 स्ट्रोक लिक्विड कूल्ड इंजन का इस्तेमाल किया है. इस खास तकनीक की मदद से लंबे सफर के दौरान भी बाइक का इंजन एकदम दुरुस्त रहेगा. साथ ही इसमें डिजिटल टीसीआई इग्निशन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है. इस बाइक के साथ ही कंपनी ने 153 सीसी की मोटरसाइकिल एसजेड-आर भी भारतीय बाज़ार में उतारी है, जिसकी क़ीमत 55,500 रुपये है. इस समय भारतीय बाज़ार में कंपनी की तीन महंगी मोटरसाइकिलें-वीमैक्स, एमटी-01 और वाईजेडएफ-आर-1 मौजूद हैं. यामाहा के पूर्ण स्वामित्व वाली भारतीय इकाई इंडिया यामाहा मोटर के मुख्य कार्याधिकारी एवं प्रबंध निदेशक हिरोयुकी सुजूकी ने बताया कि यामाहा के लिए भारत प्रमुख बाजारों में से एक है, जहां वह लोगों को दमदार मोटरसाइकिलें उपलब्ध कराने की लगातार कोशिशें कर रही है. भारत में स्टाइलिश और स्पोर्टस बाइक के प्रति यंग राइडर्स का रुझान बढ़ता जा रहा है. इसे देखते हुए कंपनी ने ये स्टाइलिश बाइक को बाज़ार में उतारा है.

इस बेहद खास बाइक की क़ीमत 8.7 लाख रुपये है. एफजेड-1 में कंपनी ने 4 स्ट्रोक लिक्विड कूल्ड इंजन का इस्तेमाल किया है. इस खास तकनीक की मदद से लंबे सफ़र के दौरान भी बाइक का इंजन एकदम दुरुस्त रहेगा.

साफ़ हवा में सांस लें

दिनोंदिन बढ़ते प्रदूषण का तोड़ शार्प कंपनी ने निकाल लिया है. शार्प ने भारत में प्लाज़्मा क्लस्टर आयन जेनरेटर पेश किया है. यह अपने तरह की पहली ऐसी तकनीक है, जो भारतीय बाज़ार में उतारी गई. यह तकनीक वातावरण को शुद्ध बनाने के काम आती है. यह जंगलों में मिलने वाली शुद्ध और साफ हवा की तरह पॉजीटिव और निगेटिव कण पैदा करती है. शार्प प्लाज़्मा क्लस्टर आयन जेनरेटर वातावररण में फैली बदबू को जल्द हटाने में मददगार होता है. कई बार खाने, सिगरेट, पेंट, टॉयलेट, पालतू जानवर एवं कूड़े आदि की बदबू कमरे में फैल जाती है, जिसे हटाकर यह मॉर्निंग एलर्जी होने से रोकता है और अस्थमा के मरीजों के लिए उपयोगी है. प्रकृति हमें स्वच्छ हवा प्रदान करती है, लेकिन आधुनिक जीवनशैली में वातावरण दूषित होने की वजह से सांस लेना मुश्किल है. शार्प की इस तकनीक के ज़रिए हम दूषित हवा को स्वच्छ बनाकर सांस ले सकते हैं. साफ हवा में सांस लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दूषित हवा से होने वाली बीमारियां अक्सर जानलेवा होती हैं.

शार्प के इस प्रोडक्ट में हाइड्रोक्सिल होता है, जो एक बेहतरीन वायु ऑक्सीडेंट माना जाता है. यह वातावरण से वायरस साफ करने, जर्म एवं बैक्टीरिया मारने, फंगल व मरे हुए कीट-पतंगों से फैलने वाले माइक्रो ऑरगैनिज़्म को साफ करने के लिए बेहतरीन डिटरजेंट है. एयर प्यूरीफायर के अलावा प्लाज़्मा क्लस्टर आयन जेनरेटर फ्रेश हवा बनाता है और नेचुरल डिटरजेंट की तरह काम करता है. यह घर, ऑफिस, होटल एवं अन्य जगहों पर आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके विभिन्न मॉडलों की क़ीमत 14,999 से लेकर 19,990 रुपये तक है.

नया फुल टच मोबाइल

पाइन ने तमाम ख़ूबियों से लैस फोन पोलो लांच किया है. सिंगापुर स्थित पाइन मोबाइल्स अपने हाईटेक फोन के ज़रिए भारतीय बाज़ार में छा जाने के लिए तैयार है. पोलो का पोर्टफोलियो फुल टच 2.8 एलसीडी से शुरू होता है, जिससे इसका इस्तेमाल आसान हो जाता है. पोलो ऑपरमिनी (मोबाइल ब्राउजर), निमबज और स्नातु जैसे एप्लीकेशंस से लैस है. यह डिवाइस जावा एप्लीकेशन को भी सपोर्ट करती है. इसमें 58 एमबी की इंटरनल मेमोरी उपलब्ध है. 32 जीबी तक टी-फ्लैश सपोर्ट और 2.0 मेगा पिक्सल कैमरा इस फोन को बेहतरीन फोटोग्राफी के लिए उपयुक्त बनाता है. इस पर लंबी दूरी तक मोबाइल ट्रैकिंग की भी सुविधा है, जो इसे और भी खास बनाती है.

पाइन मोबाइल के सीईओ रोहित अग्रवाल ने कहा कि विकसित एवं विकासशील देशों में बेहतरीन तकनीक की मांग है. पोलो ऐसी बेहतरीन तकनीक का इस्तेमाल करके ही डिज़ाइन किया गया है, जो आमजन के लिए उपयुक्त हो. कंपनी ने हाई एंड पोलो फोन को बाज़ार में अपडेटेड एप्लीकेशंस और तकनीक के साथ पेश किया है. भारतीय बाज़ारों के लिए खास तौर पर उपयुक्त बनाने के लिए इसमें हिंदी पंचांग की सुविधा दी गई है. कॉल रिकॉर्डिंग, ब्लैक लिस्ट और आंसरिंग मशीन जैसी सुविधाएं भी इसमें उपलब्ध हैं. इसमें अगली पीढ़ी का म्यूज़िक प्लेयर भी इंस्टॉल है, जो हैंडसेट को और ज़्यादा उपयुक्त बनाता है. यह पाइन मोबाइल्स के सभी आउटलेट्स और अन्य बड़े मोबाइल आउटलेट्स पर 5999 रुपये की एमआरपी और 4200-4250 रुपये की एमओपी पर उपलब्ध है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

ट्रेनिंग सेशन के बाद साइना को स्कूल भी जाना होता था. ऐसे में मैं उसे रोज स्कूल छोड़ने और ले आने के लिए 50 किलोमीटर स्कूटर चलाकर जाता था.

साइना की शाइनिंग रहे बरक़रार

राजेश एस कुमार

एक दौर था, जब टेनिस की दुनिया में भारत का नाम लेने वाला कोई नहीं था. अमृतराज के अलावा टेनिस में शायद ही कोई नाम हो, जिसकी वजह से भारत का नाम अंतरराष्ट्रीय खेल परिदृश्य में उभरा हो. वक़्त गुजरा और सानिया एवं साइना ने टेनिस वर्ल्ड में पदार्पण किया. इनके क़दम रखते ही ग्लैमर ने भी इस खेल में ज़बरदस्त घुसपैठ की. ग्लैमर के तड़के ने सानिया मिर्जा को तो अर्श से फर्श पर लाकर खड़ा कर दिया, लेकिन साइना अभी भी इस चक्रव्यूह से बाहर हैं. न सिर्फ़ बाहर है, बल्कि उनका प्रदर्शन भी दिनोंदिन बेहतर होता जा रहा है. खेल के कई बड़े पुरस्कारों से नवाजी जा चुकीं 20 वर्षीय साइना इस समय भारत की सबसे सफल महिला खिलाड़ी हैं. जिस तरह उन्होंने हांगकांग सुपर सीरीज बैडमिंटन खिताब अपने नाम कर एक बार फिर विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में दूसरे पायदान पर जगह बनाई है, वह काबिले तारीफ़ है. ग़ौरतलब है कि साइना हांगकांग टूर्नामेंट से पहले दो स्थान गिरकर चौथे स्थान पर पहुंच गई थीं, लेकिन फिर से हांगकांग के एक कड़े मुक़ाबले में बाज़ी मारकर उन्होंने अपनी रैंकिंग में दो स्थान का सुधार किया और फिर से दूसरे पायदान पर पहुंच गईं. बीते साल के बेहतर प्रदर्शन को बरक़रार रखते हुए उन्होंने 2010 में पांच खिताबों और देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न को अपनी झोली में डाला. लेकिन यहां ग़ौर करने वाली बात यह है कि उन्हें यह सफलता यूं ही नहीं मिल गई है. इस सफलता की कहानी लिखने में कड़ी मेहनत और लंबे संघर्ष की स्याही छिपी हुई है.

साइना में ओलंपिक मेडल जीतने की क्षमता है. उसने अभी अपना करियर ही शुरू किया है. वह कम से कम दो और ओलंपिक में हिस्सा लेगी. दिनोंदिन उसका खेल और धारदार होता जा रहा है.

-पी गोपीचंद, साइना के कोच एवं पूर्व बैडमिंटन चैंपियन

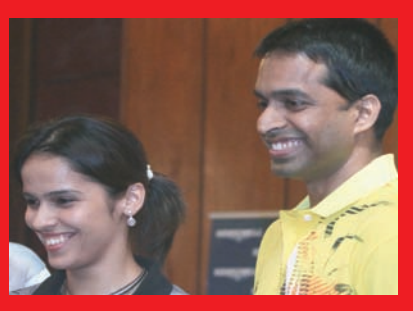

साइना कई वर्षों से किसी पार्टी, रेस्तरां या सिनेमाहॉल में नहीं गई थी. जब पहली बार मीडिया वाले मेरे घर पर एक कार्यक्रम शूट करने आए तो मैं उन्हें मिठाई भी नहीं खिला सका.

-हरवीर सिंह, साइना के पिता

17 मार्च, 1990 को हरियाणा के हिसार में जन्मी साइना आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में पली-बढ़ी हैं. उनका बैडमिंटन प्रशिक्षण सात साल की उम्र में ही हैदराबाद के लाल बहादुर स्टेडियम में शुरू हो गया था. उनके माता-पिता भी हरियाणा की तरफ़ से बैडमिंटन खेलते थे. ज़ाहिर है, उनके असर से साइना अछूती नहीं रहीं. वह कहती हैं कि मेरे माता-पिता ने मुझे एक बेहतर खिलाड़ी बनाने में जितनी मेहनत की है, अच्छे प्रदर्शन के बल पर वह उसे सफल करना चाहती हैं. ग़ौरतलब है कि साइना के पिता हरवीर सिंह हैदराबाद के डायरेक्ट्रेट ऑफ ऑयल सीड्स रिसर्च में वैज्ञानिक हैं. पिता हरवीर सिंह के मुताबिक़, साइना जिस स्टेडियम में प्रैक्टिस करने जाती थी, वह घर से 20 किलोमीटर की दूरी पर था. ट्रेनिंग सेशन के बाद साइना को स्कूल भी जाना होता था. ऐसे में मैं उसे रोज स्कूल छोड़ने और ले आने के लिए 50 किलोमीटर स्कूटर चलाकर जाता था. बीते दिनों को याद करते हुए वह कहते हैं कि एक्स्ट्रा ट्रेनिंग सेशन शुरू होने के बाद हर दिन साइना पर 150 रुपये का ख़र्च गाड़ी-भाड़ा पर आता था. इसके अलावा रैकेट एवं जूते आदि ख़रीदने पर भी ख़र्च होता था. इस तरह हर महीने उस पर 12 हज़ार रुपये ख़र्च होने लगे. चूंकि उस समय इतनी बड़ी राशि ख़र्च करना मेरे लिए मुश्किल था, सो इस ख़र्चे को मैनेज करने के लिए मुझे अपने प्रॉविडेंट फंड से पैसे भी निकालने पड़े. कभी-कभी साइना की खेल संबंधी ज़रूरतें पूरी करने के लिए 30 हज़ार रुपये तो कभी एक लाख रुपये तक निकालने पड़े. इसी तरह न जाने कितने संघर्ष के रास्तों से गुजर कर साइना इस मुक़ाम तक पहुंची है.

हालांकि साइना अभी अपने लक्ष्य से थोड़ा दूर हैं. उनका अंतिम लक्ष्य विश्व रैंकिंग में एक नंबर के पायदान पर पहुंचना है. अगर थोड़ा पीछे जाकर देखें तो साइना ने 2006 में विश्व बैडमिंटन जगत में अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी थी. यह वह दौर था, जब उन्होंने फिलीपींस ओपन प्रतियोगिता जीती. बीजिंग में आयोजित ओलंपिक खेलों में वह अंतिम आठ में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी भी बनी थीं. उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और तबसे अभी तक विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में लगातार ऊपर की ओर ही बढ़ती जा रही हैं. हालांकि उनके सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं. इन चुनौतियों में कड़ी प्रतियोगिताएं हैं, साथ ही सफलता का गुरूर, ग्लैमर की चकाचौंध और पेज थ्री पार्टियां भी हैं. अगर इन सबसे साइना बची रहती हैं तो फिर खेलप्रेमियों का आशीर्वाद और उम्मीदें उनके साथ हैं.

rajeshy@chauthiduniya.com

क्या कहते हैं सितारे

साइना नवंबर 2013 तक अपने खेल में शीर्ष पर बनी रहेंगी. साइना की कुंडली में मंगल उच्च राशि में है, जो उन्हें बहुत जुझारू और मेहनती बनाता है. अभी साइना की कुंडली में बुध की महादशा चल रही है, जिसमें शुक्र का अंतर है, इसलिए उन्होंने नवंबर और दिसंबर के टूर्नामेंट्स में बेहतरीन प्रदर्शन किया है. वह बहुत जल्द ही विश्व की शीर्षस्थ खिलाड़ी बनेंगी और लंबे समय तक इस पर कायम भी रहेंगी. उनकी कुंडली में बुधादित्य योग भी है, जो उन्हें हमेशा सुर्खियों में रखता है और प्रसिद्धि भी दिलाता है. लेकिन उनका चंद्रमा नीच राशि में है, इसलिए कई बार उनका आत्मविश्वास डगमगा जाता है. कुल मिलाकर साइना का खेल और सितारे दोनों बुलंदी पर हैं.

फोटो-प्रभात पाण्डेय

देश का पहला इंटरनेट टीवी

हर दिन 50,000 से ज़्यादा दर्शक

- दो टूक-संतोष भारतीय के साथ
- ब्लैक एंड व्हाइट रोज़ाना 1 बजे
- पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया
- स्पेशल रिपोर्ट
- नायाब हैं हम-उर्दू के मशहूर शायरों, गीतकारों के साथ मुलाक़ात
- साई की महिमा

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301 www.chauthiduniya.tv

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. DELHIN/2009/30467

कलयुग में ग्रे शेड का किरदार निभाने के बाद उनकी एक-दो फिल्में और भी आईं, जो ज़्यादा नहीं चल पाईं, लेकिन इंडस्ट्री में उन्हें नोटिस कर लिया गया.

बदल गईं असिन

जबसे असिन की नई फिल्म आने की चर्चा आम हुई है, तबसे असिन पब्लिक वेन्यूज पर नज़र आने लगी हैं. आम तौर पर पार्टियों से परहेज़ करने वाली असिन अब ऐसे मौक़ों पर ख़ूब रंग जमाने लगी हैं. हाल में मुंबई की एक पार्टी में असिन काफी हॉट और हैपनिंग नज़र आईं. हो भी क्यों न, आजकल उनके पास कुछ अच्छी फिल्में हैं. सलमान ख़ान के साथ अनीस बज्मी की रेडी के अलावा नील नितिन मुकेश के साथ वह फिल्म पॉकेटमार में बतौर मुख्य कलाकार नज़र आने वाली हैं. इस फिल्म के निर्माता हैं रवि चोपड़ा. फिल्म गजनी के बाद लंदन ड्रीम्स आने तक असिन को बॉलीवुड में ज़बरदस्त उछाल मिला था, जबकि लंदन ड्रीम्स के फ्लॉप होने के बाद उनके सारे भाव उतर गए. उसके बाद वह केवल विज्ञापनों में ही नज़र आईं. इस बीच उनके सितारे गर्दिश में रहे, लेकिन एक बार फिर उनके सितारे बुलंदी पर हैं. यही वजह है कि वह अब फिर से पब्लिक इवेंट्स में नज़र आने लगी हैं. मुंबई के एक पांच सितारा होटल की पार्टी में ख़ूबसूरत ड्रेस में असिन काफी स्टाइलिश और कॉन्फिडेंट लग रही थीं. उनके ड्रेसिंग सेंस के भी चर्चे होने लगे हैं. क्लासी मस्टर्ड येलो लेसी ड्रेस में असिन के जलवे देखने लायक़ थे. मेटालिक रंग की ड्रेस के साथ मेटल एक्सेसरीज, चंक इयररिंग्स, स्पार्कलिंग रिंग, पेंसिल हील और मेटालिक कलर मेकअप में असिन टोटल ग्लैमरस गर्ल लग रही थीं.

ख़ुश हैं जिनेलिया

बॉलीवुड में कुछ बहुत ही बेहतरीन फिल्में करने के बाद भी जिनेलिया डिसूजा को ग्लैमर इंडस्ट्री में खास जगह नहीं मिल पाई. बॉलीवुड में उनकी मौजूदगी के बारे में कहा जा सकता है कि यहां एक फिल्म करने के बाद उन्हें वापस दक्षिण फिल्म इंडस्ट्री की याद आ ही जाती है. हाल में ही आई उनकी तमिल फिल्म ओरेंज है. यह फिल्म युवाओं के बीच इतनी लोकप्रिय हो चुकी थी कि थिएटर में लगने से पहले ही इसकी टिकटें बिक चुकी थीं. इस फिल्म में जिनेलिया के साथ रामचरण तनेजा थे, जो सिल्वर स्क्रीन पर पहली बार नज़र आए. इसी साल आई उनकी फिल्म हुक या क्रुक कुछ खास नहीं चली, लेकिन इससे जिनेलिया की उम्मीदें कुछ कम नहीं हुई हैं. उन्होंने अपनी पुरानी आदत के अनुसार फिर से दक्षिण फिल्म इंडस्ट्री की ओर रुख़ कर लिया है. दक्षिण की फिल्मों से उनका प्रेम जगज़ाहिर है और यह जायज़ भी है, क्योंकि तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में काम करके जिनेलिया ने ख़ूब नाम कमाया, तभी जाकर उन्हें हिंदी फिल्मों का ऑफर मिला. उनकी पहली फिल्म तुझे मेरी कसम के लिए ऑफर ख़ुद रामोजी राव की तरफ़ से आया था, जिससे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए उनके रास्ते खुले. जिनेलिया को ख़ुद के इस इंडस्ट्री में ज़्यादा न चल पाने का दु:ख नहीं है, बल्कि उन्हें यह सोचकर अच्छा लगता है कि चार भाषाओं की फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें ख़ूब जगह मिली. इंग्लैंड से ताल्लुक रखने वाली भारतीय मूल की इस अदाकारा के बारे में शायद ही लोगों को पता होगा कि यह स्टेट लेवल एथलीट रही हैं और बास्केटबॉल एवं वॉलीबॉल भी खेलना बख़ूबी जानती हैं.

गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड

डस्की और डार्क मॉडल को बॉलीवुड में ख़ूब सराहना मिली है. मॉडल ने भी अपनी पर्सनालिटी के अनुसार ही फिल्मों का किरदार निभाया. दीपल साव उन खास हीरोइनों में हैं, जिन्हें बहुत ही कम फिल्में मिली हैं, लेकिन फिर भी वह इस इंडस्ट्री में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में सक्षम रही हैं. कलयुग में ग्रे शेड का किरदार निभाने के बाद उनकी एक-दो फिल्में और भी आईं, जो ज़्यादा नहीं चल पाईं, लेकिन इंडस्ट्री में उन्हें नोटिस कर लिया गया. काफी वक़्त के बाद वह एक और फिल्म में नज़र आने वाली हैं, जिसका नाम है साहिब, बीवी और गैंगस्टर. इसे बनाया है तिगमांशु धूलिया ने. इसमें दीपल गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड का रोल अदा कर रही हैं. गैंगस्टर का किरदार रणदीप हुड्डा निभा रहे हैं. दीपल एक वाइब्रेंट, ख़ुशमिजाज़ और मस्तमौला लड़की का रोल अदा कर रही हैं. तिगमांशू के अनुसार, दीपल का रोल वहीदा रहमान के स्क्रीन परफॉर्मेंस जैसा होना चाहिए. फिल्म में न केवल उनका रोल खास है, बल्कि शूटिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला कैमरा भी खास है. देश में पहली बार एलेक्सा कैमरे को शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया गया. फिल्म की सौ प्रतिशत शूटिंग रीयल लोकेशन में हुई है. केवल तीस दिनों में ही पूरी फिल्म शूट कर ली गई. फिल्म में दीपल के अलावा जिमी शेरगिल, माही गिल, श्रेया नारायण, दीपराज राणा आदि प्रमुख हैं.

समझदार प्रियंका

देश के एक छोटे शहर से आईं प्रियंका अपने जीवन में भावनात्मक मूल्यों को बख़ूबी समझती हैं. शायद इसीलिए उन्होंने न्यू इयर सेलिब्रेशन पार्टी में भाग लेने से इंकार कर दिया. नए साल के नए दिन का स्वागत करने के लिए वह अपने परिवारवालों का साथ चाहती थीं. न्यू इयर की रात को उन्होंने अपने लिए कोई भी कार्यक्रम नहीं बनाया. इस इवेंट पर स्टेज परफॉर्मेंस देने के लिए उन्हें तीन करोड़ रुपये का ऑफर मिला था. वेल पिगी चॉप्स के बारे में उनके फैंस के लिए कुछ अच्छी ख़बर भी है. वह करण जौहर की आने वाली फिल्म, जो 1990 के क्लासिक सिनेमा अग्निपथ का रीमेक होगी, में नज़र आने वाली हैं. इस फिल्म में वह रितिक रोशन के अपोजिट सेक्स वर्कर का किरदार अदा करेंगी, जिसका नाम काली होगा. प्रियंका इन दिनों काम के अलावा अपने दोस्तों को ख़ुश करने में भी लगी हैं. दरअसल शाहिद कपूर अपनी अगली फिल्म के लिए चंडीगढ़ में शूटिंग कर रहे थे. मौसम का मज़ा तो वह शूटिंग के दौरान ले ही रहे थे कि अचानक उनकी दोस्त प्रियंका ने आकर उन्हें सरप्राइज़ गिफ्ट दे दिया. फिर दोनों ने चंडीगढ़ के एक लक्ज़रीयस स्पा का भी लुत्फ उठाया. वेल प्रियंका, आपका रिश्तों को महत्व देना हमें भी अच्छा लगा. उम्मीद है कि प्रियंका का यह अंदाज़ उनके प्रशंसकों को भी पसंद आएगा.

प्रीव्यू

भूत एंड फ्रेंड्स

टूनपुर का सुपर हीरो की रिलीज़ के बाद एक बार फिर सिनेमाघरों में बच्चे नज़र आने वाले हैं, क्योंकि आने वाले शुक्रवार को वहां बच्चों की फिल्म भूत एंड फ्रेंड्स चमकने लगेगी. इसकी रिलीज की तिथि बच्चों की छुट्टियों का ध्यान रखते हुए तय की गई है. फिल्म के प्रोड्यूसर अनीस अर्जुन देव ने रिलीज की तारीख़ पहले 24 दिसंबर रखी थी, लेकिन उसी दिन टूनपुर का सुपर हीरो की रिलीज़ होने की वजह से उन्हें तारीख़ में परिवर्तन करना पड़ा. उनका मानना है कि इससे फिल्म का कारोबार बढ़ेगा, क्योंकि इसके कंपटीशन में दूसरी कोई फिल्म नहीं होगी. बच्चों की यह फिल्म उनके पसंदीदा जॉनर एडवेंचर पर बनी है. यह उन कहानियों पर आधारित है, जिन्हें सुनकर बच्चे बड़े होते हैं. सिर्फ़ बच्चे ही नहीं, बल्कि बड़े भी इस फिल्म का पूरा लुत्फ उठाएंगे. फिल्म को बेहतरीन बनाने के लिए इफेक्ट और एनिमेशन का इस्तेमाल किया गया है. किट्टू सलूजा द्वारा निर्मित इस मैजिकल थ्रिलर में जैकी श्रॉफ भूत बने हैं. उनके नन्हें दोस्तों का किरदार अदा किया है मार्कंड सोनी, इशिता पंचाल, आकाश नायर और तेजस रहेजा ने. मार्कंड एक प्रसिद्ध टीवी सीरियल पर बनी फिल्म खिचड़ी में काम कर चुके हैं, जबकि इशिता टेलीविज़न सीरियल उतरन में तप्पू के रोल में काफी नाम कमा चुकी हैं. यह फिल्म वाइड एंगल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले प्रोड्यूस की गई है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

मलाइका बनीं जज

मुन्नी जबसे बदनाम हुई है, सफलता उसके क़दम चूम रही है. वजह यह है कि उसे अपने ठुमके पर सबको नचाने के बाद दूसरे के ठुमकों में दम जांचने का ज़िम्मा मिल गया है. मुन्नी यानी मलाइका अरोड़ा आजकल एक टीवी चैनल के डांसिंग रियलिटी शो की जज हैं. इसमें उनके साथ माधुरी दीक्षित और कोरियोग्राफर रीमो हैं. मुन्नी बदनाम हुई की सफलता का जश्न उन्होंने अभी हाल में अपने जन्मदिन के साथ मनाया. बहन अमृता और बहनोई शकील के साथ यह उनका पहला हॉलीडे था. इस मौके पर पूरे परिवार के अलावा पति अरबाज़ और बेटा अहान भी साथ थे. इसके बाद ही वह बाम के एक कमर्शियल एड में तमिल सुपर स्टार सूर्या के साथ नज़र आने लगीं. शूटिंग पर थोड़ा वक़्त बिताने के बाद वह भी सूर्या की फैन हो गईं. उन्होंने कहा कि सूर्या बहुत ही नेक दिल इंसान हैं और उनके साथ वक़्त बिताकर पता चला कि फैंस उन्हें भगवान की तरह क्यों पूजते हैं. वेल मलाइका, वैसे तो आपने इस इंडस्ट्री में काम करने वाले स्टारों की आदत के अनुसार यह कह दिया कि सूर्या के फैंस उन्हें उनकी नेकदिली की वजह से पूजते हैं, लेकिन यह नहीं बताया कि सूर्या: द सुपर स्टार को वक़्त कब मिलता है कि वह फैंस के बीच जाएं और अपनी खास छवि बनाएं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

उत्तर प्रदेश
उत्तराखंड

दिल्ली, 27 दिसंबर 2010-02 जनवरी 2011

www.chauthiduniya.com

उत्तर प्रदेश का सियासी महाभारत

उमा बनेंगी सारथी

सभी फोटो- *प्रभात पाण्डेय*

विजय यादव

उत्तर प्रदेश के चुनावी महाभारत में भाजपा को उमा भारती के रूप में सारथी कृष्ण तो मिल गए, लेकिन अभी उसे पांडवों को एकजुट करना होगा. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पार्टी को अर्जुन की तलाश करनी होगी, अन्यथा सत्ता रूपी मछली की आंख वेधने का सपना पूरा नहीं हो सकेगा. पहले प्रदेश भाजपा के पांडव कल्याण सिंह, कलराज मिश्र, लालजी टंडन, ओम प्रकाश सिंह और राजनाथ सिंह हुआ करते थे, लेकिन अब ये बिखर चुके हैं. कल्याण भाजपा के साथ नहीं हैं. राजनाथ सिंह राष्ट्रीय राजनीति में जम चुके हैं. कलराज और लालजी टंडन भी ख़ुद को राष्ट्रीय नेता ही मानते हैं. ऐसे में उमा का साथ कौन देगा, कौन उनकी बात मानेगा, यह विचारणीय है. इसमें कोई शक नहीं कि उमा सारथी की भूमिका अच्छी तरह से निभाएंगी, लेकिन युद्ध जीतने के लिए योद्धा भी ज़रूरी हैं, जो फिलहाल उत्तर प्रदेश में पार्टी के पास दिखाई नहीं देते. पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बाद उत्तर प्रदेश में भाजपा के पास अब कोई ऐसा चेहरा नहीं है, जो उसे सत्ता में वापस ला सके. वैसे उत्तर प्रदेश में भाजपा के पास बड़े नामों एवं चेहरों की कमी नहीं है. मुरली मनोहर जोशी, मुख्तार अब्बास नकवी, विनय कटियार, मेनका गांधी एवं वरुण गांधी उत्तर प्रदेश से ही हैं, लेकिन इनमें वरुण को छोड़कर कोई आक्रामक नहीं दिखता. अब भाजपा को यह तय करना होगा कि वह किसे अर्जुन के रूप में उमा के साथ उतारेगी.

चुनावी महाभारत में भाजपा के सामने बहुजन समाज पार्टी होगी, जो कार्यकर्ता आधारित है. संगठनात्मक स्तर पर आज की तारीख में भाजपा किसी भी तरह से बसपा के सामने नहीं टिकती. यही हाल सपा का भी है. उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का संगठन काफ़ी मजबूत है. कांग्रेस इस मामले में भाजपा के साथ खड़ी नज़र आती है. संगठनात्मक तौर पर कांग्रेस भी काफ़ी कमजोर हो चुकी है. भाजपा पहले कभी संगठनात्मक तौर पर मजबूत हुआ करती थी. पार्टी के पास कार्यकर्ताओं का हुजूम होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है. भाजपा कार्यकर्ता आधारित नहीं, बल्कि नेता प्रधान पार्टी बनकर रह गई है. ऐसे में चुनाव के दौरान बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की टोली खड़ा करना भी भाजपा के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा. इन हालात से भाजपा का केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व अनजान नहीं है. केंद्रीय नेतृत्व की पहल पर ही उत्तर प्रदेश में भाजपा को पुनर्जीवित करने का अभियान शुरू किया जा रहा है. इसके लिए कोर ग्रुप गठित हुआ है. वर्ष 2011 की शुरुआत के साथ ही मकर संक्रांति के दिन से भाजपा अपने इस अभियान का श्रीगणेश करेगी. गांवों में पैठ बनाने के लिए भाजपा के नेता ग्रामीण इलाक़ों में रात्रि विश्राम भी करेंगे, लेकिन इतने भर से बात बनने वाली नहीं है. नाराज़ कार्यकर्ताओं को संगठन के साथ पुनः जोड़ने की मुहिम सफ़ल बनानी होगी, अन्यथा उमा भारती के लिए मुश्किलें और भी बढ़ेंगी. भाजपा कार्यकर्ताओं के सामने एक सवाल यह भी है कि क्या उमा भारती अपने बड़े भाई कल्याण सिंह के ख़िलाफ़ मुखर हो सकेंगी. उमा वाकई ऐसा कर पाएंगी, यह कह पाना बहुत मुश्किल है. वजह पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव हैं, जब कल्याण भाजपा में नहीं थे और उमा भाजपा की स्टार प्रचारक हुआ करती थीं. उस दौरान भी उमा ने कल्याण के ख़िलाफ़ बोलने से परहेज किया. अब कल्याण मुलायम सिंह यादव का साथ छोड़ चुके हैं. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका अपना असर है, जहां भाजपा को अपनी पैठ बनानी है. ऐसे में उमा को कल्याण सिंह के ख़िलाफ़ आक्रामक होना पड़ेगा, यह वक्त की मजबूरी भी होगी. कल्याण के भाजपा से अलग होने के बाद से पार्टी का मानना है कि वह कम से कम पांच लोकसभा सीटों और 31 विधानसभा क्षेत्रों में कमजोर हुई है. इन क्षेत्रों में लोध मतदाताओं का प्रतिशत अधिक है. एटा, बुलंदशहर, अलीगढ़, फर्रुखाबाद एवं पीलीभीत लोकसभा सीट पर कल्याण सिंह की बिरादरी नतीजे को प्रभावित करती है. ऐसे में अगर उमा भारती भाजपा में आएंगी तो भाजपा को इसका लाभ मिलेगा, पार्टी की तात्कालिक सोच यही है.

उमा भारती की वाया उत्तर प्रदेश भाजपा में वापसी को क्षेत्रीय क्षत्रप पचा नहीं पा रहे हैं. उमा को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष बनाए जाने की बात चल रही है. ऐसे में उन्हें उत्तर प्रदेश का प्रभार भी दिया जा सकता है. यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन उमा के उत्तर प्रदेश से ही चुनाव लड़ने की दशा में यहां के नेताओं को अपना वजूद ख़तरे में पड़ता दिखाई दे रहा है. यही वजह है कि वे उमा के भाजपा में आने पर खुलकर खुशी का इजहार नहीं कर रहे हैं और न ही गम जता पा रहे हैं. उमा भारती के आने से गैर भाजपाई दलों में खलबली ज़रूर है. विरोधी अभी से आरोप लगाने लगे हैं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा का मिशन 2012 सांप्रदायिकता को उभारने वाला होगा. हिंदू-मुस्लिम मतों का ध्रुवीकरण कराने के हर हथकंडे का इस्तेमाल होगा. गैर भाजपाई दलों के आरोप अनायास नहीं हैं. उमा भारती जिस राम मंदिर आंदोलन की देन हैं, वह हाईकोर्ट के ताजा निर्णय के बाद एक बार फिर से चर्चा में है. विवादित ढांचा ढहाए जाने के मामले में उमा भारती भी आरोपी हैं. इसका राजनीतिक लाभ उठाने से भाजपा तनिक भी परहेज नहीं करेगी. दिलचस्प बात यह है कि भड़काऊ भाषण देने की आदत के चलते ही उमा भारती राजनीति के शीर्ष पर पहुंचीं तो इसी वजह से उन्हें राजनीति में बुरे दिन भी देखने पड़ रहे हैं. मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रहते हुए उन्हें वर्ष 2004 में इस्तीफा देना पड़ा था. वजह कर्नाटक के हुबली शहर में क़रीब 15 साल पहले सांप्रदायिक तनाव फैलाने के आरोप में उमा के खिलाफ मुक़दमा कायम किया गया था. इस मामले में उन्हें अदालत के सामने पेश होना था. इसी के बाद उमा भारती का राजनीतिक ग्राफ नीचे आता गया और आज जबकि उनकी भाजपा में वापसी की बात हो रही है तो उन्हें अपना घर मध्य प्रदेश छोड़ने के लिए बाध्य किया जा रहा है.

आखिर क्या कारण है कि उमा भारती की मध्य प्रदेश में वापसी में उन्हीं के शिष्य रहे नेता ही रोड़े अटका रहे हैं. इसकी प्रमुख वजह उमा भारती का अक्खड़पन, उनकी तानाशाही है. भाजपा में रहते हुए उन्होंने जिस तरह से लालकृष्ण आडवाणी के ख़िलाफ़ तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया, वह किसी से छिपा नहीं है. मध्य प्रदेश के नेताओं की उमा के सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं होती थी. जिन बाबूलाल गौर ने उमा की चरण पादुका लेकर मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल की थी, वह भी आज अपनी इस नेता को नकारने लगे हैं. शिवराज सिंह चौहान को भी वह फूटी आंख नहीं सुहाती हैं. मध्य प्रदेश भाजपा के नेता डरते हैं कि अगर उमा भारती भाजपा में आएंगी तो वह फिर से पुराना रवैया अख्तियार करेंगी. उमा की इस ख्याति से उत्तर प्रदेश भाजपा के नेता अपरिचित नहीं हैं. मध्य प्रदेश भाजपा में अगर कई गुट हैं तो उत्तर प्रदेश इस मामले में उसका बड़ा भाई है. गुटबाज़ी ने ही उत्तर प्रदेश में भाजपा को कहीं का नहीं छोड़ा है. ऐसे में उत्तर प्रदेश के नेता और कार्यकर्ता उमा भारती का नेतृत्व कहां तक स्वीकार करेंगे, यह सोचने वाली बात है. इन सबके बीच एक सवाल अहम है कि क्या उत्तर प्रदेश में भाजपा के नेताओं का संगठन नाकारा हो चुका है. जो उमा भारती मध्य प्रदेश में अपना राजनीतिक अस्तित्व नहीं बचा सकीं, उनसे भाजपा उत्तर प्रदेश में किसी करिश्मे की उम्मीद कैसे कर सकती है. बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भी बैठे-बैठाए भाजपा ने एक मुद्दा थमा दिया है. देखना है कि चुनावी महाभारत में विरोधी दलों के चक्रव्यूह को उमा भारती कैसे तोड़ेंगी.

feedback@chauthiduniya.com

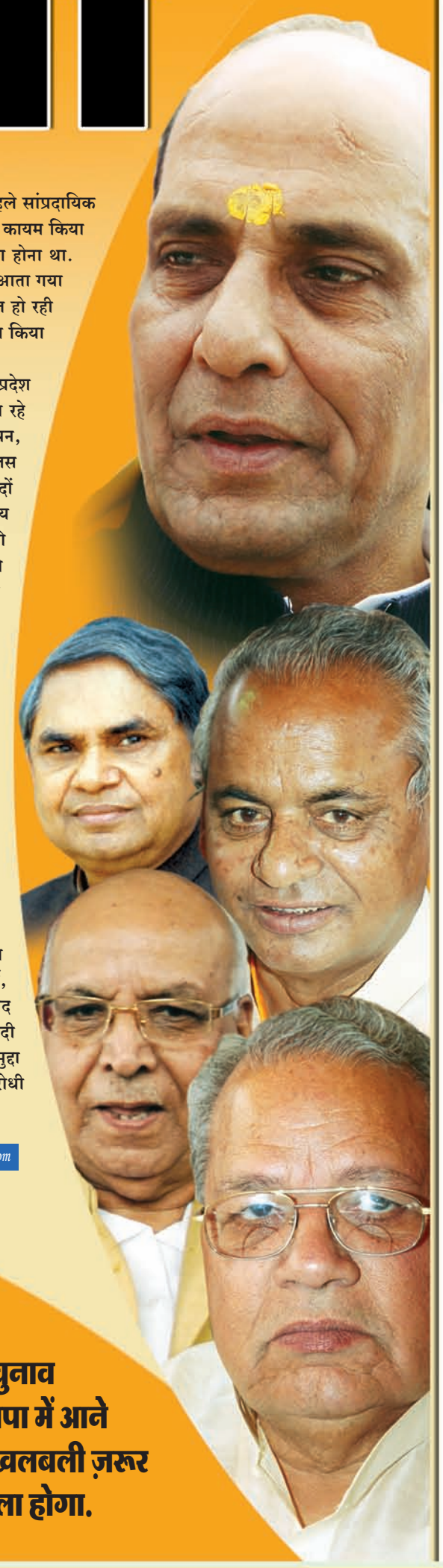

उमा भारती की वाया उत्तर प्रदेश भाजपा में वापसी को क्षेत्रीय क्षत्रप पचा नहीं पा रहे हैं. उमा को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष बनाए जाने की बात चल रही है. ऐसे में उन्हें उत्तर प्रदेश का प्रभार भी दिया जा सकता है. यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन उमा के उत्तर प्रदेश से ही चुनाव लड़ने की दशा में यहां के नेताओं को अपना वजूद ख़तरे में पड़ता दिखाई दे रहा है. यही वजह है कि वे उमा के भाजपा में आने पर खुलकर ख़ुशी का इज़हार नहीं कर रहे हैं और न ही ग़म जता पा रहे हैं. उमा भारती के आने से ग़ैर भाजपाई दलों में खलबली ज़रूर है. विरोधी अभी से आरोप लगाने लगे हैं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा का मिशन 2012 सांप्रदायिकता को उभारने वाला होगा.

चौथी दुनिया

कुंवर जितेंद्र प्रसाद उर्फ बाबा साहब ने देश की राजनीति में लंबी पारी खेली. उनके आकस्मिक निधन के बाद 2004 में उनके सुपुत्र कुंवर जितिन प्रसाद सांसद चुने गये.

संवासियों के प्रशिक्षण का सामान नष्ट हो चुका है. भवन का अधिकांश हिस्सा गिर चुका है. संस्था का कार्यालय बरामदे में चल रहा है.

सांसद-विधायक निधि में फंसा विकास

मैनपुरी जनपद से एक सांसद, पांच विधायक और एक एमएलसी हैं. जनता के यह सात नुमाइंदे सरकारी धन को साल भर में ख़र्च नहीं कर सके हैं. इस बात का पता इनकी निधियों के उपभोग का खाता देखने से चलता है. जनता के इन सात नुमाइंदों को मिलने वाली निधि का योग इतना है कि इस रक़म से जनपद के किसी भी एक कोने का कायाकल्प हो सकता है. मैनपुर से मुलायम सिंह यादव सांसद हैं. वहीं अशोक सिंह चौहान सदर विधानसभा सीट से विधायक हैं.

कालेश्वर सिंह

बिहार में विधायक निधि ख़त्म कर नीतीश कुमार एक बार फिर चर्चा में हैं. उत्तर प्रदेश में भाकपा को छोड़कर अन्य किसी दल ने इसका समर्थन नहीं किया. बात जहां करोड़ों रुपए की आती है तो सारे दल एक साथ दिखाई देते हैं. इन दलों के सांसद विधायक इस बात का जवाब देने से भागते हैं कि वह जनप्रतिनिधियों को मिलने वाली सरकारी निधि का कितना उपभोग करते हैं. इस निधि से किसे लाभान्वित किया जाता है. उत्तर प्रदेश में जन प्रतिनिधियों को मिलने वाली निधियां अपनों की तिजोरी भरने का साधनमात्र बनकर रह गई हैं. अधिकांश जनप्रतिनिधि तो इस निधि के धन को पूरी तरह से ख़र्च तक नहीं कर पाते हैं. उदाहरण के तौर पर मैनपुरी जनपद को देखते हैं, जहां से समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव सांसद हैं. मुलायम सिंह बड़े नेता हैं लेकिन सांसद निधि ख़र्च करने के मामले में वह भी कंजूस ही दिखाई देते हैं. विधायकों का भी कमोवेश यही हाल है.

मैनपुरी जनपद से एक सांसद, पांच विधायक और एक एमएलसी हैं. जनता के यह सात नुमाइंदे सरकारी धन को साल भर में ख़र्च नहीं कर सकें हैं. इस बात का पता इनकी निधियों के उपभोग का खाता देखने से चलता है. जनता के इन सात नुमाइंदों को मिलने वाली निधि का योग इतना है कि इस रक़म से जनपद के किसी भी एक कोने का कायाकल्प हो सकता है. लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है और यह असंभव भी है. यहां हर साल मानों एक जुमला याद आता है, जो समाज में वर्षों से चला आ रहा है कि अंधा बांटे रेवड़ी अपने-अपने को देय निधि का किस तरह से दुरुपयोग किया गया है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जनप्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्र से बाहर काम करा दिया है. साहब विधायक जी है. काम क्षेत्र से बाहर भी करा सकते हैं. अपने क्षेत्र में सारा विकास हो ही चुका है.

मैनपुर से मुलायम सिंह यादव सांसद हैं. वहीं अशोक सिंह चौहान सदर विधानसभा सीट से विधायक हैं. आलोक शाक्य भोगांव से विधायक हैं. संध्या कठेरिया किशनी से विधायक हैं. सोवरन सिंह यादव करहल से विधायक हैं जबकि घिरोर से ठाकुर जयवीर सिंह विधायक हैं जो बसपा सरकार में स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री भी हैं. एक एमएलसी चंद्रप्रताप सिंह यादव हैं. इन जनप्रतिनिधियों के बावजूद जनपद में लोग जीवन की बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं. प्रदेश में कोई भी सरकार आए, उसने विकास की कहानी अपने हिसाब से गढ़ी. हक़ीक़त यही है कि किसी भी सरकार ने विकास को सही मायने में धरातल पर नहीं आने दिया. आज़ादी के बाद जो विकास होना चाहिए था, वह अभी तक नहीं हो पाया है. जनता सरकार बनाती तो है लेकिन बाद में ख़ुद जनता का सरकार से कोई सरोकार नहीं रह जाता है. लोकतंत्र में जनता का हक़ सरकार बनाने तक ही है. इसके बाद सरकार जनता के लिए क्या करती है, यह सरकार पर निर्भर करता है. अभी तक जितनी भी सरकारें आईं, वह जनता का वाजिब हक़ नहीं दे सकी हैं.

जनपद के विकास के लिए जनप्रतिनिधियों को मिलने वाली सरकारी निधि जिन मदों में ख़र्च हो रही है, वह तर्कसंगत नहीं है. निधियों से होने वाले विकास के कार्य मानक के अनुरूप नहीं हैं. इससे बनने वाली सड़कें, सरकारी व अर्ध सरकारी भवनों का निर्माण, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि सभी कार्य भ्रष्टाचार का शिकार हैं. इन योजनाओं के लिए सांसद, विधायक निधि से दिए गए धन का सत्यापन किया जाए तो जनप्रतिनिधि भी भ्रष्टाचार में लिप्त नज़र आएंगे. सांसद को दो करोड़ रुपए सालाना और विधायक को सवा करोड़ रुपए सालाना मिलते हैं. इस सबका योग दस करोड़ रुपए से ज़्यादा है. जनपद के पांच विधायकों में एक मंत्री भी हैं. सरकार में बैठे मंत्री की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ अपने विधानसभा क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है बल्कि उसकी ज़िम्मेदारी पूरे ज़िले को विकास से जोड़ने की है. इस ज़िम्मेदारी से ठाकुर जयवीर सिंह मुंह चुरा रहे हैं. अगर वह चाहते तो सपा के प्रभाव वाले इलाक़ों में विकास कार्य कराकर वहां बहुजन समाज पार्टी का आधार मजबूत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया बल्कि सरकार में मंत्री बनकर सुविधाओं का लुत्फ़ उठाते रहे हैं.

किशनी की सपा विधायक संध्या कठेरिया ने अपनी पूरी निधि का ज़्यादातर हिस्सा शिक्षा और विद्युत पर ख़र्च किया है. विधायक ने ग्राम जिजई में विद्युतीकरण पर 5.306 लाख रुपए तथा शिक्षा के मद में 95 लाख रुपए दिए हैं. इसे देखकर लगता है कि मानों विधायक के क्षेत्र में पानी, सड़क जैसी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो गई हैं. हालांकि ज़मीनी हक़ीक़त कुछ और है. क्षेत्र में विभिन्न छोटी-छोटी योजनाएं जो विधायक निधि से पूरी हो सकती है, उनकी ओर विधायक का ध्यान नहीं है. क्षेत्र में ज़्यादातर गांवों के लिए संपर्क मार्ग नहीं है.

सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव ने भी पिछले वर्ष अपनी निधि का पूरा पैसा सड़कों में ख़र्च किया था. इस वर्ष वह अपनी निधि का पूरा पैसा विभिन्न मदों में ख़र्च नहीं कर पाए हैं. सांसद निधि में वर्ष 2010-2011 के लिए 90.537 लाख रुपए के प्रस्ताव स्वीकृत हुए हैं. इनमें 34.756 लाख रुपए अवशेष है. सांसद ने शिक्षा पर 38.00 लाख, सीसी सड़क पर 33.872 लाख, पानी पर 1.665 लाख तथा अपने संसदीय क्षेत्र जनपद इटावा के लिए भी 17.000 लाख रुपए दिए हैं. सांसद भी अपनी पूरी निधि वर्ष भर में ख़र्च नहीं कर पाए हैं.

जनपद की कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो जनता को बार-बार पिछड़ेपन की याद दिलाती हैं. जनपद के दो ब्लॉक गर्मी के सीजन में पानी के गंभीर संकट से जूझते हैं. इनमें सुल्तानगंज और बरनाहल ब्लॉक शामिल हैं. इन दोनों ब्लॉकों में पानी की समस्या के स्थाई समाधान के लिए किसी ने भी प्रयास नहीं किए. सपा सरकार में बनी सड़कों की मरम्मत के लिए दोबारा धन मुहैया नहीं हो पाया है जिससे विकास की गति और मंद हो गई है. भोगांव विधानसभा क्षेत्र के विधायक आलोक कुमार शाक्य ने तो अपनी 1.25 करोड़ रुपए की निधि में ज़्यादातर हिस्सा शिक्षा, विद्युत, सड़क, सोलर लाइट पर ख़र्च किया है. यह राशि क़रीब 89.524 लाख रुपए है जिसमें से 61.584 लाख रुपए के विकास कराए जा चुके हैं. व्यय धनराशि 4.117 लाख रुपए तथा अवशेष धनराशि 57.467 लाख रुपए है. जनपद के सुल्तानगंज ब्लॉक में पानी की भारी किल्लत है लेकिन विधायक ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है. पेयजल के बजाय उन्होंने विधायक निधि को अन्य मदों पर ही ख़र्च किया है. यह दर्शाता है कि पानी की समस्या पर क्षेत्रीय विधायक का ध्यान नहीं है. जबकि हर वर्ष गर्मी, जून के महीने में पानी की समस्या से जनता को जूझना पड़ता है. करहल के सपा विधायक सोवरन सिंह यादव ने भी अपनी निधि का धन पानी, सीसी सड़क, पुलिया, ट्रांसफार्मर, सोलर लाइट पर ख़र्च किया है. सोवरन सिंह पूरे वर्ष में निधि का आधे से थोड़ा अधिक हिस्सा ही ख़र्च कर पाए हैं. आधी निधि कब और किस मद में ख़र्च होगी, यह विधायक पता नहीं कब तय करेंगे. विधायक ने 126 इंडिया मार्का हैंडपंप पर 36.522 लाख रुपए, सीसी सड़क पर 21.89 लाख रुपए, माइनर पुलिया पर 3.550 लाख रुपए, ट्रांसफार्मर में 2.431 लाख, सोलर लाइट पर 5.590 लाख रुपए व्यय किया है. किशनी की सपा विधायक संध्या कठेरिया ने अपनी पूरी निधि का ज़्यादातर हिस्सा शिक्षा और विद्युत पर ख़र्च किया है. विधायक ने ग्राम जिजई में विद्युतीकरण पर 5.306 लाख रुपए तथा शिक्षा के मद में 95.000 लाख रुपए दिए हैं. इसे देखकर लगता है कि मानों विधायक के क्षेत्र में पानी, सड़क जैसी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो गई हैं. हालांकि ज़मीनी हक़ीक़त कुछ और है. क्षेत्र में विभिन्न छोटी-छोटी योजनाएं जो विधायक निधि से पूरी हो सकती हैं, उनकी ओर विधायक का ध्यान नहीं है. क्षेत्र में ज़्यादातर गांवों के लिए संपर्क मार्ग नहीं है.

भाजपा के मैनपुरी सदर से विधायक अशोक सिंह चौहान ने पानी, सीसी रोड, सोलर लाइट, शिक्षा, विकलांगों को उपकरण मदों में निधि का उपभोग किया है. विधायक अशोक सिंह ने 85.243 लाख रुपए पूरे वर्ष में ख़र्च किए हैं. इंडिया मार्का हैंडपंपों पर 1.920 लाख रुपए सीसी सड़क व नाली पर 75.201 लाख, सोलर लाइट पर 0.622 लाख, शिक्षा पर 5.500 लाख, विकलांग उपकरण पर 2.000 लाख रुपए ख़र्च किए गए हैं. घिरोर विधानसभा क्षेत्र से बसपा विधायक व मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने अपने क्षेत्र में 13.155 लाख रुपए ख़र्च किए हैं. इनका कुछ पैसा फिरोजाबाद जनपद के क्षेत्र में भी ख़र्च किया गया है. मंत्री ने सोलर लाइट पर 5.212 लाख, शिक्षा पर 2.500 लाख, यात्री प्रतीक्षालय पर 1.033 लाख, सड़क व पुलिया पर 4.410 लाख रुपए ख़र्च किया है. वर्तमान में मंत्री की निधि को देखकर लग रहा है कि उन्हें विकास के कार्यों में कोई दिलचस्पी नहीं है. फिरोजाबाद जनपद में इनकी निधि से विकास के लिए 40.00 लाख रुपए दिए गए हैं. विधायक निधि की कुल 1.25 करोड़ राशि में मंत्री आधा भी हिस्सा ख़र्च नहीं कर पाए हैं. एमएलसी चंद्र प्रताप सिंह यादव ने जनपद में सोलर लाइट, हाईमास्ट लाइट और शिक्षा पर 43.150 लाख रुपए ख़र्च किया है. एमएलसी ने अन्य जनपदों की तुलना में मैनपुरी में अपनी निधि का सबसे ज़्यादा हिस्सा ख़र्च कर दिया है.

जनपद में सपा के तीन, बसपा व भाजपा का एक-एक विधायक है. इनमें सबसे ज़्यादा लेट लतीफ और जनता के विकास कार्यों में रुचि लेने वाले विधायक ठाकुर जयवीर सिंह हैं. जिन्होंने अपनी निधि का एक हिस्सा ही ख़र्च नहीं किया है. किशनी की विधायक संध्या कठेरिया ख़र्च करने में सबसे आगे रही हैं. उन्होंने अपनी निधि का एक करोड़ रुपए से अधिक विकास कार्य में लगाए हैं. वहीं दूसरे स्थान पर भाजपा के सदर विधायक अशोक सिंह चौहान हैं जिन्होंने अपनी निधि से 85.243 लाख रुपए ख़र्च किए हैं. ये आंकड़े यह दर्शाते हैं कि इन्होंने विकास के कार्यों के लिए काफी काम किया है जब कि सच्चाई इसके ठीक उलट ही है. सांसद और विधायक निधि के प्रति जनप्रतिनिधियों की यह बेरुख़ी दर्शाती है कि इन माननीयों की दिलचस्पी विकास के प्रति नहीं है. मतदाताओं को विकास के लुभावने सपने दिखाने में माहिर ये नेता चाहें तो अपनी निधियों से ही संपूर्ण ज़िले का चहुंमुखी विकास करा सकते हैं लेकिन अगर ऐसा हो गया तो फिर उनकी नेतागीरी कैसे चमकेगी, शायद यही सोचकर सांसद-विधायक जनता को विकास से दूर रख रहे हैं.

feedback@chauthiduniya.com

नोट पर राजनीति, असर यूपी-बिहार पर

शत्रुंजय सिंह रैकवार

नेपाल में राजशाही का अंतिम चिन्ह भी समाप्त होने वाला है. नेपाल की मुद्राओं से पूर्व नरेश ज्ञानेंद्र की तस्वीर हटाने की घोषणा कर दी गई है. नेपाल की नई मुद्रा में 8848 मीटर ऊंचे माउंट एवरेस्ट की तस्वीर होगी. नेपाली मुद्रा से नरेश की तस्वीर हटाने के फ़ैसले के साथ ही नागरिकों में यह भय भी फैल गया है कि नेपाल आगे चलकर अपनी मुद्रा का अवमूल्यन भी कर सकता है. इस डर से नेपाली लोग भारतीय मुद्रा की जमाखोरी करने लगे हैं.

यहां सवाल महज नेपाल का नहीं है. नेपाल भारत का पड़ोसी राष्ट्र है. नेपाल की सीमाएं उत्तर प्रदेश और बिहार से सटी हैं. जाहिर है कि यहां होने वाला कोई भी घटनाक्रम भारत ख़ासतौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार को प्रभावित करेगा. नोट प्रकरण इसकी मिसाल है. नेपाली मुद्रा से नेपाल नरेश की फोटो हटाने के केंद्रीय बैंक के फ़ैसले के बाद वहां का आम आदमी ख़ासतौर पर व्यापारी वर्ग परेशान है. नतीजा नेपाल के एनसीसी बैंक, एवरेस्ट बैंक, ग्लोबल बैंक, कुमारी बैंक, राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक, सिद्धार्थ बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड और कृषि विकास बैंक समेत अन्य सभी बैंकिंग संस्थानों में नेपाली नोट जमा करने व उसे बदलने के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है. नेपाल सरकार ने नरेश की फोटो वाले नोटों को 13 अप्रैल, 2011 तक हरहाल में जमा करने का आदेश जारी कर रखा है. इसका नतीजा नेपाल से सटे उत्तर प्रदेश के ज़िलों से भारतीय नोटों की तस्करी के रूप में सामने आया है. सीमावर्ती इलाक़ों में भारतीय मुद्रा विनिमय का अनाधिकृत व्यापार शुरू हो गया है. इसकी एक वजह और भी बताई जा रही है, वह यह कि पिछले कुछ महीनों से नेपाल में भारतीय मुद्रा की उपलब्धता में कमी आई है. नोटों की तस्करी से जुड़े लोगों के मुताबिक़ नेपाल का क़रीब 60 प्रतिशत व्यापार भारत के साथ होता है. हाल के वर्षों में भारत से आयात बढ़ा है लेकिन निर्यात कम हुआ है. इस कारण से नेपाल में भारतीय मुद्रा का आना भी कम हो गया है. भारतीय रुपयों की इस कमी के बीच यह आशंका भी है कि नेपाल भारतीय मुद्रा के साथ अपनी विनिमय दर संशोधित कर सकता है. भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है जिसका दबाव नेपाली मुद्रा पर पड़ रहा है. इसे देखते हुए यह आशंका जाहिर की जा रही है कि नेपाल आगे चलकर अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर सकता है. इस वजह से नेपाली लोग भारतीय रुपए जमा कर रहे हैं. इंडियन करेंसी की जमाखोरी करने की होड़ का नतीजा है कि नेपालियों को भारतीय मुद्रा निर्धारित दर से चार से पांच प्रतिशत अधिक मूल्य चुकाकर ख़रीदनी पड़ रही है. नेपाल के नागरिक और व्यापारी उत्तर प्रदेश की सीमा में आकर यहां से बैंकों की एटीएम मशीनों से भारतीय रुपए निकाल रहे हैं. इस वजह से एटीएम मशीनें तुरंत खाली हो जा रही हैं. नेपालगंज में जो व्यापारी पहले हज़ार और पांच सौ के भारतीय नोट लेने में आनाकानी करते थे, अब वह खुशी-खुशी नोट ले रहे हैं. नेपालगंज में अधिकृत मनी एक्सचेंज काउंटर खुले हैं फिर भी वहां पर नेपाली मुद्रा को बदलने में निर्धारित दर से अधिक कमीशन लिया जा रहा है. नेपाल के एक व्यापारी के मुताबिक़ नेपाल के लोगों को इलाज, ख़रीदारी और अन्य वजहों से भारत आना जाना पड़ता है. उन्हें भारतीय मुद्रा की ज़रूरत होती है जिसकी नेपाल में पहले से ही कमी है. भारतीय रुपए जमा करने के पीछे एक वजह यह भी है. कारण चाहे जो भी हों लेकिन भारतीय मुद्रा की नेपाल में जमाखोरी भारत के हितों के ख़िलाफ़ है जिस ओर न तो केंद्र सरकार का ध्यान जा रहा है और न ही राज्य सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी कोई क़दम नहीं उठा रही है. भारतीय नोटों की जमाखोरी को केवल नेपाल के परिप्रेक्ष्य में देखना बहुत बड़ी राजनयिक और सुरक्षात्मक भूल होगी. वजह नेपाल में पाकिस्तानी खुफ़िया एजेंसी आईएसआई की गतिविधियां बढ़ी हैं. आईएसआई भारत में जाली नोट फैला कर देश की अर्थव्यवस्था को खोखला करने में लगी है. ऐसे में इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है कि भारतीय नोटों की जमाखोरी में आईएसआई का हाथ भी हो सकता है. अब फ़ैसला केंद्र व उत्तर प्रदेश सरकार को करना है कि वह तमाशबीन बनी रहेगी या फिर कोई कार्रवाई भी करेगी.

feedback@chauthiduniya.com

शासन की उदासी, भिक्षुक गृह को नहीं मिल रहे संवासी

फैले हुए हाथ आपको अंदर तक टटोल लेते हैं, आप के क़दम रुक जाते हैं, हाथ झोली में टटोलने को मजबूर हो जाते हैं. इन दर्दमंदों की अदा, इनकी बेजुबान निगाहों की फरियाद किसके जज्बात नहीं जगाती. इनका दर्द कौन बयां करे. हर चौक चौराहे पर हाथ फैलाये, गाड़ियों के शीशे खोलने की मिन्नतें करता दिख जाता है. छोटे-छोटे बच्चे हाथ फैलाए अपने मां बाप के लिये भीख मांगते दिख ही जाते हैं. इनके क़दम दौड़ते ही रहते हैं. जिंदा जज्बातों के लोग इनके हाथ पर कुछ न कुछ रख देते हैं और जो मुर्दा हैं वे इन्हें गालियां देते हैं और अपने रास्ते चलते बनते हैं. झिड़की और मार इनके साथ कपड़ों की तरह चिपके रहते हैं. जी हां हम भिखारियों की ही बात कर रहे हैं. सरकार ने बेगर्स एक्ट के तहत इन संवासियो की हालत सुधारने की ठानी. सन 1976 में इस एक्ट के तहत भिक्षुक गृह खोला गया. इन बेघरों को प्रशिक्षण देकर उनको रोजगार के लायक बनाने की बात कही गई. इलाहाबाद के शिवकुटी में भी एक भिक्षुक गृह खोला गया. इस गृह में संवासियों को लाकर उन्हें रोजगार संबंधी प्रशिक्षण दिया जाना था. प्रशिक्षण के अंर्तगत संवासियों को बेंत के सामान बनाने और सिलाई तथा होजरी और लकड़ी के काम का प्रशिक्षण देना था. इस के लिए चार ट्रेड निर्धारित किये गये थे. प्रशिक्षकों की नियुक्ति भी कर ली गई. यहां पर 200 संवासियों को प्रशिक्षण दिया जा सकता है. लेकिन हाल यह है कि ये संस्था तमाम योजनाओं और निर्णयों में कोसों दूर चली गई है. संवासियों के नाम पर अब यहां केवल धंधा है. यहां अब एक भी संवासी नहीं है. अधिकारियों का कहना है कि 2001 में पीडब्ल्यूडी विभाग ने इस भवन को जर्जर बताकर अनुपयोगी घोषित कर दिया था. जिसके बाद से यहां संवासियों का आना बंद कर दिया गया. अब यहां तैनात अधिकांश कर्मचारियों को समाज कल्याण विभाग के दूसरे कामों में लगा दिया गया हैं. संवासियों के प्रशिक्षण का सामान नष्ट हो चुका है. भवन का अधिकांश हिस्सा गिर चुका है. संस्था का कार्यालय बरामदे में चल रहा है. 200 संवासियों की प्रशिक्षण क्षमता वाला यह संस्थान अब ख़ुद असहाय पडा है. संवासियों के नाम पर अब यहां केवल फाइलें भरी जाती हैं. इस संस्था की सुध लेने वाला कोई अधिकारी नहीं हैं. निष्प्रयोज्य घोषित किये जाने के साल बाद भी समाज कल्याण विभाग भिक्षुक गृह के लिये दूसरा भवन नहीं खोज पाया. इस संबंध में समाज कल्याण अधिकारी का कहना हैं कि इस मामले में शासन स्तर से निर्णय लिया जाना है. शासन को रिपोर्ट भेजी जा चुकी है. कार्रवाई की प्रतीक्षा है. ज़िला समाज कल्याण विभाग अधिकारी अशोक दीक्षित का कहना है कि इस संबंध में निर्णय शासन को ही करना है. भिक्षुक गृह की अधीक्षिका स्पष्ट कहती हैं कि इस जर्जर भवन में हम संवासियों को कैसे रख सकते हैं, हमारी जान का ख़ुद भरोसा नहीं.

विशाल ओझा
feedback@chauthiduniya.com

सेना में भ्रष्टाचारी बख्शे नहीं जाएंगे : जनरल वीके सिंह

पासिंग आउट परेड का सबसे बड़ा सम्मान स्वोर्ड ऑफ ऑनर गजेंद्र कुमावत को प्रदान किया गया. जयदेव डांगी को गोल्ड मेडल, गौरव सिंह को ब्रॉन्ज, सचिन कपकटे व अरुण एस आनंद को टेक्निकल सिल्वर मेडल दिया गया.

राजकुमार शर्मा

देहरादून से भारतीय सैन्य अकादमी प्रांगण में पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए भारतीय थल सेना के अध्यक्ष जनरल वीके सिंह ने कहा कि सेना में भ्रष्टाचारी बख्शे नही जाएंगे. किसी क़ीमत पर सेना के मूल नैतिक मूल्यों से समझौता नहीं किया जाएगा. सेना की देश के प्रति प्रतिबद्धता का हवाला देते हुए जनरल सिंह ने कहा कि सेना में किसी को तथाकथित प्रोफेशनल होने की छूट नही दी जाएगी. लेकिन उन्होंने कहा कि सेना में बेहतर काम करने पर निश्चित रूप से बेहतर भविष्य होगा.

भारत-पाक संबंधों के सुधरने का संकेत देते हुए जनरल सिंह ने इस वर्ष 518 जेंटलमैन कैडेटों को कमीशन प्रदान किया. पड़ोसी देश पाकिस्तान के उच्च सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर सरफराज के इस समारोह में भाग लेने से भारत-पाक रिश्ते पर जमी बर्फ भी पिघलती दिखी. काफ़ी समय बाद पाक के सैन्य अधिकारी आईएमए की पीओपी में शामिल हुए. उन्होंने कहा भी कि उनकी मौजूदगी ख़ुद ही दोनों देशों के बीच सुधरे संबंधों का संकेत दे रही है.

इस बार पीओपी के परेड का नेतृत्व जेंटलमैन कैडेट भागीरथ समैय्याजी ने किया. पासिंग आउट परेड का सबसे बड़ा सम्मान स्वोर्ड ऑफ ऑनर गजेंद्र कुमावत को प्रदान किया गया. जयदेव डांगी को गोल्ड मेडल, गौरव सिंह को ब्रॉन्ज, सचिन कपकटे व अरुण एस आनंद को टेक्निकल सिल्वर मेडल दिया गया. केरेन कंपनी को चीफ आफ आर्मी स्टाफ बैनर से सम्मानित किया गया. आईएमए ने अब तक कुल 50475 कैडेटों को प्रशिक्षण प्रदान करने का गौरव हासिल किया है.

देहरादून की वादियों में एकाएक बढ़ी ठंढ़ में आयोजित पासिंग आउट परेड में कैडेटों के जोश व उत्साह की गर्मी ने सभी को रोमांचित कर दिया. हैलीकाप्टरों ने पुष्प वर्षा कर देश के होनहारों का स्वागत किया. इस अवसर पर कई होनहारों ने अपने पिता के नक्शे क़दम पर चल कर अपने पिता का सीना ऊंचा किया. इलाहाबाद के कर्नल शिव प्रसाद मौर्या को इस बात की खुशी और गौरव दोनों है कि उनका बड़ा बेटा सुशील कुमार मौर्या भारतीय सेना में कैप्टन है और दूसरा बेटा निखिल भी इस बार सेना में अफसर बन कर निकला. वे कहते हैं कि उनकी सारी मनोकामना पूरी हो गयी.

feedback@chauthiduniya.com

फिर पकड़े गए आतंकी

सेना के इस समारोह के पूर्व दो आतंकियों की गिरफ्तारी ने सैन्य अधिकारियों को सतर्क कर रखा था. पकड़े गए आतंकी गुलाब नबी के निशाने पर भारतीय थल सेना के प्रमुख जनरल वीके सिंह थे. शॉल बेचने के बहाने कुख्यात आतंकी नबी ने दून में अड्डा जमा रखा था.

इस आतंकी ने दून पहुंचने के बाद आईएमए की टोह कंबल व्यापारी बन कर ली थी. वह दो दिसंबर को ही अपने साथी तनवीर के साथ दून पहुंचा था. उसे हिजबुल मुजाहिदीन ने यह काम सौंपा था.

इसके साथ 30 कश्मीरियों को भी लगाया गया था. इसी ने 2006 में एसटीएफ पार्टी पर एके-47 से हमला कर तीन जवानों को मौत के घाट उतारा था. 2008 में भी सिकरीटॉप पर एसटीएफ की टुकड़ी पर हमला किया था, जिसमें दो जवान शहीद हुए थे. चार अन्य आतंकी घटनाओं में भी इसे शामिल बताया गया है.

सियासत के शहर में सन्नाटा

ज़रीफ़ मलिक आनंद

प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से लेकर जंग-ए-आज़ादी में बिस्मिल अशफाक-रोशन की साझी शहादत, साझी विरासत वाला शहर शाहजहांपुर आज न जाने क्यों राजनीतिक शून्यता का शिकार हो गया है. आज़ादी के बाद भी सेठ विशन चंद्र सेठ, प्रेम किशन खन्ना, जितेंद्र प्रसाद व सत्यपाल सिंह यादव जैसे कद्दावर नेता देश और प्रदेश की राजनीति में छाये रहे. अब मौजूदा हालात कुछ इस तरह बन गये हैं कि आरक्षण के भंवर में फंसा यह ज़िला सियासी तौर पर रस्म अदायगी तक सिमट कर रह गया है, ना पहले जैसी चर्चायें होती हैं ना सियासी कोठियों की धमक सुनाई देती है और ना ही समर्थकों में कोई जोश-ख़रोश दिखाई पड़ता है. सियासत जैसे कोई ग़ैर ज़रूरी चीज़ हो चुकी हो.

पहले सियासत न तो खाला का घर थी और न ही तवायफ का दुपट्टा जो किसी के आसुंओं से कभी ना भीगता हो. पहले सियासी ज़िंदगी कांटों भरे ताज की तरह थी. आवाम को चैन की नींद सुलाकर ख़ुद रतजगा करने का हुनर मालूम था नेताओं को. आधी धोती पहनकर गांधी ने चर्खे के सहारे नंगे भारत का तन ढकने की चिंता की थी. खाद्यान्न संकट के समय शास्त्री जी ने पूरे देश से सप्ताह में एक शाम उपवास रखने की अपील तक की थी. संत विनोबा भावे भूदान यज्ञ के सहारे ना जाने कितने देशवासियों के अन्न दाता बने. इसी देश में महात्मा, चाणक्य अपनी कुटिया में किसी आगंतुक से व्यक्तिगत वार्ता करते समय राजकोष के धन से जलने वाला दीपक तक बुझा देते थे, पर समय का चक्र कुछ इस तरह घूमा की सब कुछ उलट-पुलट हो गया. अब यहां कोई राधेश्याम इंकलाबी, मो. मियां जैसा नेता नहीं है जो बेरोजगारी, पानी, बिजली आदि समस्याओं के लिए शासन प्रशासन से लड़ सके और न ही सुरेंद्र विक्रम सिंह जैसा सांसद ही हैं जो ज़िले की समस्याओं को उजागर करके निवारण की दिशा में दैनिक अख़बारों के पत्र कालम का सहारा लेता हो. भ्रष्टाचार अब कलंक नहीं माना जाता. कलुशित चरित्र के लोग भी बकायदा इस राजनीति के बाज़ार में अपनी-अपनी दुकानों पर गद्दी नशीन होते हैं. राजनीति तो ऐसे लोगों से भरी पड़ी है.

आज़ादी के बाद से ही य्ये सियासी कोठी ज़िले की राजनीति में अहम किरदार निभाती रही है. कुंवर ज्योति प्रसाद विधान परिषद सदस्य रहे.

कुंवर ज्योति प्रसाद विधान परिषद सदस्य रहे. फिर उनके बेटे कुंवर जितेंद्र प्रसाद उर्फ बाबा साहब ने देश की राजनीति में लंबी पारी खेली. पांच बार सांसद रहे बाबा साहब को राजीव गांधी ने अपना सलाहकार नियुक्त किया था. उनके व्यक्तित्व का जादू इतना था कि बाबा साहब जो चाहते थे वही होता था.आम जनता को उनसे उम्मीदें थीं, इसलिए जनता भी उन्हें अपना रहबर समझती थी. जाति-धर्म की तिकड़में और टुच्चे भ्रष्टाचार की तो कभी कोई चर्चा नहीं होती थी.

फिर उनके बेटे कुंवर जितेंद्र प्रसाद उर्फ बाबा साहब ने देश की राजनीति में लंबी पारी खेली. पांच बार सांसद रहे बाबा साहब को राजीव गांधी ने अपना सलाहकार नियुक्त किया था. उनके व्यक्तित्व का जादू इतना था कि बाबा साहब जो चाहते थे वही होता था. आम जनता को उनसे उम्मीदें थीं, इसलिए जनता भी उन्हें अपना रहबर समझती थी. जाति-धर्म की तिकड़में और टुच्चे भ्रष्टाचार की तो कभी कोई चर्चा नहीं होती थी. बाबा के आकस्मिक निधन के बाद 2004 में उनके सुपुत्र कुंअर जितिन प्रसाद सांसद चुने गये. दूसरी बार 2009 के लोकसभा चुनाव में शाहजहांपुर सीट आरक्षित होने के साथ ही ज़िले के सारे राजनैतिक आंकड़े उलट-पुलट हो गये. जितिन प्रसाद को निकटवर्ती नवसृजित धोरहारा से लड़ना पड़ा जहां उन्हें जनता ने प्रचंड बहुमत से जिताया. आज वे केंद्रीय पेट्रोलियम राज्यमंत्री हैं. शाहजहांपुर में उनकी कोठी है, पुराना रसूख है, सियासी दख़लअंदाज़ी है. इसलिए वे जब तब कोठी पर आते जाते रहते हैं. लोकलाज में दरबार भी लगाते हैं, जनता की फरियादें भी सुनते हैं. कई कारणों से आज के दौर में कोठी और जितिन कांग्रेस के पर्यायवाची हैं, शेष दरबारी रिमोट से चलने वाले चीनी खिलौनों की तरह हैं. जब मालिक बटन दबाता है, तभी गुड़िया नाचती है वरना उसकी क्या औकात जो हिल डुल भी सके. इसी कोठी के एक हिस्से में बाबा साहब के जूनियर वारिस उनके भतीजे और सपा के रास्ते से बसपा में दाख़िल होने वाले दबंग नेता जीसी बाबा का अखाड़ा लगता है. जो भी हो जीसी साहब की धमक तो है ही. पारिवारिक पृष्ठभूमि और उनके जमींदाराना अंदाज़ की वजह से जनता की नज़र में बसपा में होते हुए भी पूरी तरह बसपाई संस्कृति में रचे बसे न हों लेकिन वह इस समय बसपा के एक दमदार नेता के रूप में पूरी तरह स्थापित तो हैं ही. ज़िला पंचायत अध्यक्ष के लिए हुए घमासान में इन्हीं के प्रयासों से आखिर संयुक्त विपक्ष को हथियार डालने पड़े और बसपा प्रत्याशी बहादुर लाल आज़ाद लगभग निर्विरोध ज़िला पंचायत अध्यक्ष चुन लिये गये.

बाबा साहब की कोठी के ठीक बगल में एक और कोठी है जिसमें दो बार सांसद रहे राममूर्ति सिंह वर्मा रहते हैं. हालांकि जाति बिरादरी की गणित के हिसाब से वे मजबूत नेता हैं, मगर ज़िले की सीट आरक्षित हो जाने के कारण अब उनका खेल जलालाबाद विधानसभा तक सिमट गया है. पिछला विधानसभा चुनाव भी वे हार गये. वहां बसपा के नीरज मौर्या विधायक हैं. पहले जैसी भीड़ भी अब वर्मा जी की मड़ैय्या पर नहीं दिखती.

एक और ज़मीनी नेता हुए हैं सत्यपाल सिंह यादव जिनका ज़िक्र किये बग़ैर इस ज़िले का राजनैतिक इतिहास कभी पूरा नहीं होगा. बाबूजी के नाम से मशहूर स्व. सत्यपाल ने छह बार तिलहर विधायकी जीती, तीन बार सासंद, उत्तर प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष और ज़िले के इतिहास में पहले केंद्रीय राज्यमंत्री रहे, गांव-ग़रीब और खेत-खलिहान के प्रबल पक्षधर रहे बाबू जी ज़िले की राजनीति में तीन दशक तक छाये रहे. वर्तमान में उनके सुपुत्र राजेश यादव तिलहर से विधायक हैं, जो मजबूती के साथ क्षेत्रीय जनता के काम कराते देखे जा रहे हैं. शहर में एक और कोठी भी है जिसे जापान बाबू की कोठी कहा जाता है. जापान बाबू चुनावी राजनीति के पुरोधा भले ही न रहे हों लेकिन यह तय है कि वे भाजपा के सर्वोच्च मठाधीश माने जाते हैं. भाजपा संगठन हो या फिर किसी प्रत्याशी का कोई चुनाव, अंतिम सिग्नल इसी एंटीना से मिलता है. प्रांतीय राजनीति में ज़िले में छह विधायक हैं जिनमें एक अवधेश वर्मा जो प्रदेश सरकार में राज्यमंत्री भी हैं. निगोही क्षेत्र से रोशन लाल वर्मा विधायक हैं. इन दोनों के अपने-अपने निजी डिग्री और इंटर कॉलेज भी हैं. जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्रों में काम भी ख़ूब कराया है. पुवायां सुरक्षित सीट से धीरेंद्र प्रसाद उप चुनाव में बसपा से जीते हैं लेकिन अभी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कर पाया है जो उनकी छवि को निखारता हो.

इस शहर में एक राजभवन भी है. जिसमें भाजपा के चर्चित नेता सुरेश कुमार खन्ना अपना दरबार लगाते हैं. शहर विधायक श्री खन्ना राज्य सरकार में दो बार मंत्री भी रहे हैं और लगातार छठी बार विधायक चुने गये हैं. दमदार नेता हैं. जनहित के कई उल्लेखनीय काम उनके नाम दर्ज़ हैं. तमाम बहस और सामाजिक सरोकारों से जुड़े तीखे सवालों के बीच से निकलकर जो कुछ निकलकर आता है, उससे लगता है कि राजनीति और राजनेताओं से आवाम जनता का विश्वास धीरे-धीरे ख़त्म होता जा रहा है. राजनीति अब समाज सेवा न होकर कार्पोरेट व्यवसाय बन गई है. जहां कम लागत पर अच्छा कमाया जा सकता है. जनता और देश अब इन सफ़ेद पोशों के लिए कोई प्राथमिकता नहीं रखते.

फोटो-प्रभात पाण्डेय

feedback@chauthiduniya.com

बिचौलिए और व्यापारी बनारसी साड़ी का कारोबर करके लखपति-करोड़पति बन गए लेकिन कारीगर की आर्थिक हालत दिन-प्रतिदिन ख़स्ता होती गई.

सियासी चक्की में पिसती हाथ की कारीगरी

बनारस और उसके आस-पास के इलाक़े के पांच से छह लाख लोग बनारसी साड़ी के कारोबार से जुड़े हैं. इस उद्योग से जुड़े अनिल कुमार के मुताबिक़ बनारसी साड़ी बनाने वाले आधे से अधिक कारीगर काम धंधे की तलाश में पलायन कर गए हैं. जो घर के मोह में बनारस नहीं छोड़ सके, वह ग़रीबी में जीवन यापन करने को मजबूर हैं. वजह भारतीय नारी के सुहाग और श्रृंगार का प्रतीक बनारसी साड़ी का उद्योग संकट के दौर से गुज़र रहा है. इस काम में लगे हज़ारों कारीगरों की माली हालत काफ़ी ख़राब हो चली है.

उत्तर प्रदेश की सियासी चक्की में हाथ की कारीगरी बुरी तरह पिस रही है. सत्तासीन बहुजन समाज पार्टी और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी, यह दोनों ही ज़ुबानी जमा ख़र्च से काम चला रहे हैं. बुनकरों की बदहाली का मसला ही लीजिए. सूबे में चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या सपा या भाजपा का या फिर बसपा का, बुनकर अपनी हालत पर पहले भी रोता रहा है और आज भी आत्महत्या करने पर मजबूर है. सत्ता परिवर्तन के साथ दलों की भूमिका बदल जाती है. जैसे वर्तमान राजनीतिक स्थिति में सपा विपक्ष में है, तो उसने बुनकरों की बदहाली के लिए वर्तमान बसपा सरकार को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया है. बसपा भला क्यों चुप रहती, हाथी पर सवार नेताओं ने भी पलटवार करते हुए सपा को ही कठघरे में खड़ा कर दिया है. बसपा अब यह जानना चाहती है कि सपा ने अपने शासनकाल में बुनकरों के लिए क्या किया? सूती और सिंथेटिक धागों की क़ीमत अगर बढ़ रही है तो उसके लिए राज्य सरकार को किस आधार पर जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? इस तरह बसपा ने केंद्र की कांग्रेस सरकार को भी घेरे में ले लिया. इस सियासी रार के बीच बुनकर महज मूकदर्शक है, उसे कुछ भी बोलने और जानने की इजाजत नहीं है. नेता आपस में ही वाकयुद्ध करके उसके मसले को सुलझाने में लगे हैं. यही वर्षों से होता आया है और आगे भी जारी रहेगा. घर में शादी हो और बनारस की साड़ी व फिरोजाबाद की चूड़ियों की ख़रीदारी न हो, यह हो नहीं सकता. इनके बगैर दुल्हन का श्रृंगार कैसे होगा. इनकी ख़रीदारी के नाम से ही महिलाओं की आंखों में चमक आ जाती है. यह तस्वीर का ख़ूबसूरत पहलू है जहां केवल खुशियां ही खुशियां दिखाई देती हैं. इसका एक दूसरा पहलू भी है. इन साड़ियों व चूड़ियों की चमक के पीछे उन कारीगरों की मुफलिसी छिपी रहती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी इस धंधे से जुड़े हैं. ये कारीगर साड़ी के साथ खुशियों की सौगात भी बुनते हैं लेकिन इनके चेहरे पर दुखों का ताना-बाना और आंखों में त्रासदी की दास्तां भरी पड़ी है. यह दोनों ही उद्योग उत्तर प्रदेश की पहचान और परंपरा दोनों से ही जुड़े हैं जो समय के साथ समाप्त होते जा रहे हैं. इस आर्थिक मार से भदोही के कालीन उद्योग से जुड़े बुनकर भी कराह रहे हैं. इन कारीगरों की उंगुलियों में जादू है. उनके बुने कालीन राष्ट्रपति भवन से लेकर प्रधानमंत्री निवास और देश-विदेश की नामचीन हस्तियों के घरों की शोभा बढ़ाते हैं लेकिन ख़ुद उनके घरों में टाट का पर्दा लटकता है. बनारस और उसके आस-पास के इलाक़े के पांच से छह लाख लोग बनारसी साड़ी के कारोबार से जुड़े हैं. इस उद्योग से जुड़े अनिल कुमार के मुताबिक़ बनारसी साड़ी बनाने वाले आधे से अधिक कारीगर काम धंधे की तलाश में पलायन कर गए हैं. जो घर के मोह में बनारस नहीं छोड़ सके, वह ग़रीबी में जीवन यापन करने को मजबूर हैं. वजह भारतीय नारी के सुहाग और श्रृंगार का प्रतीक बनारसी साड़ी का उद्योग संकट के दौर से गुजर रहा है. इस काम में लगे हज़ारों कारीगरों की माली हालत काफ़ी ख़राब हो चली है. बनारसी साड़ी उद्योग पर मंडरा रहे इस संकट का प्रमुख कारण सूरत और मऊ में बनने वाली सस्ती व सिंथेटिक और पॉलीस्टर की साड़ियां हैं. इस उद्योग में बिचौलियों की गहरी पैठ भी कारीगरों की दुर्दशा का एक अहम पहलू है. बिचौलिए और व्यापारी बनारसी साड़ी का कारोबर करके लखपति-करोड़पति बन गए लेकिन कारीगर की आर्थिक हालत दिन-प्रतिदिन ख़स्ता होती गई. बनारस के इन बुनकरों के माली हालात ख़राब होने की वजह से उनके परिवार की शैक्षिक व सामाजिक स्थिति में भी कोई सुधार नहीं हो सका. रोज़ी-रोटी की समस्या से परेशान बुनकर रिक्शा चलाने, होटल ढाबों में काम करने और फेरी लगाने को मजबूर हैं. जिन हाथों की उंगुलियां कभी सुहागिनों को सजाने वाली रेशमी साड़ियां बुनती थीं, वह आज कप-प्लेट धोने को मजबूर हैं. बुनकरों के हालात सुधारने के लिए सरकार तक फ़रियाद भी पहुंचाई गई. जैसे सरकारी रिवाज़ है, इनके मामले में ठीक वैसा ही हुआ. सरकारी अमले ने बुनकरों को समय-समय पर आश्वासनों की पोटली थमाने से कभी परहेज नहीं किया लेकिन इनका जीवन स्तर सुधारने, उन्हें बैंक से क़र्ज़ आदि की व्यवस्था करने, बनाए गए माल की बिक्री के साधन उपलब्ध कराने और बिचौलियों को इस धंधे से बाहर का रास्ता दिखाने जैसे ज़मीनी क़दम उठाने से हमेशा ही परहेज किया गया. सरकारी उपेक्षा का ही नतीजा है कि ये बुनकर महाजनों और स्थानीय गद्दीदारों के शोषण का शिकार होते हैं. इनके ख़ुद के पास इतना पैसा नहीं होता कि वह कच्चा माल ख़रीद कर उससे साड़ी तैयार कर सकें. ऐसे में बुनकर इन महाजनों से कच्चा माल लेकर साड़ी तैयार करते हैं और फिर उसे गद्दीदारों को सौंप देते हैं. इसके एवज में उनके हाथ में बहुत ही मामूली रक़म आती है, जिससे उनका ख़ुद का गुज़ारा चल पाना मुश्किल होता है. अगर बुनकर किसी तरह जुगाड़ करके कच्चे माल का इंतजाम कर भी लेते हैं तो साड़ी तैयार होने के बाद उनके सामने उसे बेचने की दिक्कत होती है. मार्केट में गद्दीदारों का वर्चस्व होता है. थकहार कर बुनकर साड़ी सस्ते दाम पर गद्दीदार को ही सौंप देते हैं. इस वजह से उनकी माली हालत में सुधार न पहले हुआ था और न अब हो रहा है. बुनकर मोहम्मद सलीम के अनुसार उनके घरों के बच्चे, बूढ़े और महिलाएं तक इस काम में लगी रहती हैं, लेकिन फिर भी उनके हिस्से में भरपेट खाना नहीं आता है. बैंकों से उनके लिए ऋण की व्यवस्था भी नहीं है. सरकारी मदद का लाभ कुछ गिने-चुने बुनकर ही उठा रहे हैं. हज़ारों बुनकर बिजली के बकाया भुगतान की समस्या से भी परेशान हैं. साड़ी के एक सिरे से दूसरे सिरे का अंत तो उन्हें नज़र आता है लेकिन उन्हें अपनी दुश्वारियों का अंत होता दिखाई नहीं देता है.

बुनकरों की समस्या का समाधान तो नहीं हुआ, लेकिन इसे लेकर सियासत चमकाने का काम ज़रूर हो रहा है. अगर यह कहा जाए कि बुनकरों के मसले को लेकर राज्य सरकार और सपा के बीच शब्दों के बाण चल रहे हैं तो ग़लत न होगा. इन दोनों ही दलों में इस बात की होड़ मची है कि कौन बुनकरों का सबसे बड़ा हितैषी है. बुनकरों के मसले पर बसपा को घेरने की पहल सपा ने की. विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष अहमद हसन के नेतृत्व में सपा नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मिलकर बुनकरों की समस्याएं उनके सामने रखीं. फिर क्या था, बसपा सरकार ने सपा को ही घेरे में ले लिया. पूछा कि सपा ने अपने शासनकाल में बुनकरों के लिए क्या किया? इसके जवाब में सपा ने अपनी सरकार में किए गए कार्यों का ब्यौरा पेश किया. इसके बाद बसपा सरकार ने फिर पलटवार किया और इस बार उसके निशाने पर केंद्र की कांग्रेस सरकार भी थी. या यूं कहें कि इसी बहाने मायावती सरकार ने सोनिया गांधी पर सीधे निशाना साधा. सरकार ने कहा कि उसके अधिकार में जो था, वह किया गया. बुनकरों के लिए अगर किसी ने कुछ नहीं किया तो वह केंद्र की सरकार है. सूती और सिंथेटिक धागों की क़ीमत बढ़ाने के लिए राज्य सरकार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है. यह सीधे तौर पर केंद्र का मसला है. धागों की क़ीमतों पर केंद्र का नियंत्रण रहता है. क़ीमतों में बढ़ोतरी होने की जानकारी के बावजूद केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय ने उचित क़दम नहीं उठाए. केंद्र के पाले में गेंद फेंकते हुए राज्य सरकार ने बुनकरों के अनुदान में 30 फ़ीसदी की बढ़ोतरी करने और धागे का दाम कम करने की मांग भी कर डाली है. इस मसले पर दबाव बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव की ओर से केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय को पत्र भी लिखा गया है. सपा व बसपा के बीच छिड़ी इस जंग में कांग्रेस बचाव की मुद्रा में है. वजह रूई का समर्थन मूल्य तय करना, कच्चे माल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने, धागे बेचने के लिए विक्रय केंद्र खोलने व बुनकरों को ब्याज रहित ऋण मुहैया कराने जैसे मसले केंद्र के पाले में ही आते हैं. संतकबीर नगर और मऊ में आर्थिक तंगी से त्रस्त आकर नौ बुनकरों के आत्महत्या करने का मसला उठाकर अहमद हसन पहले ही भयावह तस्वीर सबको दिखा चुके हैं.

बनारसी साड़ी के साथ फिरोजाबाद की चूड़ियों का ज़िक्र न आए, यह असंभव है. अफ़सोस, महिलाओं को सुहाग की निशानी देने वाले कारीगर ख़ुद मौत का शिकार होते जा रहे हैं. चूड़ी बनाने के दौरान यह कारीगर ख़तरनाक रासायनिक तत्वों के संपर्क में आते हैं जिससे वह गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं. उन्हें इतना पारिश्रमिक भी नहीं मिलता कि वह अपना बेहतर इलाज करा सकें. ज़िला अस्पतालों में भी इन कारीगरों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया नहीं हो पाती हैं. इस कार्य में हज़ारों महिलाएं व बच्चे भी लगे हैं. घातक बीमारियां इन्हें भी अपना निशाना बना रही है. चूड़ी उद्योग से जुड़े कारीगरों व मज़दूरों की हर सांस के साथ कांच के महीन कण उनके शरीर के अंदर घुसते जाते हैं जो अंतत: उन्हें मौत के मुंह में धकेल देता है. दूसरों को सुहाग की निशानी देने वाले इस उद्योग से जुड़े परिवारों में ऐसी महिलाओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है, जिनका ख़ुद का सुहाग उजड़ चुका है. उनके बच्चे कम उम्र में ही घातक बीमारियों से पीड़ित हैं. सरकारी योजनाएं इनके लिए बेमानी हैं. इनके मुरझाए चेहरे चूड़ियों की चमक के सामने छिप जाते हैं. बनारसी साड़ी के बुनकरों जैसी ही ख़राब हालात भदोही के कालीन उद्योग से जुड़े कारीगरों की भी है. भुखमरी, कर्ज़ और बदहाली से परेशान इन बुनकरों ने दूसरा रास्ता अख्तियार कर लिया है. आलम यह है कि कालीन बेल्ट में बुनकरों का अभाव हो गया है. यह इस उद्योग के लिए ख़तरनाक संकेत तो है लेकिन बुनकरों के सामने इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है. उन्हें इस उद्योग में रात-दिन खटने के बाद भी बदहाली का जीवन गुज़र बसर करना पड़ता है. ऐसे में अधिकांश बुनकर बड़े शहरों की ओर पलायन कर गए हैं. अगर वह ऐसा नहीं करते तो शायद उन्हें आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ता. बीते तीन-चार वर्षों में कई बुनकर तंगहाली की ज़िंदगी जीने के बजाय मौत को गले लगा चुके हैं. एक अनुमान के अनुसार क़रीब साठ हज़ार बुनकर अपना पुश्तैनी धंधा छोडक़र पलायन कर चुके हैं या फिर वह अब कोई दूसरा काम धंधा कर रहे हैं.

बुनकरों की घटती संख्या से चिंतित कालीन निर्माता केंद्र सरकार से गुहार तक लगा चुके हैं. भदोही का कालीन विश्व प्रसिद्ध है, इस उद्योग पर संकट से उत्तर प्रदेश के कारीगरों का हुनर और उनकी अपनी अलग पहचान खोने का ख़तरा न तो केंद्र और न ही राज्य सरकार को दिखाई देता है. कालीन निर्माता भारी मुनाफ़ा कमाते हैं लेकिन वह ख़ुद यह कोशिश नहीं करते कि मुनाफ़े का वाज़िब हिस्सा बुनकरों को भी मिल सके.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

फिरोजाबाद के चूड़ी बनाने वाले कारीगर लगातार मौत के शिकार होते जा रहे हैं. चूड़ी बनाने के दौरान यह कारीगर ख़तरनाक रासायनिक तत्वों के संपर्क में आते हैं, जिससे वह गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं. इस कार्य में हज़ारों महिलाएं व बच्चे भी लगे हैं. घातक बीमारियां इन्हें भी अपना निशाना बना रही है. चूड़ी उद्योग से जुड़े कारीगरों व मज़दूरों की हर सांस के साथ कांच के महीन कण उनके शरीर के अंदर घुसते जाते हैं, जो अंतत: उन्हें मौत के मुंह में धकेल देता है.

चौथी दुनिया

बिहार झारखंड

दिल्ली, 27 दिसंबर 2010-02 जनवरी 2011

www.chauthiduniya.com

फंड ख़त्म, विधायक नाराज़

नीतीश कुमार का विधायक फंड ख़त्म करने का फ़ैसला असल में उन्हें मिले प्रचंड बहुमत की वजह से ही संभव हुआ. चाहकर भी कोई विधायक अब तक इस फ़ैसले की मुख़ालफ़त नहीं कर रहा था. लेकिन चौथी दुनिया ने इस मुद्दे पर अलग-अलग पार्टियों के विधायकों से जब बात की तो उनके दिल का गुबार फूट पड़ा. पहली बार इन विधायकों ने खुलकर इस फ़ैसले पर सवाल खड़े किए. पेश है एक ख़ास पड़ताल.

सरोज सिंह

बिहार में इन दिनों विधायक फंड ख़त्म करने के नीतीश सरकार के फ़ैसले पर ज़ोरदार बहस छिड़ी है. भ्रष्टाचार ख़त्म करने के नाम पर लिया गया यह फ़ैसला बिहार और यहां के विधायकों की छवि को कितना निखारेगा, यह तो इसकी जगह बनने वाली वैकल्पिक योजना के साथ आने वाला समय तय करेगा. पर इतना ज़रूर है कि सरकार की इस नीति से विधायकों की नीयत पर सरकारी मुहर लग गई. सरकार ने माना कि विधायक फंड का सही उपयोग नहीं हो पा रहा है और विधायक बदनाम हो रहे हैं. सरकार की समझ है कि विधायक फंड ख़त्म होने से जनप्रतिनिधियों को क्षेत्र में काम करने में सुविधा होगी और भ्रष्टाचार पर काबू पाया जा सकेगा, लेकिन सरकार की यही समझ कुछ लोगों के गले नहीं उतर रही है. इनमें विपक्ष के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी से लेकर भाजपा विधायक अरुण कमार सिन्हा तक शामिल हैं. इन लोगों का मानना है कि भ्रष्टाचार का हवाला देकर इस योजना को बंद करना ठीक नहीं है. इससे ईमानदार विधायकों की भावनाओं को ठेस पहुंची है. जदयू सांसद उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि किसी संस्था या योजना को यह कहकर बंद नहीं किया जा सकता कि वहां भ्रष्टाचार है. ऐसे में तो सभी थानों एवं अस्पतालों को सबसे पहले बंद कर देना चाहिए.

दूसरी पारी में सबसे बड़ा फ़ैसला लेने के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि मेरी इच्छा है कि राजनेताओं की साख न केवल बनी रहनी चाहिए, बल्कि बढ़नी भी चाहिए. उन्होंने कहा कि इस फंड के ख़त्म होने के बाद सरकार ऐसी समेकित योजना बनाएगी, जिससे राज्य के किसी क्षेत्र में विकास में बाधा उत्पन्न न हो. नीतीश कुमार ने जहां अपनी बात ख़त्म की, सवाल वहीं से शुरू हो जाते हैं. अब तक सालाना 318 करोड़ रुपये विधायकों की अनुशंसा पर ख़र्च होते थे. क्या नई व्यवस्था में यह पैसा सही मायनों में गांव का चेहरा बदल सकेगा? क्या नई व्यवस्था को भ्रष्टाचार का इंफेक्शन नहीं होगा. क्या बिहार के विधायक इतने कमज़ोर हैं कि वे साल भर में मात्र एक करोड़ का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे. क्या इस राशि को लेकर वह इतने दबाव में थे कि इससे पल्ला झाड़ लेने में ही उन्होंने अपनी भलाई समझी. बहुत सारे विधायक जो अब मंत्री बन गए, उनकी ईमानदारी एवं दबाव झेलने की शक्ति को सरकार अब किस कसौटी पर कसेगी? वैसे ईमानदार एवं काम करने वाले विधायक जो पटना में लॉबिंग में समय बर्बाद न करके अपने क्षेत्र में जनता की समस्याओं को निपटाने में अपना समय बिताते हैं, वे क्या अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाने में ख़ुद को कमज़ोर महसूस नहीं करेंगे. क्या ऐसे विधायकों को छोटे-मोटे कामों के लिए भी हाकिमों के आगे-पीछे नहीं घूमना होगा. क्या जनप्रतिनिधियों को वित्तीय शक्ति से दूर करके लोकतंत्र को मज़बूत किया जा सकता है. इसके अलावा एक अहम सवाल यह है कि क्या मज़बूत मॉनीटरिंग व्यवस्था लागू करके इस फंड को बचाया नहीं जा सकता था. नेता विपक्ष अब्दुल बारी सिद्दीकी का कहना है कि अगर सरकार यह कहती है कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए यह फंड ख़त्म किया गया है तो मैं इससे इत्तेफ़ाक़ नहीं रखता हूं. मैं मानता हूं कि विधायकों पर दबाव पड़ते हैं, पर सही तरीके से काम करने वाले अपना काम कर लेते हैं. उन्होंने कहा कि फंड ख़त्म करने को लेकर सरकार के साथ कोई विचार विमर्श नहीं हुआ है. हां, इतना ज़रूर है कि सत्र के दौरान मैंने कहा था कि अगर सरकार इस योजना को ठीक ढंग से नहीं चला सकती तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है. सिद्दीकी कहते हैं कि अगर बिहार की एनडीए सरकार को लगता है कि उसने भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए कोई बड़ा क़दम उठाया है तो मेरी नीतीश कुमार एवं सुशील मोदी से गुज़ारिश होगी कि वे जल्द से जल्द तमाम एनडीए शासित राज्यों से विधायक फंड ख़त्म करने का अनुरोध करें. वरिष्ठ नेता पी के सिन्हा साफ़ कहते हैं कि नीतीश सरकार के इस फ़ैसले से तमाम विधायकों की ईमानदारी पर प्रश्नचिन्ह लग गया है. सांसद फंड से देश भर में काम हो रहा है. एक ओर इसे और बढ़ाने की मांग हो रही है तो दूसरी तरफ़ यहां दूसरी गंगा बहाने की कोशिश हो रही है. सिन्हा मानते हैं कि जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं एवं लोगों का दबाव झेलना पड़ता है, पर वे नेता किस काम के, जो सही फ़ैसला न ले सकें. उन्होंने कहा कि इस योजना को लागू करने की परिकल्पना यह थी कि विधायकों को अपने क्षेत्र में जनोपयोगी छोटे-मोटे काम कराने का अधिकार मिले, ताकि जनता के प्रति उनकी ज़िम्मेदारियों का निर्वाह हो सके, लेकिन फंड ख़त्म होने से विधायकों को दिक्कत आएगी और अफसरशाही हावी होगी. सरकारी महकमे कितने दूध के धुले हैं, इसे सभी जानते हैं. जदयू सांसद उपेंद्र कुशवाहा की राय है कि हाथ में घाव हो जाने से डॉक्टर हाथ ही नहीं काट देता है. हर जगह ईमानदार और बेईमान लोग होते हैं. कुछ लोगों के कारण सभी को बदनाम नहीं किया जा सकता. योजना में दिक्कत थी तो इस पर सही नियंत्रण करने के उपाय करने चाहिए थे. कुशवाहा का कहना है कि अब ईमानदार विधायकों को काम करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना
पड़ेगा. इस

मसले पर आनंद मोहन का कहना है कि यह सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए किया गया एकतरफ़ा फ़ैसला है. एमएलए फंड के समाप्त होने से किसी भी स्थानीय समस्या का निदान संभव नहीं हो सकेगा. इससे बेहतर होता कि विधानसभा भंग कर मुख्यमंत्री अकेले राज्य का शासन चलाते.

कांग्रेस के प्रवक्ता प्रेमचंद्र मिश्रा सरकार की नीयत पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं. वह कहते हैं कि सरकार ने जितनी जल्दबाजी में इस फंड को बंद किया, वह शक़ पैदा करता है. इससे यह संदेश गया कि नीतीश सरकार का पिछला कार्यकाल भ्रष्टाचार को नहीं रोक पाया. मिश्रा के मुताबिक़, यह सरकार केवल कहती है, पर करती कुछ नहीं. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कहते हैं कि स्पीडी ट्रायल करके 52 हज़ार अपराधियों को जेल में डाला गया. जब यहां जेलों की क्षमता ही 31 हज़ार कैदियों की है तो सरकार हमें यह बताए कि बाकी के क़ैदी भाजपा कार्यालय में हैं या जदयू कार्यालय में. उन्होंने कहा कि सरकार केवल भ्रष्टाचार रोकने का नाटक कर रही है. पहली बार चुनी गईं निर्दलीय विधायक ज्योति रश्मि का कहना है कि सरकार का यह क़दम अधिकारियों के आगे विधायकों को नतमस्तक करने के लिए है. सरकार नहीं चाहती कि जनता ने जिन प्रतिनिधियों को चुना है, वे आज़ादी से काम करें. गुस्से में भाजपा विधायक अरुण कुमार सिन्हा भी हैं. वह कहते हैं कि विधायक फंड ख़त्म करने के फ़ैसले से हम जैसे विधायक अपमानित महसूस कर रहे हैं. अगर सरकार को लगता है कि इस फंड को ख़त्म कर देने से बिहार का भला होगा तो मैं इस अपमान के घूंट को भी पी लूंगा. सिन्हा के मुताबिक़, पांच साल कोई कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ा रहता है, हम उसे विधायक व सांसद तो बना नहीं सकते, अगर विधायक निधि से उसके मोहल्ले में कोई स्कूल बन जाए तो फिर इसमें परेशानी क्यों है. वह कहते हैं कि अगर मन पवित्र रहेगा तो सब ठीक होगा, वरना फिर तो वही बात होगी कि अगर सरसों को ही भूत लग जाए तो फिर भूत कैसे उतरेगा. लेकिन इन सबसे उलट जदयू प्रवक्ता संजय सिंह कहते हैं कि विधायक फंड ख़त्म करने का ऐतिहासिक फ़ैसला लेकर नीतीश कुमार ने पूरे देश को एक नई राह दिखाई है. भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ जंग शुरू हो चुकी है और जिस संकल्प के साथ यह सरकार काम कर रही है, उससे बहुत जल्द बिहार देश का नंबर वन और विकसित राज्य बन जाएगा. नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार पहले सोचता है और फिर पूरा देश उसका अनुसरण करता है. ख़ैर, दोनों तरफ़ से तर्क दिए जा रहे हैं, पर सच्चाई यह है कि विधायक फंड का किस्सा बिहार में समाप्त हो गया है. अब इंतजार है उस योजना का, जो विधायकों के मान-सम्मान को तो बचाए ही, साथ ही भ्रष्टाचार की काली छाया से भी कोसों दूर हो, तभी इस बड़े फ़ैसले को जायज़ ठहराया जा सकेगा.

feedback@chauthiduniya.com

नेता बोले

किसी संस्था या योजना को यह कहकर बंद नहीं किया जा सकता कि वहां भ्रष्टाचार है. ऐसे में तो सभी थाने और अस्पताल सबसे पहले बंद कर देने चाहिए.

-उपेंद्र कुशवाहा

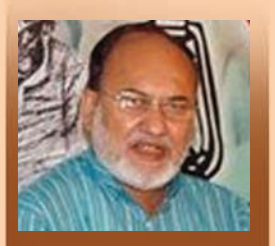

अगर सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए यह फंड ख़त्म किया गया है तो मैं इससे इत्तेफ़ाक़ नहीं रखता. विधायकों पर दबाव पड़ते हैं, पर सही काम करने वाले अपना काम कर लेते हैं.

-अब्दुल बारी सिद्दीकी

सांसद एवं विधायक फंड से देश भर में काम हो रहा है. इसे और बढ़ाने की मांग हो रही है और दूसरी तरफ़ यहां दूसरी गंगा बहाने की कोशिश हो रही है.

-पी के सिंहा

विधायक फंड ख़त्म करने का ऐतिहासिक फ़ैसला लेकर नीतीश कुमार ने पूरे देश को राह दिखाई है. बिहार में भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ जंग शुरू हो चुकी है.

-संजय सिंह

यह सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए किया गया एकतरफ़ा फ़ैसला है. इससे बेहतर होता कि विधानसभा भंग कर मुख्यमंत्री अकेले राज्य का शासन चलाते.

-आनंद मोहन

सरकार ने जितनी जल्दबाजी में इस फंड को बंद किया है, वह शक़ पैदा करता है. इससे यह संदेश गया कि नीतीश सरकार का पिछला कार्यकाल भ्रष्टाचार को नहीं रोक पाया.

-प्रेमचंद्र मिश्रा

सरकार का यह क़दम अधिकारियों के आगे विधायकों को नतमस्तक करने के लिए है. सरकार नहीं चाहती कि जनता ने जिन प्रतिनिधियों को चुना है, वे आज़ादी से काम करें.

-ज्योति रश्मि

विधायक फंड ख़त्म होने से हम जैसे विधायक अपमानित महसूस कर रहे हैं. अगर सरकार को लगता है कि इससे बिहार का भला होगा तो मैं इस अपमान के घूंट को भी पी लूंगा.

-अरुण कुमार सिंहा

चौथी दुनिया

उदयनाचार्य की जन्मस्थली को पर्यटन स्थल का दर्जा दिलाने की घोषणा की थी जो आज तक वास्तविकता में नहीं बदल सकी.

हेमंत सोरेन ने चौथी दुनिया से बात करते हुए यह विचार व्यक्त किए. उन्होंने कहा कि झारखंड खनिज संपदा के मामले में देश का सबसे धनी राज्य होने के बावजूद पिछड़ा हुआ है.

चौथी दुनिया

एक नज़र इधर भी

नाला बना जी का जंजाल

महावार नगर पंचायत के गंगा रोड की कहानी बड़ी अजीब हो चुकी है. इस सड़क की वर्ष 2001 में नगर पंचायत के द्वारा पीसीसी ढलाई की गयी थी. कनीय अभियंता द्वारा नाले को छोटा कर दिया गया. नतीजतन घरों का गंदा पानी सड़क पर ही बहने लगा. इसी नाले के जीर्णोद्धार के लिए वित्तीय वर्ष 2005–06 में लाखों रुपये निकासी की गयी, लेकिन नाले पर प्लास्टर चढ़ा कर राशि की बंदरबांट कर ली गयी. ख़राब निर्माण के कारण स्थिति इस यह है कि मोहल्ले के लोग सुबह–सुबह नाले की सफाई करने में जुट जाते हैं. ऐतिहासिक व पौराणिक महत्व रखने वाले इस बाज़ार में गंदगी के कारण अब ग्राहक भी नहीं आना चाहते हैं. इस सड़क की दयनीय स्थिति पर संजीत कुमार सोनी, शत्रुघ्न गुप्ता, संजीव जायसवाल, मोहन चौधरी, राजेंद्र जायसवाल, राशिद आलम, मणिभूषण, नवीन कुमार, अरविंद गुप्ता, प्रमोद वर्णवाल इत्यादि ने गहरी नाराज़गी जताई है. अब विधायक डॉ. अच्युतानंद ने इसके सुधार व महत्व को क़ायम रखने के लिए विधानसभा में भी इस मामले को उठाया है. *–अंजुम परवेज*

रेलवे ढाले पर दुर्घटना की आशंका

सहरसा में इट्हरा ढाले के समीप प्रधानमंत्री सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है. इस वजह से वाहनों की आवाजाही बढ़ गई है. रेलवे अधिकारियों की लापरवाही के कारण इट्हरा रेलवे ढाले पर फाटक नहीं होने से दुर्घटना की आशंका बनी रहती है. इसके बावजूद रेल प्रशासन ने अभी तक फाटक लगाने की कोई व्यवस्था नहीं की है. बिना फाटक के रेलवे ढाले से रेल से ट्रैक्टर की टक्कर से पिछले दिनों एक ड्राइवर की मौत भी हो चुकी है. जल्द से जल्द इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है. *–रोशन कुमार*

वोट के बदले मिल रहा है जॉब कार्ड

संग्रामपुर प्रखंड के किसी पंचायत में मनरेगा से काम तो कराया जा रहा है लेकिन मुखिया महोदय ने अपने समर्थक, मज़दूर व अपने साथ रहने वालों का ही जॉब कार्ड बनवाया है. मज़दूर पांच दिन काम करते हैं तो दस दिन का काम दिखाकर उनसे अंगूठे का निशान लिया जाता है. पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद मज़दूरों को काम देकर अपना वोट पक्का किया जा रहा है. ऐसे में बेचारे मज़दूर भी बिना काम किये कुछ पैसे पाकर फ़िलहाल ख़ुश तो हो रहे हैं लेकिन उनके भविष्य से सरेआम खिलवाड़ किया जा रहा है. हालांकि इन पैसों में बंदरबांट हो रही है. जागरूक ग्रामीण बताते हैं कि चुनाव में अपना वोट पक्का करने के लिए ही गरीब मज़दूरों को सब्ज़बाग़ दिखाकर उन्हें कुछ राशि देकर उनका कीमती वोट ले लिया जाएगा. *–अभय कुमार पांडेय*

जर्जर विद्यालय भवन

विकास के इस दौर में भी गया ज़िले के आमस प्रखंड के सुग्गी मध्य विद्यालय का भवन जर्जर है. विद्यालय में भवन तो है लेकिन पढ़ने वाले बच्चों की संख्या नहीं है. कारण इस जर्जर भवन में बच्चों को पढ़ाना ख़तरे से ख़ाली नहीं है. स्थानीय अभिभावकों की मांग है कि इस जर्जर भवन को तोड़कर नया भवन बनाया जाए. *–मिथिलेश कुमार*

हज़ारों बोरा गेहूं सड़ रहा है

भारतीय खाद्य निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक और डिपो प्रबंधक की मनमानी के कारण कटारी हिल स्थित एफसीआई के निकट रेलवे लाइन के बगल में साठ हज़ार बोरा गेहूं खुले आसमान में सड़ रहा है. इसका ठीकरा गोदाम प्रभारियों पर फोड़ा जा रहा है. जबकि गोदाम प्रभारियों ने गेहूं को खुले आसमान में रखवाने का विरोध किया था. अब जबकि इस गेहूं के ख़राब होने की ज़िम्मेदारी गोदाम प्रभारियों के माथे देकर उनके वेतन से राशि काटी जा रही है तो गोदाम प्रभारियों ने विद्रोह कर दिया है. *–सुदर्शन कुमार*

बुद्ध की सरकटी मूर्ति

गया ज़िले के गुरुआ प्रखंड में प्रसिद्ध बौद्ध स्थल गुनेरी स्थित है. यहां भगवान बुद्ध की सैकड़ों मूर्तियां जहां–तहां बिखरी पड़ी हैं. इन मूर्तियों में भगवान बुद्ध की सरकटी विशाल मूर्ति लोगों के आकर्षण का केंद्र है. स्थानीय लोगों ने सरकार से बुद्ध की इन प्राचीन मूर्तियों को संरक्षित करने और गुनेरी को बुद्ध पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की मांग की है. *–डॉ. प्रमोद कुमार वर्मा*

झारखंड जाने वाली सड़क दयनीय

जीटी रोड से गोपालपुर होकर झारखंड के चतरा ज़िला जाने वाली गोपालपुर–इटरांव सड़क की हालत ख़राब है. इसी सड़क से गैमन इंडिया समेत अनेक सड़क निर्माण कंपनियों के वाहन बड़ी संख्या में गुज़रते हैं. नियमतः इन कंपनियों को इस सड़क की मरम्मत करनी चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है. *–सुशील कुमार*

भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं : धूमल सिंह

एकमा प्रखंड मुख्यालय के किसान भवन में विधायक मनोरंजन सिंह उर्फ़ धूमल सिंह ने भ्रष्टाचार निवारण हेतु बैठक की. इसमें विधायक ने लोगों से एपीएल, बीपीएल, इंदिरा आवास इत्यादि योजनाओं की जानकारी ली एवं इसके लंबित निष्पादन के लिए अधिकारियों को निर्देश दिये. शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षा पदाधिकारी नियाज़ अहमद से जानकारी ली. कहा कि किसी भी महकमे में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा. इस मौके पर प्रखंड प्रमुख सिंह उर्फ़ भवानी मुन्ना ने भ्रष्टाचार निवारण के लिए विस्तृत रूप से सुझाव दिये. इस अवसर पर बीडीओ सीओ सहित जदयू के कई पदाधिकारी उपस्थित थे. *–प्रेम कुमार*

खगड़िया: परदेस से आ रहा है एड्स

राजेश सिन्हा

एड्स के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से भले ही हर साल लाखों करोड़ों रुपये पानी की तरह बहाए जा रहे हों, लेकिन बिहार का खगड़िया ज़िला एड्स पीड़ितों से पटता जा रहा है. विकास के मामले में बेहद पिछड़े इस ज़िले की हालत यह है कि अब ऐसे रोगियों की संख्या हज़ार से भी ऊपर पहुंच चुकी है. जानकारों का कहना है कि इस इलाक़े से पलायन का सिलसिला अगर थमा नहीं तो आने वाले सालों में यहां के लोग एड्स पीड़ित ज़िले के रूप में जाने जाएंगे. यह प्रमाणित हो चुका है कि एचआईवी पीड़ितों में अधिकांश परदेसी हैं. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक़ 2004 से अब तक 11712 लोगों की जांच के बाद एचआईवी पीड़ित लोगों की संख्या 518 पायी गई है. लेकिन अगर ग़ैरसरकारी आंकड़ों पर भरोसा करें तो अभी तक खगड़िया ज़िले के डेढ़ हज़ार से अधिक लोग एचआईवी से पीड़ित हो चुके हैं. सामाजिक बहिष्कार सहित अन्य कारणों से ऐसे लोग खुलकर न ही स्थानीय चिकित्सक के सामने आ पा रहे हैं और न ही समाज के सामने आने का प्रयास कर रहे हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि साल 2004 से एड्स के प्रति जागरूकता पैदा करने के नाम पर राशि ख़र्च करने में इज़ाफ़ा हुआ. जबकि 2004 में 42 लोगों की जांच करने के बाद एचआईवी पीड़ित रोगी महज़ एक पाया गया जबकि 2005 में 4187 लोगों की जांच के बाद 88 रोगियों की पहचान की गई. 2006 में महज़ 2162 रोगियों की जांच करने के पश्चात 53 लोग एचआईवी से ग्रसित पाए गए. 2007 में 2422 लोगों की जांच की गई और 73 रोगियों को चिह्नित किया गया. 2008 में 982 लोगों की जांच में 39 रोगियों की पहचान हुई. 2009 में 1220 लोगों की जांच के बाद 73 लोगों में एड्स के वायरस पाए गए. वहीं अभी तक 697 लोगों की जांच ही संभव हो सकी है. खगड़िया, चौथम, गोगरी, परबत्ता और अलौली में एचआईवी जांच के लिए केंद्र तो बनाए गए लेकिन चौथम एवं अलौली केंद्र बंद पड़े हैं. अगर सुव्यवस्थित तरीक़े से गांव कस्बे जाकर लोगों की जांच की जाए तो सरकारी नीति में बेहद ख़ामियां देखने को मिलेंगी. सरकारी स्तर से लोगों को रोज़गार देने का वादा तो किया जा रहा है लेकिन गांव–कस्बे में लोगों को रोज़गार नहीं मिल पाता है. नतीजतन लोग दिल्ली, पंजाब सहित अन्य राज्यों में पलायन कर जाते हैं. वहां असुरक्षित यौन संबंध क़ायम कर लेते हैं. जब उन्हें यह आभास होता है कि किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं तो तब काफ़ी देर हो चुकी होती है. फिर लोग अपने घर की तरफ़ रुख़ करते हैं. रुपये–पैसे लेकर घर लौटे हैं, लेकिन वे आते हैं तो इस बीमारी से ग्रसित हो चुके होते हैं. किसान विकास ट्रस्ट नामक स्वयंसेवी संस्था के चीफ़ मोबलाइज़र कृष्ण मोहन सिंह इस मसले पर खुलकर कहते हैं कि अभी भी समाज में सेक्स के मसले पर लोग खुलकर बात करने से परहेज़ करते हैं. समाज के 33 प्रतिशत लोग ही अभी तक साक्षर हो सके हैं. साक्षर लोगों को जागरूकता अभियान के ज़रिए जागरूक तो किया जा रहा है लेकिन निरक्षर लोग अभी भी असुरक्षित यौन संबंध से वाक़िफ़ नहीं हो पाए हैं. समाजसेवी नागेंद्र सिंह त्यागी के मुताबिक़ अगर इस तरह की भयानक बीमारी पर क़ाबू पाना है तो सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को उनकी ही भाषा में इस बीमारी के प्रति जागरूक करना होगा. स्थानीय संहीली के समाजसेवी अरविंद मोहन की दलील है कि ग्रामीण इलाक़े के मज़दूरों को स्थानीय स्तर पर ही रोज़गार उपलब्ध कराकर पलायन रोकना होगा. जब तक मज़दूरों का पलायन नहीं रुकेगा तब तक एचआईवी पर नियंत्रण पाना टेढ़ी खीर है. पीड़ितों का कहना था कि उन्हें कभी भी असुरक्षित यौन संबंध के बारे में पता ही नहीं चला था. वे इस बीमारी की चपेट में आ गए, समझ में नहीं आता. चौथम के एक एड्स पीड़ित दंपति ने बेबाक़ी के साथ कहा कि एड्स होने के बाद वह लोग पल–पल मौत का इंतज़ार कर रहे हैं. जबसे समाज के लोगों को यह जानकारी मिली है कि वह इससे पीड़ित है, समाज के लोगों ने उन्हें दरकिनार कर दिया है. समाज में किसी भी तरह का उत्सव होने पर इन्हें आमंत्रित नहीं किया जाता.

उत्तर बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति के ज़िला पर्यवेक्षक जितेंद्र कुमार लाल का कहना है कि समाज के लोगों को एड्स पीड़ितों के साथ प्यार भरा बर्ताव करना चाहिए. इनका बहिष्कार करना ग़लत है. ज़िंदगी के अंतिम पड़ाव पर खड़े इन लोगों के साथ निंदनीय व्यवहार इंसानियत के ख़िलाफ़ है.

feedback@chauthiduniya.com

नीतीश की जीत का राज़

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नालंदा कल्याणबिगहा स्थित पैतृक घर

पत्नी स्व. मंजू देवी की प्रतिमा

पिता स्व. कविराज रामलखन सिंह की प्रतिमा

नालंदा

विगत तीन विधानसभा चुनावों में नालंदा में नीतीश कुमार अजेय क्यों हैं? इसे लेकर तरह तरह की बहस हमेशा होती है. केवल जाति का हवाला देकर संतोष करने वाले भी नए सिरे से नालंदा के चुनावी गणित को समझने में लग गए हैं. विशेषज्ञों की मानें तो जीत के रहस्य को ज़िले के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में समझा जा सकता है. जाति एक बड़ा पक्ष है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता है पर उनकी विजयगाथा में इसके अलावा भी बहुत कुछ है. इस ज़िले के लोगों का नीतीश कुमार के साथ भावनात्मक लगाव उनकी ताक़त को दोगुना कर देता है. नीतीश कुमार की सादगी लोगों को प्रेरणा देती है. कल्याण बिगहा स्थित उनके मकान को देखकर लोग उनकी ईमानदारी का लोहा मान लेते हैं. जहां तक सामाजिक समीकरणों का सवाल है, नालंदा ज़िला मूल रूप से कुर्मी–कोइरी बहुल ज़िले के रूप में सूबे भर में चर्चित है. इन दोनों जातियों के इर्द–गिर्द ही ज़िले में जदयू की राजनीति घूमती रही है. इन्हीं दोनों जातियों की आबादी सर्वाधिक होने के कारण मतदाता भी सर्वाधिक हैं. वहीं जदयू के द्वारा विगत विधान सभा चुनावों में प्रत्याशियों के टिकट बंटवारे में भी इन दोनों जातियों को ही प्रधानता दी जाती रही है. मतदाता एवं प्रत्याशियों के एक ही जाति वर्ग से होने का फ़ायदा जदयू को मिलता आ रहा है. जहां चुनाव में जदयू को जातीय समीकरणों का फ़ायदा बराबर मिलता रहा है, वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विकास कार्य करने वाले मंत्री की छवि का भी फ़ायदा मिला है. नीतीश कुमार का गृह ज़िला होने के कारण नालंदा को जदयू का गढ़ माना जाता रहा है. इसी वजह से ज़िले के तमाम वर्ग के लोगों का भावनात्मक संबंध नीतीश कुमार एवं उनकी पार्टी से रहा है. चुनावों में भावनात्मक संबंधों का फैक्टर भी विशेषतौर पर देखा जाता रहा है. जहां नीतीश के साथ ज़िलेवासियों का भावनात्मक संबंध का चुनाव नतीजों पर ख़ासा असर देखा गया है वहीं उनके विकास के मुद्दे ने जीत में निर्णायक भूमिका निभाई है.

नालंदा में विपक्षी दलों की स्थिति पर नज़र डाली जाए तो ज़िले में विपक्ष की स्थिति विगत चुनावों से लगातार कमज़ोर होती दिख रही है. नालंदा के अलग–अलग क्षेत्रों में राजद एवं कम्यूनिस्टों का शुरूआती दौर में अच्छा प्रभाव देखा गया. ख़ासतौर से हिलसा इस्लामपुर बिहारशरीफ एवं राजगीर विधान सभा क्षेत्रों में इन दलों के प्रत्याशियों ने शुरूआती दौर में जीत भी दर्ज की. लेकिन समय बीतने के साथ साथ इन दलों का प्रभाव घटता गया. विगत चुनावों में इन दलों का प्रभाव घटकर शून्य के स्तर पर आ गया. जदयू की बढ़ती लोकप्रियता से इन दलों का प्रभाव स्वत: ही काफ़ी कम हो गया. वहीं विपक्षी दलों की क्षीण होती स्थिति के साथ– साथ इन दलों में योग्य एवं लोकप्रिय प्रत्याशियों की भी कमी होने लगी. बिहारशरीफ के पूर्व राजद विधायक पप्पू खान के हत्या के मामलो में फंस जाने के बाद ज़िला मुख्यालय बिहारशरीफ में राजद के संगठन में तेज़ी से ह्रास हुआ. वहीं राजद के लोकप्रिय नेता के सलाख़ो के पीछे चले जाने से राजद नेतृत्व विहीन हो गया. नतीजतन राजद का संगठन कमज़ोर होता गया. यही स्थिति हिलसा राजगीर तथा इस्लामपुर क्षेत्रों में कम्यूनिस्टों की रही. समय के साथ कम्युनिस्टों के संगठन के कमज़ोर होने का सीधा फ़ायदा सतारूढ़ गठबंधन एनडीए को मिला. कम्युनिस्ट गठबंधन के ढ़ीले पड़ जाने तथा योग्य नेताओं के अभाव के चलते सतारूढ़ गठबंधन का मार्ग प्रशस्त हुआ. नीतीश के विकास के मुद्दे एवं सुशासन, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में बदलाव लाने में अहम भूमिका निभाई. विकास के मुद्दे ने जाति की रूढ़िवादी सोच को ध्वस्त कर दिया तथा आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रों में समरसता तथा समानता का वातावरण तैयार हुआ. ज़िले में बड़े पैमाने पर होने वाले विकास के कार्यों ने लोगों की मानसिकता बदली. लोग जातीय विचारधारा की सोच से बाहर निकल कर विकास की नए विचारधारा में आ गए. आम लोगों के मानसिक बदलाव ने ज़िले में राजनीति को नई दिशा दी. विगत तीन विधान सभा चुनावों में एनडीए गठबंधन ने जिस प्रकार ज़िले की सभी सीटों पर जीत दर्ज की, इसे इन्हीं बदली परिस्थितियों के संदर्भ में बख़ूबी समझा जा सकता है.

नालंदा में विपक्षी दलों की स्थिति पर नज़र डाली जाए तो ज़िले में विपक्ष की स्थिति विगत चुनावों से लगातार कमज़ोर होती दिख रही है. नालंदा के अलग-अलग क्षेत्रों में राजद एवं कम्यूनिस्टों का शुरूआती दौर में अच्छा प्रभाव देखा गया.

कुमार प्रशांत
feedback@chauthiduniya.com

एजेंडा

बायसी को बाढ़ से बचाएंगे संतोष

पूर्णिया की बायसी विधानसभा में इस बार तेज़तर्रार, मृदुभाषी, भाजपा के युवा नेता संतोष कुशवाहा ने कई दिग्गजों को पटकनी देकर इस अल्पसंख्यक बहुल विधानसभा का इतिहास बदल डाला. मालूम हो कि पूर्णिया ज़िले का बायसी विधानसभा अल्पसंख्यक मुस्लिम बहुल है, जहां मुस्लिमों की जनसंख्या 70 प्रतिशत के करीब है. बायसी विधानसभा के इतिहास में आज़ादी के बाद से अबतक मुस्लिम को छोड़कर अन्य संप्रदाय से कोई भी विधायक नहीं बना था. स्थानीय जनता का उनके संबंध में कहना है कि हिंदुओं के अष्टयाम से लेकर मुस्लिमों के जलसे में वे लगातार भाग लेते रहे हैं. इससे वे सबके अजीज हैं. संतोष कहते हैं कि कि यह जीत बायसी की जनता की जीत है. विगत जनप्रतिनिधियों से बायसी की जनता का मन टूट चुका था और वे निराश हो चुके थे. जनता ने मुझ पर भरोसा जताया. बायसी पूर्णिया का सबसे पिछड़ा इलाक़ा है. पिछले 20 सालों से बायसी में कोई विकास नहीं हुआ है. इस क्षेत्र की मुख्य समस्या बाढ़ है. इस मुद्दे पर मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा और निदान का उपाय निकालूंगा.

पीपा पुल की जगह पक्का पुल : सतीश

राबड़ी देवी को हराकर पहली बार विधानसभा पहुंचे सतीश कुमार का मानना है कि नीतीश कुमार के करिश्माई नेतृत्व के कारण बिहार को देश का नंबर वन राज्य बनने से कोई नहीं रोक सकता. राघोपुर की जनता का आभार जताते हुए सतीश कुमार का कहना है कि कच्ची दरगाह से रूस्तमपुर तक पीपा पुल की जगह पक्का पुल बनवाना मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है. इस काम के लिए वह जी–जान से जुट चुके हैं. कहते हैं कि नीतीश कुमार के आशीर्वाद से राघोपुर की जनता की यह चाहत जरूर पूरी होगी. कटाव की समस्या भी सतीश कुमार की नज़र में है. कहते हैं कि जनता ने जो भरोसा उन पर जताया है, उसे वह हर हाल में पूरा करेंगे.

मुज़फ्फरपुर हासिल करेगा पुराना गौरव : सुरेश शर्मा

विधानसभा तक पहुंचना मुजफ्फरपुर के सुरेष शर्मा के लिए बड़ा ही सुखद अनुभव है. वह बताते हैं कि लगभग दो दशक के संघर्ष के बाद उन्हें कामयाबी मिली है. उनका कहना है कि जनता के आशीर्वाद का क़र्ज़ उतारना मेरी ज़िम्मेदारी है. शहर को साफ़ रखना और बिजली की कि किल्लत को दूर करना मेरी प्राथमिकता होगी. मेरा प्रयास होगा कि ज़िले में बंद पड़े छोटे–बड़े कारखानों से फिर धुंआ निकले. मुजफ्फरपुर–पटना के बीच नई सड़क जल्द से जल्द बनवाने के लिए मैं जी जान लगा दूंगा. अगर सब ठीक रहा है तो यह शहर फिर से अपने पुराने गौरव को हासिल कर लेगा.

–रोशन कुमार

जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा का दंश

संजीव कुमार सिंह

महान दार्शनिक उदयनाचार्य की जन्मस्थली करियन को आज पंचायत का दर्जा मिल चुका है, लेकिन पंचायतीराज के दस वर्षों के कार्यकाल में उदयनाचार्य जैसे विश्व प्रसिद्ध चिंतक एवं दार्शनिक के लिए कोई विशेष कार्य नहीं किया गया. स्थानीय जनप्रतिनिधि की तो और बात है बिहार के चार मुख्यमंत्रियों ने उदयनाचार्य की जन्मस्थली को पर्यटन स्थल का दर्जा दिलाने की घोषणा की थी जो आज तक वास्तविकता में नहीं बदल सकी. पंचायत में ग्रामीण सड़कें, बिजली, नलकूप, स्वास्थ्य एवं शिक्षा की बदहाली पंचायतवासियों को मुंह चिढ़ाती है. शिक्षा के लिए इस पंचायत में एक अदद उच्च विद्यालय तक नहीं है. करियन पंचायत के अंतर्गत शिवनगर, देवनपुर, गायघाट, बरैठा, बलहा, भररिया एवं जोगिया गांव की 12 हज़ार की आबादी निवास करती है. इस पंचवर्षीय कार्यकाल में पारिवारिक सूची में 3182 परिवार के नाम शामिल हैं, जिसमें से 1763 परिवार बीपीएल सूची के अंतर्गत आते हैं. इन परिवारों के लिए बिजली उपलब्ध कराने की घोषणा फ़िलहाल लंबित है. पंचायत स्थित दोनों स्वास्थ्य केंद्र बलहा एवं करियन की भवन जर्जर हो चुकी है. पंचायत की अधिकांश आबादी कृषि पर आधारित जीवन–यापन करती है, इसके बावजूद पंचायत की सरकारी सिंचाई व्यवस्था मृतप्राय है. पंचायत की मूलभूत समस्या में 1000 परिवारों का नाम न तो बीपीएल सूची में है और न ही एपीएल सूची में. इसे एक पंचायत भवन तक नसीब नहीं हो सका है.

शिवाजीनगर प्रखंड

घूरन यादव | अनीता देवी

एनडीए शासनकाल में महिलाओं को मिले पचास प्रतिशत आरक्षण का जीता–जागता इदाहरण बन चुके करियन पंचायत की जनता ने सामान्य सीट से अनीता देवी को मुखिया पद पर बिठाया. इस पंचायत की विशेषता है कि सरपंच के पद पर भी एक सामान्य महिला विभा देवी क़ाबिज़ है. करियन पंचायत की मुखिया कहती है कि यहां दो नवसृजित विद्यालय जोगिया एवं भरड़िया में खोले गये हैं और एक प्राथमिक विद्यालय देवनपुर को मध्य विद्यालय का दर्जा दिलाया गया है. इन विद्यालयों के लिए 12 शिक्षकों की बहाली की गई है. पशु चिकित्सालय एवं आंगनबाड़ी केंद्रों का भवन बनवाया गया है. कबीर अंत्योष्टि योजना के तहत 16 एवं कन्या विवाह योजना के तहत 53 लोगों को क्रमशः 1500 एवं 5000 की राशि मुहैया कराई गई है. पेयजल के लिए 71 चापाकल लगाये गए हैं. सौंदर्यीकरण में 17 सोलर लाइट और करियन गांव में 80,000 की लागत से सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराया गया है. वृद्धा, विधवा एवं विकलांगों को पेंशन योजना के तहत क्रमशः 181, 22 एवं 25 लाभार्थियों को प्रतिमाह 200 रुपये दिये जा रहे हैं. सिंचाई के लिए दो स्टेट बोरिंग एवं 311 लोगों को सामान्य इंदिरा आवास तथा 46 को विशेष इंदिरा आवास मुहैया कराया गया है. पंचायत में पानी टंकी एवं उच्च विद्यालय स्थापित करने का इरादा दोबारा सत्तासीन होने पर पूरा किया जायेगा. वहीं उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी पूर्व मुखिया घूरन यादव विकासों को रुटीन वर्क बताते है. इस पंचायत में कुल 34 पदों के लिए चुनाव होने हैं, जिसमें मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति एवं ज़िला पार्षद के एक–एक पद हैं जबकि ग्राम पंचायत सदस्य के 15 एवं ग्राम कचहरी पंच के 15 पद शामिल हैं.

feedback@chauthiduniya.com

बदहाली में महाकवि की जन्मस्थली

महाकवि आरसी प्रसाद सिंह की जन्मस्थली जहांगीरपुर उत्तर पंचायत आज भी प्रशासनिक एवं जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा का जीता जागता उदाहरण है. कविवर की जन्मस्थली होने के बाद भी पंचायत क्षेत्र में कोई भी ऐसी झलक नहीं दिखती कि जिससे लगे कि यह धरती हिंदी एवं मैथिली साहित्य के महान विद्वान की है. पंचायत क्षेत्र में न तो उनकी प्रतिमा है और ना ही उनकी लिखी रचनाओं को सहेजने के लिए कोई पुस्तकालय. ग्रामीणों ने वर्षों पूर्व उनके पैतृक गांव एरौत का नाम बदलकर आरसीनगर कर दिया लेकिन यह नाम महज गांव तक ही सिमट कर रह गया. सरकारी रजिस्टरों में आज भी इस गांव को लोग एरौत के नाम से ही जानते हैं. लोगों ने उच्च विद्यालय एरौत का नामाकरण भी महाकवि के नाम पर करने का मन बनाया, लेकिन यह मसला भी सरकारी फाइलों में दम तोड़ गया.

पंचायत में आज भी पेयजल, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, जर्जर तटबंध, ग्रामीण सड़कों की बदहाली समेत अन्य कई समस्याएं हैं. पेयजल के लिए ग्रामीण चापाकल एवं कुंए पर पंचायत की दस हज़ार की आबादी निर्भर है. सिंचाई के साधन मृतप्राय हैं. शिक्षा के नाम पर पंचायत में उच्च विद्यालय को उच्चतर माध्यमिक का दर्जा प्राप्त तो हो चुका है पर पढ़ाई प्रारंभ नहीं हो पाई है. बालिका उच्च विद्यालय की मांग वर्षों से जारी है. स्वास्थ्य एवं चिकित्सा व्यवस्था के नाम पर एक उपकेंद्र है जो भाड़े के मकान में चलता है. इसके अलावा पंचायत में बेरोजगारी की समस्या भी ख़ास बनती जा रही है.

रोसड़ा प्रखंड

पंचायती राज व्यवस्था की शुरूआत वर्ष 2001 में होने के साथ ही जहांगीरपुर उत्तर पंचायत के मुखिया पद पर क़ाबिज़ हुए अरुण कुमार सिंह लगातार दूसरे बार भी मुखिया बने. दूसरा कार्यकाल समाप्त होने के साथ ही पंचायत में चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है और मुखिया जी हैट्रिक लगाने की जुगाड़ में अपने किये गये कार्य एवं बचे हुए कार्य को पूरा करने की कसक को लेकर एक बार फिर से चुनाव लड़ने के मूड में हैं. वे जनता के बीच अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं. मुखिया जी का दावा है कि पंचायत में वृद्धों को वृद्धावस्था पेंशन, विकलांगों को विकलांगता पेंशन एवं विधवाओं को लक्ष्मीबाई पेंशन योजना के तहत 200 रुपये प्रति माह दिये जा रहे हैं. इन योजनाओं में तक़रीबन 300 लोगों को लाभांवित किया जा रहा है. बीपीएल सूची के अंतर्गत तक़रीबन सभी परिवारों को इंदिरा आवास के तहत राशि उपलब्ध कराने का दावा करते हुए मुखिया कहते हैं कि अब तक 600 लोगों को इससे लाभांवित किया गया है. कन्या विवाह योजना के तहत 140 लोगों को लाभांवित किया गया है. पंचायत में सौंदर्यीकरण के तहत 40 सोलर लाइट जगह–जगह लगाई गई हैं. पंचायत में पेयजल की व्यवस्था हेतु 70 से अधिक चापाकल हैं. सभी बीपीएल परिवारों को जनवितरण प्रणाली के तहत अनाज उपलब्ध कराया जा रहे हैं. पंचायत भवन का जीर्णोद्धार, विभिन्न सड़कों में पुल–पुलिया का निर्माण, नरेगा के तहत मज़दूरों को काम दिलाना एवं विभिन्न सड़कों पर काम करवाना विद्यालयों में भवन निर्माण कार्य, भूतहा, मुरादपुर एवं एरौत पासवान टोल में नवसृजित विद्यालय की स्थापना के अलावा इन विद्यालयों में शिक्षकों की बहाली इस पंचवर्षीय कार्यकाल की उपलब्धि है. तीसरी बार जनता ने सर आंखों पर बिठाया तो पंचायत में पानी टंकी, अस्पताल, पशु चिकित्सालय एवं विभिन्न ग्रामीण सड़कों का पक्कीकरण का कार्य पूरा करने के साथ ही पंचायत को आदर्श पंचायत का दर्जा दिलाने की कोशिश रहेगी.

वर्ष 2006 में दूसरी बार मुखिया बने अरुण कुमार सिंह पर उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी मोहन जी यादव ने मतों की हेराफेरी कर जीतने का आरोप लगाते हुए न्यायालय में याचिका दायर की गई थी. इसमें मुंसिफ ने पंचायत का चुनाव निरस्त कर दिया और अरुण कुमार सिंह छह महीने तक मुखिया पद से हटे रहे और मुंसिफ के फ़ैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दे डाली. उच्च न्यायालय ने पुन: अरुण कुमार को निर्वाचित घोषित कर दिया. तब से लेकर आज तक वे मुखिया पद पर क़ाबिज़ हैं. प्रखंड की यह इकलौती पंचायत है जहां दो बार निर्वाचन के समय मतगणना हुई और दो बार न्यायालय में मतगणना के बाद अरुण कुमार सिंह मुखिया पद पर बने रहे. पंचायत चुनाव के दौरान कुल 6 पदों के लिए चुनाव होने हैं, जिसमें ज़िला पार्षद, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच, मुखिया, वॉर्ड सदस्य एवं वॉर्ड पंच का पद शामिल है. जहांगीरपुर उत्तर पंचायत की कुल 10 हज़ार की आबादी 30 पदों पर अपने प्रतिनिधि का चुनाव करेगी.

हाथों में हुनर, दिल में ख़्वाब

मीरा सिंह बताती हैं कि संस्था की प्रमुख ईशा सिंह के सहयोग से हम लोग लड़कियों के हाथों में न केवल हुनर देने का काम करते हैं, बल्कि उनमें आत्मविश्वास भरने का काम भी करते हैं. कोशिश होती है कि लड़कियों को इस तरह तैयार किया जाए, ताकि वह जीवन की किसी भी चुनौती का सामना कर सके. उनके दिलों में कुछ बड़ा काम करने का ख़्वाब पैदा किया जाता है, ताकि वह अपने परिवार व जमुई का नाम रोशन कर सकें.

कहते हैं अंधेरा तभी तक रहता है, जब तक कोई दीपक जलाने वाला नहीं होता. जमुई शहर के सामाजिक ताने–बाने में लड़कियों के हाथों में हुनर देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का जो सपना स्वयंसेवी संस्था सहयोग शांति ने देखा था, लगता है वह पूरा होने लगा है. सहयोग शांति के समारोह में जब आत्मविश्वास से लवरेज लड़कियां कैटवॉक के लिए उतरीं तो लगा कि उन्हें अब मंजिल पाने से कोई नहीं रोक सकता. उस समय सहयोग शांति की त्रिमूर्ति इशा सिंह, मीरा सिंह और रंजना सिंह के चेहरे पर उभरे संतोष के भाव यह बयां कर रहे थे कि पिछले छह सालों में जो मेहनत उन्होंने की है वह बर्बाद नहीं जा रही है.

सहयोग शांति कार्यालय में सौंदर्य प्रतियोगिता में 18 प्रतिभागियों के बीच पुरानी बाज़ार की शिखा रानी मिस सहयोग शांति चुनी गईं. नेहा सिंह दूसरे व पूर्णिमा भारती तीसरे स्थान पर रहीं. जज की भूमिका में प्रो. सुचिता उपाध्याय एवं डॉ. रीता उपाध्याय ने बख़ूबी अपना सहयोग दिया.

सहयोग शांति की अध्यक्षा उषा सिंह ने बताया कि संस्था द्वारा वर्ष 2004 से लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें निशुल्क कम्प्यूटर शिक्षा, कढ़ाई, बुनाई और पेंटिंग की शिक्षा दी जा रही है. उन्होंने बताया कि जमुई में गरीब लड़कियों को अपने पैरों पर खड़ा करने के मकसद से ही सहयोग शांति काम कर रही है. बहुत सारी दिक्कतों का सामना करते हुए इस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है. हम लोग चाहते हैं कि लड़कियों के लिए अच्छा काम करने वाले संस्था से जुड़ें. मीरा सिंह ने बताया कि गरीब व लाचार लड़कियां जब संस्था से कुछ सीखकर और अपने पैरों पर खड़े होकर जाती हैं तो दिल को सुकून मिलता है. लगता है कि कोई अच्छा काम हम लोगों के सहयोग से हुआ. मीरा सिंह का मानना है कि अगर जमुई के लोग ग़रीब लड़कियों के सहयोग में आगे आएं तो संस्था को काम करने में आसानी होगी. उन्होंने कहा कि काम में परेशानी तो आती है पर संस्था के सदस्य हर मुश्किल को आसान बनाने की हिम्मत रखते हैं. मीरा सिंह ने बताया कि संस्था की प्रमुख ईशा सिंह के सहयोग से हमलोग लड़कियों के हाथों में न केवल हुनर देने का काम करते हैं बल्कि उनमें आत्मविश्वास भरने का काम भी करते हैं. कोशिश होती है कि लड़कियों को इस तरह तैयार कर दिया जाए ताकि वह जीवन की किसी भी चुनौती का सामना कर सके. उनके दिलों में कुछ बड़ा काम करने का ख्वाब पैदा किया जाता है ताकि वह अपने परिवार व जमुई का नाम रोशन कर सकें.

जमुई की लड़कियों में भी किस कदर आत्म विश्वास जगा है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि 18 प्रतिभागियों ने शहर के नामी–गिरामी हस्तियों के रहते कैटवॉक पर बिल्कुल फिल्मी अंदाज में चलकर अपना जलवा बिखेरा. प्रतिभागियों ने जजों के सवालों का जवाब बहुत ही सटीक तरीके से दिया. मीरा सिंह के प्रयासों से जमुई में रंग आने शुरू हो गए हैं. कार्यक्रम के दौरान ललित कला अकादमी की छात्रा प्रिया सिंह, प्रिया गोयल, कोमल सिंह, स्मृति एवं अंशिका, खुशी, प्राणजाल, कशिश, ईशा आदि ने नृत्य एवं गायन से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया. नृत्य–संगीत कार्यक्रम का निर्देशन संगीत शिक्षिका आभा सिंह ने किया. कुल मिलाकर इस तरह के कार्यक्रमों से एक नई आशा पैदा हो रही है.

चंदा सिंह
feedback@chauthiduniya.com

झारखंड नवनिर्माण की मुहिम में जुटी है सरकार: हेमंत

नवल किशोर सिंह

झारखंड के उपमुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी ज़िम्मेवारियों के निर्वहन में गंभीरता से लगे हैं. वे झारखंड के बाधित विकास को गति प्रदान करने की मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की मुहिम में कदमताल करते दिख रहे हैं. सूबे की अर्थव्यवस्था की मज़बूती के लिए, ख़ासकर ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर सृजित करने पर बल दे रहे हैं. उनका मानना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना विकसित होने से कृषि क्षेत्र का भी विकास होगा. इससे रोज़गार के नए रास्ते खुलेंगे. इसीलिये वह ग्रामीण सड़कों के विकास, विद्युतीकरण, शिक्षा के विकास, स्वास्थ्य सुविधा बेहतर करने के प्रयास में लगे हैं. उनके मुताबिक़ लोगों को अपने ही इलाक़े में रोज़गार मिले तभी पलायन रुकेगा. नक्सलवाद पर भी अंकुश लगेगा. हेमंत सोरेन ने चौथी दुनिया से बात करते हुए यह विचार व्यक्त किए. उन्होंने कहा कि झारखंड खनिज संपदा के मामले में देश का सबसे धनी राज्य होने के बावजूद पिछड़ा हुआ है. इसका एकमात्र कारण आधारभूत संरचना का अभाव है. कहते हैं कि झारखंड में एनडीए के घटक दल इतनी ही मजबूती के साथ काम करेंगे जितनी मज़बूती बिहार में दिखी है और अगले चुनाव में बिहार की तर्ज पर प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की वापसी होगी. आगे कहते हैं कि घटक दलों के बीच किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है. कांग्रेस कहती है कि यह बेमेल गठबंधन है, लेकिन समय बताएगा कि यह गठबंधन बिहार में भाजपा–जदयू गठबंधन की तरह एक मिसाल कायम करेगा और अगले चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ हमारी पुनर्वापसी होगी.

सोरेन ने कहा कि मुंडा सरकार ने सत्ता में आते ही पंचायत चुनाव को संपन्न कराने की चुनौती स्वीकार की और मतदाता जितने उत्साहित होकर भारी संख्या में मतदान कर रहे हैं, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि यह जनता की आकांक्षा थी जिसे हमने पूरा कर दिखाया. अब ग्रामीण क्षेत्रों की जनता अपने विकास का रास्ता स्वयं तय करेगी. इसे विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में भागीदारी का अवसर मिलेगा. वर्षों से अपने अधिकारों से वंचित ग्रामीणों को उनके अधिकार दिलाने का काम हमारी सरकार ने किया है.

नक्सली हमारे ही समाज के भटके हुए लोग हैं. उन्हें मुख्यधारा में लाकर नए झारखंड के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया जा रहा है. इसका सकारात्मक परिणाम भी मिल रहा है. विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिये सभी विभागों की समीक्षा की जा रही है और आवश्यक निर्देश दिये जा रहे हैं. योजनामद की अधिकतम राशि ख़र्च किये जाने का निर्देश भी दिया गया है. हमारी कोशिश है कि जनता को शत–प्रतिशत लाभ मिले और विकास की राशि सरेंडर न करनी पड़े. उन्होंने बिहार चुनाव में झामुमो का खाता खुलने पर बिहारवासियों को बधाई दी और कहा कि अब झामुमो बिहार में भी अपने संगठन का विस्तार करेगा और जनता की आकांक्षाओं को पूरी करने का प्रयास करेगा.

feedback@chauthiduniya.com

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. DELHIN/2009/30467

टूटी सड़क और जाम की समस्या को लेकर कुछ दिनों पहले गुलाबबाग के लोगों ने सड़क जाम किया और बाज़ार बंद किया.

गुलाबबाग मंडी

बीमार और ख़स्ताहाल

नीरज कुमार सिंह

बिहार की सबसे बड़ी और सबसे अधिक राजस्व देने वाली गुलाबबाग मंडी नीतीश के शासन में भी बदइंतजामी की मिसाल बनी हुई है. हालत यह है कि लोग गुलाबबाग मंडी जाने के नाम पर नाक-भौंह सिकोड़ने लगते हैं. बिहार सरकार को राजस्व देने के मामले में अव्वल रहने के बावजूद यह मंडी विकास के मामले में काफ़ी पिछड़ गई है. टूटी सड़कें, जाम, धूल, सड़कों और नालों के अभाव के साथ-साथ अतिक्रमण यहां की पहचान बन गया है. ऐसा नहीं है कि गुलाबबाग के स्थानीय निवासियों व व्यवसायियों ने प्रशासन से लेकर सरकार तक इस संबंध में गुहार नहीं लगाई है. टूटी सड़क व जाम की समस्या को लेकर विगत दिनों गुलाबबाग के लोगों ने बाज़ार बंद किया और सड़क जाम किया. उस समय प्रशासन के आश्वासन पर स्थानीय लोगों ने आंदोलन वापस ले लिया, लेकिन समस्या अभी भी जस की तस है. ऐसा नहीं है कि जाम की समस्या का हल नहीं हो सकती. दरअसल जाम की समस्या यहां के धर्मकांटा व बालू गिट्टी के कारोबारियों की वजह से पैदा हुई है.

गुलाबबाग की मुख्य सड़क पर 5 धर्मकांटे हैं, जिसमें से दो धर्मकांटों पर ट्रक-ट्रैक्टर की काफ़ी भीड़ इकट्ठा होती है. इसमें से एक अपना धर्मकांटा के बारे में स्थानीय लोगों का कहना है कि यह धर्मकांटा कुछ गल्ला पाट व्यवसायियों के सहयोग से खोला गया है, जिसमें मंडी अनाज व पाट बेचने आए किसानों की मापतौल में घालमेल किया जाता है. किसानों से माल ख़रीदने वाले व्यवसायियों की शर्त होती है कि माल की मापतौल वाहन सहित अपना धर्मकांटा पर ही की जाएगी. इससे वाहनों का लंबी कतार लग जाती है. इस धर्मकांटे का निर्माण मुख्य उच्चपथ की ज़मीन का अतिक्रमण करके किया गया है. इस धर्मकांटे में वजन के बाद ही माल कृषि उत्पादन बाज़ार समिति के प्रांगण व गोदामों में पहुंचता है. यही स्थिति कृषि बाज़ार समिति प्रांगण के सामने वाले धर्मकांटे की है. इसके अलावा गिट्टी और बालू के कारोबारियों ने मुख्य सड़क की भूमि का अतिक्रमण करके डिपो खोल लिया है. इनकी गिट्टी, बालू मुख्य सड़क पर जेसीबी लगाकर ट्रक में भरी जाती है और इससे उड़ने वाली धूल से गुलाबबाग मंडीवासी असमय ही श्वास, फेफड़े की कई बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं. ख़ुश्कीबाग कप्तान पुल से लेकर गुलाबबाग जीरो माईल तक मुख्य सड़क का हाल यह है कि इस पर वाहन तो क्या आदमी का पैदल चलना भी दुर्लभ है. जबकि इस सड़क का निर्माण सीपीडब्ल्यूडी की तरफ से एक निजी कार्यकारी ऐजेंसी की तरफ़ से कराया गया है. इसके बावजूद यह सड़क निर्माण के एक साल के अंदर ही टूटने लगी. इस संबंध में स्थानीय लोगों का कहना है कि सुशासन की सरकार में राष्ट्रीय उच्च पथ 31 के निर्माण में काफ़ी लूट-खसौट हुई है. इसके बाद विभाग ने सड़क की मरम्मत का आदेश दिया लेकिन मरम्मत करने वाली एजेंसी भी बेडमिसाली सड़क पर डालकर फरार हो गई. इसी बेडमिसाली की धूल इस कदर उड़ती है कि दिन में ही सड़क पर अंधेरा छा जाता है. सड़क, धूल, जाम और धर्मकांटें की समस्याओं को लेकर गुलाबबाग वासियों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लेकर ज़िला प्रशासन तक कई बार गुहार लगाई. उन्हें अश्वासन मिला लेकिन कोई ठोस पहल होती नहीं दिखी.

feedback@chauthiduniya.com

YOU'RE INVITED
10% Discount Diamond Jewellery (M.R.P.)
100% Discount Hallmark Gold Jewellery (Making Charges)
INVITES YOU FOR A
Exhibition CUM Sale
OF Diamond AND
Gold
JEWELLERY
Prop. : Sanjeet Soni
Exclusive Show room
D'damas
Celebrate Always
-: Venue :-
VINOD SONY JEWELLERY
Damrulal Durga Ashtan, Deo Market, Mungeriganj, Begusarai
Mob : 9031113944, 9835258815, Ph : 06243-240664
Who ever will bring this advertisement cutting will get a definite gift of 10-25% with the purchase of the jewellery
Very soon we will be coming up with Silver and gold wholes Jewellery

EMP एकाउंटिंग प्रोग्राम

जहाँ रोजगार पाने के सपने होते हैं साकार...

कम्प्युटर साक्षारता ही नहीं बल्कि जॉब के कई दरवाजे खोलते है

माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के प्रोग्राम

दुनियाँ की अग्रगणी कम्पनि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोग्राम बेरोजगारों हेतु जॉब पाने का सबसे असान जरिया है। जहाँ बेरोजगार युवक-युवतियाँ आई०टी० के क्षेत्र में रोजगार पाने हेतु कम्प्युटर शिक्षा से जूड़े कोई ना कोई कोर्स का चयन करते हैं। वहीं समय के अभाव में कामकाजी युवक युवतियाँ, जों पहले से या तो कोइ जॉब में कार्यरत हैं या बैंकिंग, पी०ओ०, रेलवे, कलर्क या अन्य प्रतियोगिता परिक्षाओं एवं उससे जुड़े जॅब में कम्प्युटर शिक्षा की अनिर्वायता को देखते हुए या अन्य जॅब मे कम्प्युटर से संबंधित अवारनेस लाने हेतु, कम समय के मद्देनजर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कोर्स का चुनाव करना लाजमी समझते है। वहीं अन्य बेरोजगार जॅब हेतु कम्प्युटर के बहुत कुछ कोर्स करने हेतु अगर सक्षम नहीं है, तो कुछ कोर्स करना ही पसंद करते हो तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कम लागत में कम्प्युटर से संबंधित कोर्स हेतु माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेस्लीस्ट बनकर जॉब पाने का अवसर प्राप्त कर रहें हैं। और आए दिन कोई भी शिक्षित व्यक्ति हेतू घर से बाहर तक कम्प्युटर के वगैर उनकी दिनचार्या अधुरी रह जाती है। वो भी अगर कम्प्युटर के क्षेत्र में साक्षर बनकर अपने रोजमर्रे की दिनचार्या को सुदृढ़ बनाना चाहते हैं तो उन्हें भी तो उन्हें कम्प्युटर के क्षेत्र मे असानी से साक्षरता हासिल करने के लिए कोई ना कोई उपयुक्त कोर्स की जरूरत पड़ती हैं। उस परिस्थिति मे भला माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ट्रेनिंग से उपयुक्त ट्रेनिंग आखिर क्या हो सकती है और आप माइक्रोसॉफ्ट स्पेस्लीस्ट का सटिफिकेट प्राप्त करके कम्प्युटर शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहचान बनाकर रोजमर्रे के कार्यो हेतु सक्षम हो जाते है। और आप इस सर्टिफिकेट को अपने देश में ही नहीं विदेशो तक जगह-जगह जरूरत के अनुसार व्यवहार में ला सकते है। मालुम हो कि माईक्रोसॉफ्ट दुनियाँ भर की जानी मानी सॉफ्टवेयर की नं०1 प्रमाणित कंपनी है और आप इससे जूड़े माईक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेसलिष्ट की ट्रेनिंग लेकर उसका सर्टिफिकेट हासिल करते है, तो इस ब्रांडेड सर्टिफिकेट की विश्वस्तरीय पहचान आपकी योग्यता के उपर किसी प्रकार की प्रश्नचिन्ह लगने नहीं देती है। दुनियाँ की यह फेमस कंपनी कई देशों में अपना अर्थोराइज टेस्टींग सेंटर की जिम्मेवारी कई कम्प्युटर शिक्षा के क्षेत्र मे उत्कृष्ट संस्थानों को दिया है। यहाँ के प्रदेशो मे अर्थोराइज ट्रेनिंग सेंटरो में एलाईड इंडस्ट्रियल डाटा कम्प्युटर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सरीखे संस्थान इसकी भली भाँति ट्रेनिंग देने का काम कर रहीं है। हेल्पलाइन : 9334100961

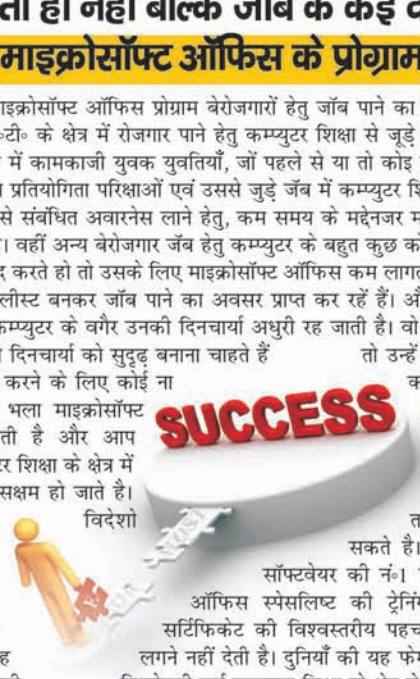

आलेख: अपराजिता प्रिया

सुचना तकनीक से जूड़ा हुआ फिनांस एवं बैंक मैनेजमेंट पर आधारित एकाउंटिंग इम्फॉर्मेसन सिस्टम का विश्वस्तरीय कोर्स EMP है। एकाउंटिंग के सभी पैकेज पर कार्य करने की दक्षता आपको EMP एकाउंटिंग कोर्स के तहत मिलती है इसके तहत कमर्सियल मार्केट पर आधारित एकाउंटिंग के किसी खास कार्यो में दक्षता रखने वाली सॉफ्टवेयर (पैकेज) हो, अथवा कार्पोरेट सेक्टर की जरूरत पर आधारित एकांउटिंग बिजनेस सह टैक्स से संबंधित सम्पूर्ण कार्यो को निष्पादित करने वाली सॉफ्टवेयर हो, इन तमाम कार्यो हेतु EMP एकाउंटिंग कोर्स को करके आप इस क्षेत्र में सम्पूर्ण दक्षता हासिल कर सकते है। इलेक्टॉनिक मेनुअल एवं प्रोग्राम एकाउंटिंग (पैकेज) की परिभाषा को परिभाषित करने वाली EMP एकाउंटिंग कोर्स की मांग देश में लाखो की तदाद में है। इन प्रदेशो में इसकी उपयुक्त ट्रेनिंग देने वाली संस्थान काफी कम है। इस कोर्स से जूड़े मात्र एकाउंटिंग की कुछ कमर्सियल पैकेज जैसे (इजी, विजी, टैली, फैक्ट, इआरपी) सरीखे नाम को आप भले जानते होंगे इन सरीखे पैकेजों पर ट्रेनिंग लेने वालों की संख्या इस पर अधारित जॉब की मांग की तुलना में हजारो गुणा ज्यादा है। यही वजह है कि अब आई०टी० से जुड़े सिर्फ एकाउंटिंग पैकेज पर आधारित ट्रेनिंग लेने वक्त सतर्कता नहीं बरतने वाले को खासे बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। वहीं एकाउंटिंग एवं टैक्स, इम्फॉर्मेसन सिस्टम के सम्पूर्ण ट्रेनिंग के रूप में EMP एकाउंटिंग प्रोग्राम का कोर्स करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या से काफी कम (90% कम) है। यहीं कारण है कि EMP के अंशत: अथवा पूर्णत: ट्रेड सबो को छोटे से छोटे बड़े से बड़े जॉब पाने का मौका उनके ट्रेनिंग के दौरान भी मिल जाती है। EMP कोर्स करने वाले अभ्यर्थी समान्य कंपनियों से लेकर कॉर्पोरेट सेक्टर की विदेशों तक फैली हुई कंपनीयों मे जॉब हासिल करने मे सक्षम होते है। इस कोर्स को करनेवाला अभ्यर्थी एकाउंट्स मैनेजर, ई-ऑडिटर, एकाउंट्स एनालिष्ट, टैक्स कंसल्टेंटस, सॉफ्टवेयर, इंडस्ट्रीज अथवा अन्य कंपनियों के एकाउंट्स एडभाइजर के जॉब में कार्यरत तो हो ही रहे है, साथ ही CA को माने तो उनके 90% वर्क लोड को EMP एकाउंटेंट को हलका करने का काम बखुबी से निभा रहे है। मालूम हो कि बेहतर कैरियर की शुरूआत करने हेतु EMP कोर्स से जुड़ने वाले अभ्यार्थि सिर्फ कॉमर्स, संकाय के ही नहीं होते है बल्कि कला एवं विज्ञान के भी इस कोर्स को करके अपने कैरियर को सवारने का काम कर रहे है। इस कोर्स को करने हेतु कोई उम्र सीमा की बंदिश नहीं रहने के कारण मायुस एवं हातास बेरोजगार भी इस कोर्स को आजमा कर रोजगार के अवशर प्राप्त कर रहे है। मालुम हो कि प्राइवेट कंपनियाँ खास करके अपने एकाउंटिंग जॉब से संबंधित पदाधिकारी हेतु उनके ज्यादा उम्र को नजरअंदाज करते है, क्योंकि कंपनी के एकाउंटिंग कार्य संबंधित गोपनीयता को उम्रदराज एकाउंटेंट बरकरार रखने मे जितने सक्षम होते है उतने युवा नहीं। मालुम हो की कोई भी विजनेस मे एकाउंटेन्ट की गोपनीयता ही उसकी विश्वसनीयता को बढ़ाने का काम करती है, जो बेहतर प्रमोशन हेतु कारगर शाबित होती है। EMP कोर्स से ट्रेंड अभ्यार्थि को जॉब के लिए ट्रेनिंग के उपरान्त इंतजार करने की जरूरत अब तक नहीं पड़ी है। अपितु आप इस कोर्स से जुड़ने वाले को ट्रेनिंग के दौरान ही रोजगार पाने के अवसर प्राप्त होने के उदाहरण देखने का मिलते रहेगा।

इस कोर्स को करने हेतु योग्यता की बात की जाए तो इंटर, ग्रेजुएट सहित अन्य क्षेत्रों के पढ़े लिखे बेरोजगार भी इस कोर्स को आजमा कर जॉब के अवशर प्राप्त कर रहे है। नेस्कॉम के सर्वे के मुताबिक दुनियाँ में 50 लाख से भी ज्यादा आई० टी० प्रोफेसनल की जरूरत है, यानि उसमे से 7,50,000 ट्रेंड अभ्यार्थि भारतीय होगें। जो देश-विदेश तक की माँगों की पूर्ति हेतु व्यवहार में लाए जाऐगें। मालुम हो कि एकाउंटिंग इम्फॉर्मेसन सिस्टम कोर्स EMP का देश-विदेश हेतु जो मांग है, उसके अनुपात मे 5% लोग भी यहां ट्रेनिंग नहीं ले पाऐ हैं। कहा जाए की अपने देश के भीतर बिहार-झारखंड सरीखे विभिन्न प्रदेशों मे इसकी माँग और पूर्ति के बीच की दूरी ज्यादा है यानी मांग ज्यादा है पूर्ति कम है तो ऐसे में जॉब ढुढ़ने का प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसे में विदेशों में इसकी पूर्ति कहाँ से संभव है। यानि की EMP कोर्स को करने वाले के उपर बेरोजगारी की छाया पड़ने कि दूर-दूर तक कोई संभावना नहीं दिखती। आप बेफिक्र होकर इस कोर्स को अपनाऐ जो काफी कम समय मे समान्य योग्यता रखते हुए भी आपको असानी से ट्रेनिंग पाने का अवशर देगी। इस भूमंडलीयकरण के दौड़ में आई० टी० से जुड़ा एकाउंटिंग इम्फॉर्मेसन सिस्टम का फिनांस एवं बैंक मैनेजमेंट पर अधारित कोर्स EMP आपके उज्जवल भविष्य का निर्माण करेगी। इसमे रोजगार पानेवाले अभ्यार्थि अगर कमर्सियल एकाउंटिंग विजनेस पैकेज को व्यवहार में लानेवाली कम्पनी में जॉब पाते है तो उन्हे दस हजार से पच्चीस हजार मासिक सैलरी का जॉब मिलता है, अगर कॉरपोरेट सेक्टर या मिडियम कॉरपोरेट या बैंकिगं सेक्टर के जॉब में जाते है तो बीस हजार से साठ हजार महीने का जॉब मिलती है। इस कोर्स को करने वालों की मांग बाजार मे इसलिए बुम पर है कि इस कोर्स का ट्रेंड अभ्यार्थि खासकर CA के उपर एकाउंटिंग कार्यो के बढ़ते बोझ को 95% हल्का करने का काम बखुबी से कर रहा है। EMP कोर्स उच्चस्तरीय जॉब के साथ प्रतिष्ठित जॉब हेतु कारगर साबित हुई है। कम समय में, कम खर्च पर, बेरोजगार को इस कोर्स से जुड़ते ही जॉब पाने का जो अवसर मिल रहा है यह IT के दूसरे कोर्स के सामने चुनौती-पूर्ण माहौल खड़ा किया है। आप इसे आजमाकर अपने कैरियर की बुलंदियों पर पहूँचकर रोजगार के सपने साकार करें।

कोर्स में छिपा है करिश्मा

एकाउंटिंग कोर्स ईएमपी के क्षेत्र में देश के कुछ चुनिंदे संस्थान के पता एवं फोन नंबर.

1. एलाइड कम्प्यूटर एकाउंटिंग सेन्टर, पटना
   603, अशियाना टावर, एक्जीविशन रोड, पटना फोन नं.- 0612-3245469, 9334100961
2. एकेडमी ऑफ कम्प्यूटर एकाउंट्स सेक्टर-34, चंडीगड़
3. फाईनेशिंयल एण्ड मैनेजमन्ट सेन्टर, गुडगाँव (हरियाणा)
4. इंस्टीटयूट आफ कम्प्यूटर एण्ड फाइनेंस एक्जीक्यूटिव, करोल बाग, मेट्रो स्टेशन, नई दिल्ली

ALLIED COMPUTER
शीघ्र मिलें
ISO प्रमाणित, एवं राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित, 20 वर्ष पुरानी देश की पहली एकाउंटिंग संस्थान
603, अशियाना टावर, एक्जीविशन रोड, पटना Ph. : 9334100961, 9386546721 Website : alliedcomputer.org
देश में व्याप्त महंगाई कि मार झेल रहे गरीब बेरोजगार, अच्छे संस्थान मे दाखिला लेने हेतू शिक्षा लोन अथवा बैंक लोन के चक्कर में अच्छे संस्थान के साथ उपयुक्त कोर्स करने से रह जाते है दूर, और जॉब पाने से हो जाते है वंचित। उनके लिए देश मे एकमात्र, 20 वर्षो से फेमस, संस्थान एलाईड कम्प्युटर ने फिलहाल जेनरल गरीब परिवार सहित SC/ST/OBC/ अल्पसंख्यक एवं छात्राओं हेतू EMP+ कोर्स करने का रास्ता कर दिया असान, अब यहां के कुल फीस में 50 हजार तक करायें माफ, यानी प्रवेश हेतू मात्र 30% ही दें। साथ ही निःशुल्क कोर्स के तहत पायें। DCA +DTP+Hardware नेटर्वकिंग +Spoken+Tally, सहित कुछ अन्य कोर्स। साथ ही ट्रेनिंग के दौरान पार्ट टाईम जॉब सुविधा भी उपलब्ध है।
योग्यता +2/ इन्टर, ग्रेजुएट (कला, विज्ञान या वाणिज्य) अन्य बेरोजगार/मैट्रिक
बेरोजगारों हेतू सरकारी एवं प्राईवेट जॉब का सरकार ने भी खोल दिया पिटारा
अब होने वाली सभी नियोजन हेतू आपको कमर कस के शीघ्र हो जाना होगा तैयार, क्योंकि कम्प्युटर की उपयुक्त कोर्स के वगैर आप हर बार नियोजन का करते रह जायेगें इंतजार। तब वो आपकी भूल होगी, जब आप ऐसे में सरकार को ठहरायेंगें जिम्मेवार।